

# Haryana Vidhan Sabha

## Debates

11th February 1969

(Evening Sitting)

Vol. 1—No. II

OFFICIAL REPORT

### CONTENTS

Tuesday, the 11th February, 1969

	Page
General Discussion on the Budget	
(contd)	(11)1
Extension of Time of the Sitting	(11)43
General Discussion on the Budget	(11)44-53
(Resumption) (Concl'd)	

## HARYANA VIDHAN SABHA

Tuesday, the 11th February, 1969

(Evening Sitting)

The Vidhan Sabha met in the Hall of the Haryana Vidhan Sabha, Vidhan Bhawan, Sector-1, Chandigarh, at 2.30 P.M. of the Clock. Mr. Speaker (Brig. Ran Singh) in the Chair.

### GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET

**Mr. Speaker** : Hon. Members, we now start general discussion, on the Budget for the year 1969-70.

श्रीमती प्रसन्नी देवी (इन्दरी) : स्पीकर साहिब, पिछली सरकार के पिछले टाईम पर अगर नजर दौड़ाएं तो पता चलता है कि इस थोड़े से अर्से के अन्दर सरकार ने हर काम में बड़ी तेजी के साथ कदम उठाए हैं । हरियाणा प्रांत में दो किस्म के इलाके हैं एक वह इलाका है जहां पर वर्षा नहीं होती, सूखा पड़ता है । दूसरा वह इलाका है जहां वर्षा इतनी होती है कि फलडूज आते हैं । सूखा पड़ने से खेती बाड़ी नहीं होती, परिणाम यह होता है कि वहां पर अकाल पड़ता है कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर फलडूज आते हैं, फसल बरबाद होती है इसलिए हरियाणा में दोनों किसम के इलाके हैं जिनका सरकार ने इलाज करना है । अगर सरकार इन दोनों समस्याओं का इलाज कर ले तो हरियाणा हिन्दुस्तान में नम्बर एक पर आ सकता है क्योंकि यहां की जमीन बड़ी उपजाऊ

हे, किसान भी मेहनती है और जलवायु भी अच्छा है । मगर किसान को ट्रैक्टर वगैरा के अच्छे साधन मुहैया किये जायें तो हरियाणा प्रान्त सबसे अच्छा हो जायेगा । छोटे किसानों को बगैर सूद के कर्जा, ट्रैक्टर, खाद और पानी के साधन टाईम के मुताबिक दिये जायें तो में समझती हूं हिन्दुस्तान की अनाज की समस्या को दूर करने में हरियाणा प्रान्त सबसे अधिक हिस्सा डाल सकता है । जिन इलाकों में सूखा पड़ा हुआ है, नहरों का पानी नहीं है वहां पर बिजली पहुंचा कर ट्यूब-वैल्ज कामयाब हो सकते हैं, सरकारी तौर पर जमींदारों को पानी निकाल कर दिया जा सकता है । जहां पर पानी अच्छा मिलता है वहां पर सरकार किसी स्पैशल स्कीम का इन्तजाम करे । बहुतसे इलाके नदी के साथ साथ है जहां पर ड्रेनें बहुत तादाद में हैं वहां पर पानी बहुत तादाद में आता है उस पानी को रोके, चाहे यू० पी० गवर्नमेंट से समझौता करना पड़े, चाहे कोई बांध बान्ध जाये, कुछ भी करना पड़े, लेकिन उस पानी को जरूर रोका जाना चाहिए क्योंकि इससे हरियाणा की फसल को बहुत नुक्सान पहुंचता है । जहां पर ड्रेनें निकल सकती हैं वहां पर ड्रेनों के जरिये से पानी बाहर निकाला जा सकता है । कई नहरों में साईफन लगाकर पानी बाहर निकाला जा सकता है । मेरे अपने इलाके में जब जमुना में फ्लड आता है तो फ्लड का पानी चार चार महीने तक खेतों में भरा रहता है । उस इलाके का पानी बहुत मीठा है, अगर बाढ का पानी नुक्सान न करे तो उस जमीन पर ट्यूबवैल्ज लगाये जा सकते हैं और खेती के लिहाज से बहुत अच्छा इलाका बन सकता है ।

इसके इलावा सरकार ने बिजली के बारे में जितने अच्छे कदम उठाये हैं, उसकी जितनी सराहना की जाये उतनी थोड़ी है क्योंकि जितना काम हरियाणा में पिछले तीस साल के अरसे में हुआ था उतना इस सरकार ने थोड़े से अर्से में कर के दिखा दिया । इन्होंने 30 हजार ट्यूबवैल्वेज मार्च तक त्नगाने का फैसला किया है और अगले साल क बजट में 41 हजार के करीब नये ट्यूबवैल्वेज को बिजली के कुनैक्शन देने का फैसला किया है । यह बहुत अच्छा कदम है । अगर सारे बजट में से दूसरे डिपार्टमेंट्स के हिस्से को निकाल दिया जाये तो आधा हिस्सा बिजली डिपार्टमेंट क हिस्से आता है । इतना रुपया इसलिए रखा है कि बिजली की डिवाैल्पमेंट से सारे हरियाणा की डिवाैल्पमेंट हो जाती है । ट्यूबवैल्वेज लगने से किसान अपनी मर्जी से खेती कौ पानी दे सकता है, नहर के पानी की तरह इन्तजार नहीं करना पड़ता । जमुना नगर और करनाल के इलाके में जहां सरकारी ट्यूववैल्वेज है, पिछली सरकार यानी राव बीरेन्द्र सिंह की सरकार ने ट्यूबवैल्वेज के रेट्स 25 पैसे प्रति यूनिट कर दिया था । 25 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से नहर का पानी तकरीबन पांच गुना अधिक पड़ता है । मैं समझती हूं कि एक साधारण किसान को इतना पैसा जुटाना बड़ा मुश्किल है, इस तरह किसानों के साथ बड़ी ज्यादती है । इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि दस एकड़ तक जमीन रखने वाले किसान से मालिया बिल्कुल न लिया जाए । वास्तव में देखा जाये तो किसान दूसरे तबकों की निसबत ज्यादा मेहनत करता है । अगर दफतर के बाबुओं की तरह अपना स्टैन्डर्ड रखना चाहे तो मैं

समझती हूँ कि किसान का पेट भर कर का गुजारा भी नहीं हो सकता । किसान न अपना स्टैंडर्ड रख सकता है, न अच्छा कपड़ा पहने सकता है और न दूसरे कामों पर पैसा खर्च कर सकता है ।

इसके इलावा, स्पीकर साहिब, सड़कों के लिए, सरकार ने काफी पैसा रखा है । सड़कों के लिहाज से भी हरियाणा अपने पड़ोसी प्रान्त पंजाब से काफी पिछड़ा हुआ है । सरकार ने सड़कों के लिए काफी काम किया है लेकिन फिर भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 15-15, 20-20 मील तक कोई सड़क नहीं है । ऐसे इलाकों की तरफ सरकार को खास ध्यान देना चाहिए । स्पीकर साहिब, आपके जरिए, मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जो इलाका किसी भी मामले में, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे पानी का हो, चाहे बिजली का हो सरकार पिछड़ा हुआ समझे, उन इलाकों के लिए का कमेटी बनाई जानी चाहिए जो सारे हरियाणा में श्रमण करके पता लगाये कि कौन सा इलाका पिछड़ा हुआ है ताकि उन पिछड़े हुए इलाकों को दूसरे अच्छे इलाकों के बराबर किया जा सके ।

हमारे इलाके में बहुत सी जगहों पर पीने के पानी की बड़ी समस्या है । कई जगह पर कुएं का पानी बहुत गहरा है और कुएं खोदने में जनता को बहुत दिक्कत होती है, सरकार को ऐसे इलाकों में पीने के पानी का इन्तजाम करना बहुत जरूरी है ।

स्पीकर साहिब, हमारे समाज का सब से बड़ा हिस्सा हरिजन और दूसरी पिछड़ी हुई जातियों का है जिनको हम अभी तक आगे नहीं ले जा पाये हैं जितना ले जाना चाहिए । यह मैं मानती हूँ कि सरकार ने बजट में, पिछले सालों की अपेक्षा इस साल काफी रुपया रखा है । लेकिन फिर भी, स्पीकर साहिब, मैं आपके जरिये सरकार से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जो 25 लाख रुपये की रकम हरिजनों को कम सूद प्र कर्जे देने के लिए रखी यह बिना सूद से दिया जाना चाहिए । अगर वगैर ब्याज से लोन दिया जाए तो हरिजन कुछ न कुछ तरक्की कर सकते हैं क्योंकि यह एक ऐसा वर्ग है जिसके पास जमीन नहीं होती । इनके इलावा जो दूसरी बैंकवर्ड क्लासिज हैं उनका भी यही हाल है । इन लोगों को ऊपर उठाने का यही एक तरीका हो सकता है कि जितना भी पैसा दिया जाये वही बगैर सूद से दिया जाए । इसके इलावा पंचायतों के पास सरप्लस जमीन होती है उसमें हरिजनों के लिए जो हिस्सा रखा हुआ है उसमें बैंकवड क्लासिज भी शामिल है । मेरा सरकार से निवेदन है मेरा हरिजनों और दूसरी पिछड़ी हुई जातियों का हिस्सा अलग अलग फिक्स कर देना चाहिए ताकि हर वर्ग को पूरा पूरा हिस्सा मिले ।

अब मैं शिक्षा के बारे में थोड़ा सा कहना चाहती हूँ । मैं मानती हूँ कि सरकार ने शिक्षा के बारे में बड़े अच्छे कदम उठाए । पिछले दिनों सरकार ने कुछ स्कूल अपग्रेड भी किये और एक साल के लिये दोबारा फीस भी लगी थी । जहाँ कहीं भी मैं जाती थी लोग

मुझ से शिकायत करते थे कि बच्चों पर फीस नहीं लगानी चाहिए । खास तौर से गरीब लोग बहुत परेशान थे । गरीब आदमी तो विना फीस के नहीं बड़ी मुश्किल से बच्चों को पढ़ा पाता है, फीस लगने पर तो वे बिल्कुल नहीं पढ़ा पाएंगे । इसलिये फिस माफ करके सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है । स्कूल भी पिछले साल काफी अपग्रेड किये और इस साल भी काफी रुपया रखा है ।

एक चीज मैं टीचर्ज के बारे में कहना चाहती हूं । टीचर्ज के एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में तबादले करने से उन्हें रिहायश की दिक्कत पेश आ रही है । इन के लिये सरकार पंचायतों के जरिये कोई स्कीम दना दे यानी किराये पर मकान बना दे. और उनकी तनख्वाह के मुताबिक कुछ परसैन्टेज जितनी ठीक समझे, काटते रहें तो टीचरों की यह दिक्कत बहुत हद तक दूर हो सकती है । इस से स्पीकर, साहिब, पढाई में भी काफी सुधार है सकेगा क्योंकि जब अध्यापकों को दिक्कत नहीं होगी तो वे पढाई की तरफ पूरा ध्यान दे सकेंगे । इसलिये, मेरी सरकार से यही प्रार्थना है कि अगर यह उनके लिये दो दो कमरों वाले छोटे छीटें सैट भी बना दें तो वह एक अच्छा कदम होगा ।

इसके इलावा, स्पीकर साहिब, मै नशाबन्दी के बारे में थोडा सा अर्ज करना चाहती हूं । इसके बारे में सरकार ने कहा है कि वह सोच रही है । स्पीकर साहिब, यह तो ठीक है कि नशाबन्दी करने से सरकार को काफी घाटा पड़ेगा लेकिन इससे लोगों को जो

नुक्सान हो रहा है वह सरकार को पड़ने वाले घाटे से कहीं ज्यादा अहमियत रखता है । आज जितना सरकार को फायदा होता है उससे कई गुना ज्यादा नुक्सान इस शराब की वजह से हो जाता है क्योंकि अक्सर गरीब आदमी इसमें पैसा फूंकते हैं । यह पैसा भी तो हमारे देश और समाज का ही है । अगर शराब को कानूनी तौर से बन्द कर दे तो काफी बचत हो सकती है । जो गरीब आदमी या मजदूर 5-6 रुपये दिन में कमाने के बाद शाम को 3-4 रुपये शराब पर खर्च कर देते हैं वे खर्च नहीं होंगे बल्कि उनका प्रयोग दूसरी उपयोगी चीजें खरीदने तथा बच्चों के पालन-पोषण पर होगा और जब ऐसा होगा तो दिन प्रति दिन हमारे समाज का रहन-सहन का स्तर ऊंचा होता जाएगा ।

स्पीकर साहिब, हरियाणा एक छोटा सा प्रान्त है । यह आज तक पिछड़ा हुआ रहा है क्योंकि इसकी तरफ पंजाब में कोई खास ध्यान नहीं दिया गया था । इसमें उद्योग धन्धे लगने का बड़ा स्कोप है । यदि छोटे छोटे उद्योग धन्धे यहां लगा दिए जाएं तो उनमें गरीब आदमियों को काम करने का अच्छा मौका मिलेगा । हमारे कुछ जिले हैं जहां इस तरह के उद्योगों को स्थापित किया जा सकता है । हिसार में कपास काफी ज्यादा पैदा होती है । वहां कौटन मिल लग सकती है । करनाल में पशु ज्यादा हैं । वहां चमड़े का कारखाना तथा दूध की स्कीम कामयाब हो सकती है । इसी तरह यदि छोटे छोटे कारखाने देहातों के अन्दर लगाए



जाएं तो जितना भी गरीब वर्ग हमारा वहां रहता है उसको मजदूरी मिल सकेगी और वे लोग उन्नति करने के लायक हो सकेंगे ।

स्पीकर साहिब, सेहत के महकमे से सम्बन्ध रखने वाली भी कुछ बातें मैं आपके द्वारा सरकार के आगे रखूंगी । यह तो बड़ी अच्छी बात है कि सरकार ने मैडिकल कालेज में पढ़ने के लिए हरियाणा के विद्यार्थियों को काफी सीटें रिजर्व कर दी हैं और तहसील हैडक्वार्टरज पर जहां जहां प्राइमरी हैल्थ यूनिट्स नहीं हैं हैए—थ यूनिट्स खोलने का सरकार का विचार है । लेकिन इन सब बातों को देखते हुए भी इस दिशत में अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है क्योंकि आज भी देहात का बहुत सा हिस्सा ऐसा है जिसमें 20, 30 और कई जगह 40— 40 मील तक कोई हस्पताल नहीं है । ऐसी हालत में आप अन्दाजा लगाएं कि जो फलड अफैक्टिड एरियाज हो, जहां बाढ़ आती है, हस्पताल पास न हो, तो उनके ऊपर क्या कुछ बीतती होगी । किस ढंग से वे अपना बचाव कर सकते हैं । इस लिए अगर सरकार ज्यादा न कर सके तो कम से कम 1 ।) मील के एरिया के अन्दर तो इसे अवश्य कोई न कोई डिसपैन्सरी खोलनी ही चाहिए जिससे बीमारी के समय गरीब आदमी उससे लाभ उठा सके ।

इसके साथ ही साथ, स्पीकर साहिब, मैं आपके जरिए सरकार से एक और प्रार्थना करना चाहती हूँ । हमारे हरियाणा में, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, फलड काफी हिस्से में आते हैं । इसके लिए सरकार काफी साधन जुटाती ज। रही है । बहुत सी ड्रेनें गहरी

की जा रही हैं लेकिन सबसे बड़ी समस्या पुलों की है । ड्रेनें तो बन जाती हैं लेकिन कई कई मील तक पुल नहीं होता । गांव इस तरफ बसा होता है, खेत परली तरफ बने होते हैं और बीच में पुल न होने की वजह से उन्हें बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है । इसलिए सरकार से मेरी प्रार्थना है कि ज्यादा नहीं तो कम से कम अढाई तीन मील के फासले परतो इसे अवश्य पुल बना देने चाहिए, चाहे कहीं नहर है या ड्रेन है ।

स्पीकर साहिब, आपने मुझे बोलने का समय दिया है इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सरकार से, अपना स्थान लेने से पूर्व, विनती करती हूँ कि जो जो प्रार्थनाएं मैंने उनसे की हैं उन पर वे जरूर ध्यान दें ।

**श्री बनारसी दास गुप्ता ( भिवानी ) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा चल रही है । मैं इस मामले पर बहुत कुछ बातें कहना चाहता था, कहूंगा भी, लेकिन जब मैं सामने विरोधी दल के सदस्यों की सीटें खाली देखता हूँ तो मेरा उत्साह कम हो जाता है । अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि लोकतंत्र में विरोधी दल का होना अति आवश्यक है । जितना सरकारी दल जरूरी होता है, विरोधी दल भी उतना हो आवश्यक होता है और उसके बिना यह सदन मैं समझता हूँ अधूरा है । मेरे सामने अगर मेरे में दोस्त बैठे हुए होते तो बहुत सारी ऐसी बातें थीं जिनका कहना मुझे बड़ा जरूरी होता लेकिन फिर भी, अध्यक्ष महोदय, तमाम घटनाएं आपके सामने हैं । इधर बैठे हुए लोगों

का इसमें कोई दोष नहीं कि आज वे मेरे भाई सदन से वाक-आऊट करके चले गए हैं । स्पीकर साहिब, आप तो जानते हैं आज से कुछ दिन पहले किसी सदस्य महोदय ने कुछ ऐसी-बात की जो सदन के सम्भाग में शोभनीय नहीं थी । आपने, अध्यक्ष महोदय, अपने कर्तव्य की तरफ ध्यान देते हुए एक ऐक्शन लिया परन्तु मुझे खेद है कि विरोधी दल के भाई और विरोधी दल के नेता उस बात को उस कहानी को रोज दोहराते तो अवश्य हैं परन्तु इस बात को महसूस नहीं करते कि इसमें दोष किस का है या होना चाहिए । डेमोक्रेसी में यह सबसे अनिवार्य है कि सदन के जो अध्यक्ष हैं, उनके आदेश का तुरन्त पालन किया जाए । अध्यक्ष का अपमान डेमोक्रेसी का अपमान है, तमाम लोकतंत्र की बेइज्जती है । तो इस बात को सहन न करते हुए और लोकतंत्र की स्वस्थ परम्पराओं को कायम रखने के लिए एक पग यहां उठाया गया है और एक प्रस्ताव के जरिए कुछ भाई जो ऐंसी हरकत करते थे उनके विरुद्ध एक फैसला, एक निश्चय सदन में किया गया है आज उस बात को लेकर अगर विरोधी दल के भाई सदन में उपस्थित न हो तो मैं समझता हूँ कि वे अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करते हैं' । जिस जनता को वे प्रतिनिधित्व करते- हैं, उसके साथ वे विश्वासघात कर रहे हैं । आज बजट जैसे अहम मामले पर विचार होते समय अगर वे यहां मौजूद होते, अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करते, अपने विचार रखते और कोई कंस्ट्रक्टिव क्विस्टिंसजम करते तो उससे सरकार को भी लाभ होता और हमारे प्रदेश को भी लाभ होता । स्पीकर साहिब, यदि आज विरोधी दल के नेता यहां

उपस्थित होते तो बतलाते वे इस बात को कि यह बजट कैसा है, इस बजट में क्या खामियां हैं और सरकार तथा सदन उनकी बातों को सुनता, मगर दुर्भाग्य है कि उन्होंने इस बात पर विचार न करते हुए सदन का त्याग किया । मैं तो चाहता था कि फ़ैक्ट्स के साथ, फिगरज के साथ मैं उनके सामने कुछ बातें रखता । इत्फाक से आज विरोधी दल के नेता वही महाशय है जो आज से कुछ दिन पहले यहां होने वाली सरकार के भी नेता थे । उन्होंने भी एक बार बजट पेश किया था । सूखी सदन में उस बजट में कई प्रकार के टैक्स हरियाणा की जनता पर थोपे थे और आज से केवल सात महीने पहले जो वर्तमान सरकार को 8 करोड़ के घाटे का बजट इस सदन में पेश करना पड़ा था वह भी उनकी सरकार की कारगुजारियों का नतीजा था । लेकिन मैं दाद देता हूँ इस सरकार को, मैं दाद देता हूँ वित्त मंत्री महोदया, श्रीमती ओमप्रभा जैन को, कि इतना घाटा होने के बावजूद भी एक पैसे का टैक्स जनता के ऊपर नया नहीं लगाया और न ही किसी कर में वृद्धि कि मगर फिर भी बड़ी शान के साथ प्रदेश का काम चलाया, विकास और डिवैल्पमेन्ट का काम चलाया । स्पीकर साहिब, आपको मालूम है कि डेढ़ सौ स्कूल हरियाणा में अपग्रेड किए गए और बिना एक पैसा लिए ।

आपको यह भी मालूम है कि इससे पहले 40 हजार रुपये हाई-स्कूल को अप-ग्रेड करने के लिए गांव से वसूल किए जाते थे । और 15 हजार रुपये किसी मिडल स्कूल को अपग्रेड करने के

लिए लेते थे उन गरीब ग्रामीण किसानों से लेकिन इस सरकार ने एक पाई भी नहीं ली और 150 स्कूलों को अपग्रेड किया है । तो शिक्षा के क्षेत्र में यह एक बड़ा भारी कदम है ।

इसके इलावा, अध्यक्ष महोदय, संयुक्त दल की सरकार ने आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों पर भी फीस लगा दी थी वह फीस भी इस सरकार ने माफ कर दी है । दूसरे विकास के क्षेत्र जैसे खेती है, उद्योग धंधे हैं, सड़के हैं, इनमें भी सराहनीय काम हुआ है । जहां तक बिजली बोर्ड का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं उसमें तो एक रिकार्ड ही कायम कर दिया हूँ । सारे हिन्दुस्तान में सात महीने के अन्दर कहीं भी इतना काम नहीं हुआ होगा । इस सरकार ने सात महीने के अन्दर 15 हजार ट्यूबवैलों को बिजली दी जबकि 20 साल के अन्दर केवल बीस हजार ट्यूबवैलों को ही दी गयी । सात-आठ महीनों में 15 हजार ट्यूबवैलों को बिजली देना कितना सराहनीय और तारीफ का काम है । अध्यक्ष महोदय, जिन इलाकों में इन ट्यूबवैलों को एनरजाइज किया गया इस इलाके में आपको जाने का इत्तफाक हुआ होगा । लुहारू और महेन्द्रगढ का इलाका, जहा रेगीस्तानी इलाका था, जहां रेत के टीले थे, जहां पीने को पानी नसीब नहीं होता था आज उस इलाके के अन्दर बिजली की मेहरबानी से अंगूर की खेती की जाती है । और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और सर-सब्ज खेत दिखलायी देते है । ऐसे रेगिस्तान में जहां कई बार सफर करते हुए इन्सान पानी की घूंट के विना प्राण त्याग देते थे आज उन इलाकों में अंगूर की

खेती और तरह तरह की हरी सब्जी पैदा करना यह एक स्वपन है जो आज साकार और सबल हो कर नजर आया है । इन बातों से आप अन्दाजा लगायें कि इस सरकार ने कितना विकास किया है और जिस सरकार ने जनता पर टैक्स भी बढ़ाये लेकिन उसके बावजूद भी कोई आठ महीने के शासनकाल में कोई विकास नहीं कर पायी हो वह कैसी थी । स्पीकर साहिब, आज से सात महीने पहले इस सरकार ने जो आठ करोड़ रुपये के घाटे का बजट पेश किया था, आज जनता पर विना कर लगाये और विकासके कार्यों पर अधिक खर्च करने के बाद भी उसे पांच करोड़ और दस लाख के घाटे तक ले आना बड़े ' गर्व. की बात है । बिना जनता पर टैक्स लगाये इतना मेक-अप करना बड़ा सराहनीय कदम है । इस वर्ष केवल एक करोड़ और 24 लाख का घाटा दिखाया गया है । पिछले घाटे को शामिल करने के बाद यह ह लाख 34 हजार होता है । बहिन ओम प्रभा जैन की किन शब्दों में मैं प्रशंसा करूं । उन्होंने बड़ा ही सराहनीय काम किया है । अध्यक्ष महोदय, इस घाटे को पूरा करने के लिए एक पैसे का भी नया कर अगले वर्ष के लिए नहीं लगाया है । यह भी कितनी खुशी की बात है । इसप्रकार से बीस साल के अस में कोई भी घाटे का बजट होता था तो फौरन जनता का गला दबोच लिया जाता था । और बोझ तो लोगों की पीठ पर पहले ही होता है उस पर और वजन रख दिया जाता था लेकिन हमारी सरकार ने बजट के अन्दर कोई नया टैक्स नहीं लगाया है, न पिछले टैक्स को बढ़ाया है बल्कि हमारी वित्त मन्त्री महोदया ने आश्वासन दिये हैं कि सम्पत्ति कर की

वसूली में कुछ सरलता की जाये और जो नये उद्योगधंधों को लगायेंगे उनको पांच साल तक प्रौपर्टी टैक्स देने से एगजेम्मेंट किया जाये, मुक्त किया जाये । इसके इलावा मुझे इस बात को खुशी है कि इस बजट में बूढ़ों का भी सरकार ने ध्यान रखा है । आज हमारे विरोधी दल के साथी यहां नहीं हैं परन्तु हमारी डिप्टी स्पीकर साहिबा जो बूढ़ों का विशेष ध्यान रखती हैं यहां बैठी है । स्पीकर साहिब, पिछले दिनों राव साहिब की सरकार ने उन गरीब और बूढ़े लोगों की पेन्शनें बन्द कर दी थीं परन्तु हमारी सरकार उन पेन्शनो को फिर से देना आरम्भ कर रही है । इतना ही नहीं कि आरम्भ कर रही है बल्कि पहले पन्द्रह रुपये महीने दी जाती थी अब 25 रुपये महीना कर रही हूँ । यह भी कितनी प्रशंसनीय बात है ।

स्पीकर साहिब, जो सब से प्रशंसनीय और सराहनीय कार्य इस सरकार ने किया है वह यह है कि घाटे का बजट होते हुए और हमारे साधन इस छोटी सी स्टेट के बहुत सीमित होते हुए भी हमारे जो लो-पेड कर्मचारी हैं और जो इस सरकार के हाथ और पैर हैं, जो सरकार की पालिसी कार्यान्वित करते हैं उन लो-पेड कर्मचारियों के ग्रेड रिवाइज किये गये और दो करोड़ रुपये साल का बोझा बर्दाश्त किया गया और फिर भी सरकार का काम बड़े अच्छे ढंग से चल रहा है । यह एक बड़ा अच्छा बजट आज हाउस के सामने पेश किया गया है । विरोधी दल जरा अपने बजट को देखें और इस बजट को देख कर शान्ति के साथ,

इतमिनान के साथ इसकी तुलना करें, इसका मुकाबला करें । इस बजट में जो खामियां उनको नजर आतीं वे अगर उन्हें पेश कर देते तो कुछ मजा आता और कुछ समझ आती और इस सदन को भी कुछ लाभ होता । परन्तु मैं समझता हूं वे अपने फर्ज को भूले बैठे हैं । स्पीकर साहिब, आपको तो मालूम है जब यह सदन का अधिवेशन आरम्भ हुआ तो गवर्नर साहिब ने अपना भाषण दिया । उस गवर्नर एड्वंस पर विरोधी दल के नेता राव साहिब ने जो अपना भाषण दिया और बाद में ' सप्लिमैन्ट्री ग्रान्ट्स गर जो कुछ उन्होंने कहा उन बातों को सुन कर मैं बड़ा मायूस हुआ, बड़ा निराश हुआ, उन्होंने अपने भाषण में केवल पोलिटिकल बातों का ही जिक्र किया और वे भी बहुत नीचे स्तर की । स्पीकर साहिब, मैं कहना तो काफी कुछ चाहता था अगर वे यहां पर मौजूद होते लेकिन इस समय वे हमारे सामने मौजूद नहीं हैं फिर भी मैं एक बात का जिक्र करना चाहता हूं । उन्होंने बार बार डिफैक्टर का जिक्र किया । हमारे जनसंघ के— नेताओं ने भी डिफैक्टरों का जिक्र किया । लेकिन मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि वे खुद ही हमेशा डिफैक्टरों को माला पहनाने के लिए तैयार रहते हैं । स्पीकर साहिब, आप पिछला हिन्दुस्तान का इतिहास उठा कर देख लें । आप उसमें यह पायेंगे कि जिन लोगों ने कांग्रेस से डिफैक्ट किया उन्हें इन जन संघ और विरोधी दल वाले नेताओं ने इनाम दिया और मुख्य मन्ती बनाया । मध्य प्रदेश की मिसाल आपके सामने है जी०एन० सिंह ने कांग्रेस को छोड़ा तो इन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया, चौधरी चरण सिंह ने यू०पी० में कांग्रेस को



छोड़ा तो इन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया और हरियाणा में राव साहिब ने कांग्रेस को छोड़ा तो उनको मुख्य मन्त्री बनाया । ये लोग तो वैसी ही बातें करते हैं कि चोरी करना बहुत बुरी बात है लेकिन चोरी किये हुए माल को घर में लाया जाये तो बड़ी अच्छी बात है । अभी भगवत् दयाल ने कांग्रेस को छोड़ा तो इन्होंने अपना लीडर बना लिया । ये डिफैक्टर को इनाम देते हैं और यहां कहते हैं कि डिफैक्शन बहुत बुरी बात है । इस का मतलब तो यह हुआ कि अगर मैं इन से इत्तफाक करूं तो मैं कल ही इनका लीडर बन जाऊंगा । भाई मुख्तियार सिंह ने कहा था कि हम तो शिकारी हैं । चौधरी साहिब इस वक्त यहां मौजूद नहीं हैं । मैं उन्हें बतलाता कि आप शिकारी तो हैं मगर मुर्दा खाने वाले शिकारी हैं । खुद भार कर शिकार करने वाले नहीं । उन्होंने कहा था कि मैं किसी से नहीं कहता कि पार्टी बदलो । यह तो ठीक है कि वह खुद तो शिकार नहीं करते मगर आपने देखा होगा कि एक पक्षी गिद्ध होता है जो पेड पर बैठा रहता है और जब कही कोई पशु मर जाता है तो वह झपट्टामार कर उस पर टूट पड़ता है । उसी तरह के चौधरी साहिब शिकारी हैं । खैर इस वक्त वह यहां नहीं हैं इस लिए उनकी गैरहाजिरी में ऐसी बातें कहने में मुझे मजा नहीं आ रहा । मैं इस विषय को छोड़ता हूं । मैं जनाब आपके द्वारा सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि किसी भी प्रदेश की उन्नति के दो ही साधन होते हैं' । एक तो खेती का साधन और दूसरा उद्योग धन्धों का साधन । खेती की तरफ सरकार ध्यान दे रही है लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें हैं..

श्री अध्यक्ष : कितना टाइम और टाईम चाहते हैं?

श्री बनारसी दास गुप्ता : सिर्फ 15 मिनट और ।

श्री अध्यक्ष : सिर्फ 5 मिनट ।

श्री बनारसी दास गुप्ता : जनाब, अभी मैंने अपने हल्के की बात तो कही ही नहीं । स्पीकर साहिब, खेती का जहां तक ताल्लुक है यह ठीक है कि इस साल वर्षा नहीं हुई । भगवान हमारे से रूठ गया और दरियाओं में पानी कम रहा व नहरे भी कम —चली लेकिन इसके बावजूद भी नहरों के पानी की जो तकसीम है वह विधि पूर्वक होनी चाहिए । किसी को यह शिकायत न हो कि पानी की तकसीम में कोई गडबडी हुई है । स्पीकर साहिब, जिस इलाके से मैं ताल्लुक रखता हूं उसके लिए ही नहीं बल्कि तमाम भिवानी तहसील की यह हालत है कि वह सारा इलाका नहरकी टेल पर आता है जिसके कारण वहां तक पानी पूरा नहीं पहुंचता और अगर नहर के अन्दर कोई बीच होता है तो जो घाट । होता है वह टेल के ऊपर रहने वाले किसानों को भरना पड़ता है । और जनाब वहां खेती के मामले में पानी के न मिलने की समस्या नहीं है वहां तो पीने का पानी भी नहीं मित्रता और यह भी एक बड़ी भारी समस्या रहती है । अगर आप यूलिस की रिपोर्ट मंगा कर देखें तो उससे पता चलेगा कि रिपोर्टों में बहुत परसेंटेज ऐसे केसिज की होगी कि नहर पर पानी लेते वक्त लोगों के झगडे हुए और आपस में सिर—फुटौवल हुई । हालत यहां तक नाजुक है कि भिवानी

डिस्ट्रीव्यूटरी में जो पानी आता है, और उससे तैयार किया हुआ जो वाटर वर्कस है जिससे पीने का पानी दिया जाता है उस पानी को देने के लिए किसानों के खेतों की मोरियां बन्द कर दी जाती हैं । मैं यह नहीं कहता कि वाटर वर्क? स में पानी न दिया जाए मगर उनके रजवाहे बन्द करना और मोरियां बन्द करना एक बड़ा भारी अन्याय है । आपको पता हूँ कि किसान कितना महंगा बीज लेता है लेकिन जब पानी को वारी आती है तो उसकी मोरियां बन्द हो जाती हैं कितना उसका नुकसान होता है और कितना उसको दुःख होता है । मैं आपके द्वारा सरकार से यह प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वहां पर पानी की मिकदार इतनी बढ़ाई जाए कि वाटर वर्कस का पानी भी पूरा हो और फिर ऐसी नौबत न आए किसानों की मोरियां बंद हों ।

जहां तक उद्योग-धंधे का ताल्लुक है मैं कहूंगा कि सरकार का ध्यान इस तरफ है लेकिन जो भी इंडस्ट्रियल कालोनी बनाई जाए उनकी तरफ पूरा ध्यान दिया जाए । मैं सरकार का ध्यान हिसार की इंडस्ट्रियल कालोनी की तरफ दिलाना चाहता हूँ । वही के लोग बड़े निराश हो चुके हैं, उनको पीने का पानी नहीं मिलता और उनको दूसरी सुविधाएं नहीं मिलतीं, काफी उद्योगपति घाटा खा खा कर वहां से जा चुके हैं । वह पर 4 फोकल प्वायंट्स सरकार ने डिक्लेयर किए हैं लेकिन उनमें से पूरे साधन नहीं मिले । इसलिए मेरा निवेदन यह है कि जो भी औद्योगिक बस्ती बनाई जाएं और उसके लिए जो भी कमिटमेंट की जाए वह पूरी की जाए

और उद्योगपतियों को पूरी सुविधाएं मुहैया की जाएं । मैं इस वारे में एक सुझाव देना चाहता हूं कि दिल्ली हरियाणा के नजदीक है और दिल्ली खरीदने और बेचने का केन्द्र है । हम दिल्ली से कायदा उठा सकते हैं । इसलिए एक इंडस्ट्रियल बैल्ट ऐसी बनाई जाए कि हरियाणा के अन्दर दिल्ली के तीन तरफ औद्योगिक बस्तियों का विकास किया जाए जिससे कि माल तैयार होकर दिल्ली में बेचा जगर और प्रोडक्शन के लिए माल खरीदा जा ए । अगर इस तरफ ध्यान दिया गया तो हरियाणा का औद्योगिक क्षेत्र आगे बढ़ेगा ।

**श्री अध्यक्ष :** आप का टाईम हो गया है । अब आप खत्म करें ।

**श्री बनारसी दास गुप्ता :** एक मिनट और, जनाब, इसके बाद मैं झज्जर का इलाका, भिवानी का इलाका, महेन्द्रगढ का इलाका जहां पर ट्यूब वैल्ज भी नहीं लगाए जा सकते उसकी तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । यहां पर मीठे पानी की भी बैल्ट नहीं है जमीन के अन्दर इस लिए ट्यूबवैल्ज का भै । फायदा नहीं हो सकता । लिहाजा मेरी सरकार से अपील है कि किशाऊ डैम बचाने की के । जमुना नदी पेर योजना चल रही है उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जा ना चाहिए, क्योंकि बगैर जमुना पर डैम बनाए इन इलाकों का उद्धार नहीं हो सकता । जनाब, आप खेती वाले धन्धे से सम्बन्ध रखते हैं और आपको पता है कि खेती में पानी की सबसे बड़ी उपयोगिता है इस लिए पानी का इन्तजाम किया जाए ।

मेरा इलाका नगर है । नवार में जो विकास होता है वह नगर पालिकाओं के द्वारा होता है लेकिन हरियाणा की सभी नगरपालिकाओं की हालत बड़ी सोचनीय है । उनके खर्चे ज्यादा हैं, मगर आमदनी कम है । वे नई सुविधाएं नहीं दे सकती । यहां तक कि या सड़कों जैसी चीजों को दे मेनटेन नहीं कर सकतीं नतै की बात तो रहने दीजिए । इस लिए नगरपालिकाओं के लिए ग्रांट रखी जाए ताकि वे अपने रिसोर्सिज डिवलेप कर सकें । इन शब्दों के साथ स्पीकर साहिब, मैं एक बात और कहना चाहता हू । जैसे अभी बहिन प्रसन्नी देवी ने हरिजनो की बात कही —.

**श्री अध्यक्ष :** आपका टाइम खत्म ही गया, अब आप बैठिए ।

You are exceeding Your time please. You have, every time said one minute, one minute.' No more please.

**Shri Banarsi Dass Gupta :** Thank you, Sir I resume my seat.

**चौधरी राम प्रकाश (मुलाना, ऐस. सी. ) :** स्पीकर साहिब इस बजट को पढ़ने से पता लगता है कि कोई नया टैक्स न लगाने के वावजूद भी यत्र छोटी सी स्टेट कितनी तरक्की कर रही है । मैं इस के लिये अपनी सरकार को बधाई पेश करता हूँ । अभी अभी विजली और ट्यूबवैल्ज का यहां जिक्र किया गया है । चीफ मिनिस्टर साहिब यहां पर नहीं है । इन्होंने कह बार अपनी तकरीरों में फरमाया है कि जिला अम्बाला की जमीन बड़ी उपजाऊ है और अगर यहां पर काफी मिकदार में ट्यूबवैल्ज लगाया जाए या पानी देने के कोई और साधन हो जाएं तो यह अकेला जिला

सारे हरियाणा को अनाज सप्लाई कर सकता है । लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इस जिला में काफी तादाद में ट्यूबवैल्ज नहीं है' और खास तौर पर मुलाना जगाधरी रोड पर और अम्बाला कैंट के दर मियानी इलाका में नहीं है । बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस सारे इलाका में कोई ट्यूबवैल नहीं है । वह बहुत अच्छी जमीन है और थोड़े पैसे से ट्यूबवैल वहां लगाए जा सकते हैं । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जहां आप और जिलों को ट्यूबवैल्ज लगाने के सिलसिले में तरजीह देते हैं तो वहां हमारे जितना अम्बाला में जिसके बारे में चीफ मिनिस्टर साहिब ने वायदा भी किया हुआ है कि ट्यूबवैल्ज लगाए जाएंगे वह लगाने चाहिए । मैं सरकार का मशकूर हूँ कि उस ने बराडा ब्लॉक में ट्यूबवैल्ज और बिजली के सिलसिले में कुछ थोड़ा सा ध्यान दिया है और 33 के वी लाइन का सबस्टेशन बनाया है लेकिन उससे कुछ थोड़े से हिस्से की इरीगेशन हो सकती है और सारे इलाके की नहीं । अगर ऐसे चार पांच सबस्टेशन और बना दिए जाएं तब उस इलाके का भला हो सकता है और सिंचाई हो सकती है । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जहां दूसरे जिलों में 66 के वी सबस्टेशन बनाए गए हैं तो कम से कम दो चार सबस्टेशन हमारे इस तुलाके में भी बनाने चाहिए ।

जहां तक सड़कों का सवाल है मेरे इलाके में पिछले दस सात में कोई सड़क नहीं बनी है हालांकि दो तीन साल हुए उस वक्त जो पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर थे उन्होंने फरमाया था कि कालपी से

नारायणगढ़ जो सड़क जाती है उसे मुकम्मल करेंगे । स्पीकर साहिब वह इलाका ऐसा है जिसकी तरफ आज तक किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है । वहाँ पर न कोई सड़क हूँ न स्कूल है और न हस्पताल है और न कोई ट्यूबवैल है । आप जानते हैं कि जमींदार ने जब मंडी को गल्ला लाना होता है तो वह बगैर सड़क के नहीं लाया जा सकता है । कालपी से नारायणगढ़ वाली सड़क का सर्वे हो गया हुआ है ऐस्टिमेंट बन चुका है और सैंक्शन हो चुकी है लेकिन अफसोस की बात है सड़क पर काम नहीं शुरू हुआ है । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस बजट सेशन के बाद वह सड़क बननी जरूरी है । एक और इम्पौरटेंट सड़क पावनी से सराहों की है । जगाधरी से पावनी तक का टुकड़ा तो ब्लाक डिवलपमेंट स्कीम के तहत बन चुका है और कुछ टुकड़ा बराडा से सराहों तक मुकम्मल है और कोई चार मील का टोटा बाकी रहता है और उस टुकड़े के न होने से सारी सड़क बेकार हो जाती है । पोसवाल साहिब ने वायदा किया था कि इस साल के बजट में वह सड़क आ जाएगी । अगर इस साल यह सड़क बन जाए तो मैं उनका बड़ा मशकूर हूंगा । फिर जो थोड़ी बहुत सड़कें हमारे हैं भी वह फलड्ज की वजह से डैमेज हो गई हैं । आज तक उन सड़कों की मरम्मत की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है । शाहाबाद बराडा सड़क जो है वह टोटली टूटी पड़ी हुई है । तीन चार मील का टुकड़ा ऐसा है जो बेकार हो गया है । उसकी मरम्मत की बहुत जरूरत है । उस पर बड़े ट्रक चलते हैं और यह सड़क हमारे प्रांत को हिमाचल प्रदेश से मिलाती है ।

फिर अधोआ से वराडा तक का कोई दो मील का टुकड़ा हूँ जो टूटा पड़ा है । उस सड़क के बनाने पर काफी पैसा खर्च हुआ हुआ है लेकिन दस मात्र से उसकी कोई मुरम्मत नहीं हुई है । उसमें खड्डे पड़े हुए हैं । किसान जो बराडा गन्ना लाते हैं उनके बैल खत्म हो जाते हैं और गड्डे टूट जाते हैं । इसी तरह कुछ इप्रोच रोडज हैं । मेरे इलाका की पंचायतों ने जितना रुपया उनके हिस्से पड़ता था गवर्नमेंट के पाम जमा करा दिया हुआ है और वह सड़कें आसानी से बन सकती है । इसलिये यह जो चार पांच एप्रोच रोडज हैं उन हार जरूर काम शुरू किया जाए । एक अधोअ, से लाडवा जाती हुं । उस इलाके में कोई सड़क नहीं है । तीन चार मील का हिस्सा खुद लोगों ने अपनी हिम्मत से बगैर सरकार का पैसा लिये बना लिया है और अब सात मील का टुकड़ा वाकी बचता हूँ । वह सड़क जल्दी बननी चाहिए ।

हमारे हरियाणा में आठ नौ महीने से बारिश नहीं हुई लेकिन सरकार ने कुछ खास खास एरियाज को ड्राट एरिया करार दिया है और कई एरिया कई एरियाज रह गए हैं । मेरा निवेदन है कि जिस जिस इलाका में बारिश नहीं हुई है उसे ड्राट एरिया करार देना चाहिए । मैं तो समझता हूँ कि सारे हरियाणा को ही ड्राट एरिया करार देना चाहिए । जो खास खास इलाके ड्राट एरिया करार दिए गए हैं उनकी खास रियायतें मिलती हैं लेकिन जिला अम्बाला को कोई रियायत नहीं मिली है । वहां न बारिश हुई न वहा नहर है और न ट्यूबवेलज है । जो एक नहर हमारे इलाके में



से गुजरती भी है उसे एक बंद गली भी हमें नहीं मिलता है ।  
इसलिए मेरा निवेदन हुं कि उसको ड्रा' एरिया करार दिया जाए ।

एक बात मैं जंगलात के बारे मे करना चाहता है । हमारे सूबा में'  
सिर्फ दो हीं जंगल है एक मोरनी का और दूसरे कलेसर का ।  
जंगलात वालों ने हमारे ऊपर जो मेहरबानी की है वह मै बताना  
चाहता हूं । कहीं दस एकड़ में कहीं बीस एकड़ में यह पौधे लगा  
रहे हैं और वह पौधे कैसे लगाए जाते हैं वहूँ में खास तौर पर  
बताना चाहता हूं । जौ जमीन हरिजनों और गुजारों के कब्जा में  
थी उन से उनको पिछली सरकार ने उजाड़ कर रख दिया है ।  
दौलता साहिब यहां नहीं है' । मैंने उस वक्त उन से कहा था कि  
गरीब लोगों को उजाड़ रहे हो उनकी बद दुआ लगेगी, आपका  
भला नहीं होगा । आरन वहूँ हाउस में नही है' और यह उनकी  
बददुआ का असर है । दादूपुर एक जगह है वहा बीस घर बसे हुए  
थे इन गरीबों के, उनकी उजाड़ कर रख दिया है और उनकी  
जमीन पर से पौदे लगाने के लिये उठा दिया गया है । मैं पूछना  
चाहता हूं कि दस बीस एकड़ पर पौदे लगाने का क्या मतलब हूँ ।  
पोदे लगाने हैं' तौ सारे एरिया में लगाओ लेकिन यह वहां ही  
लगाते हैं जहां कोई गरीब गुजरे बसे होते हैं । मैं निवेदन करता  
हूं कि ठीक है कि हम जंगलात चाहते हैं और इनका होना जरूरी  
है लेकिन दस बीस एकड़ पर जंगलात लगाने का कोई मतलब  
नहीं है । मैं बहिन जॉ के नोटिस में यह बात लाया था कि मुजारे  
उजड़ गए हैं और उन का गुजारा नहीं होता है भूखे मर रहे हैं

और उन्होंने बड़ी मेहरबानी करके फरमाया है कि अच्छा देखने जायेंगे उस इलाके को । बीस एकड़ का रकवा तो ले लिया खौधरी राम प्रकाश है लेकिन एक पौदा नहीं लगाया है खामखाह जमीन पर कब्जा किया हुआ है । यह बात मैंने चार पांच रोज पहले बहिन जी को बतायी । बहिन जी ने भी जाने का वायदा किया लेकिन अब यह पता लगने पर ..... कंजरवेटर जो हैं उन्होंने पौदे लगाने शुरू कर दिये हैं । इससे पहले कि बहिन जी वहां जा कर इन्साफ कर सकतों उन्होंने पहले हा पौदे लगाने शुरू कर दिए हैं ताकि कह सकें कि अब क्या हो सकता है पौदे लगा दिए हैं पैसा बरबाद हो जाएगा । मैं आठ बस रोज पहले उस अफसर को मिला था और उसे ऐसा न करने के लिए कहा था लेकिन उन्होंने फौरन पौदे लगाने शुरू कर दिए कि कहीं बहिन जी वहां पर इन्साफ न कर दे । उस अफसर की जवाबतलबी होनी चाहिए । जितना रुपया उसने पौदों को लगाने पर खर्च किया है वह सब बरबाद हो चुका है और वह उससे रिकवर होना चाहिए । अब मैं थोड़ा सा फलड के बारे में जिक्र करना चाहता हूं ।

**श्री अध्यक्ष :** आप कितना टाईम और लेंगे?

**चौधरी राम प्रकाश :** मैं ज्यादा टाईम नहीं लूंगा, सिर्फ पांच मिनट और चाहिए । मैं फलड के बारे में कह रहा था, हमारे दूसरे साथी एम ० एल ० ए० साहिबान ने भी फलड के बारे में जिक्र किया । ठीक है, हरियाणा में फलड आते हैं और करोड़ों रुपये की हर

साल बरबादी होती है, लाखों करोड़ों रुपये की सम्पत्ति नष्ट होती है । मैने भी हाउस में तीन-चार बजट सेशन देखे हैं और सरकार से कई बार निवेदन किया कि फ्लड की ऐसी बीआरी है हरियाणा थे जिसको जितनी मर्जी कोशिश करें, जितनी मर्जी ड़ेनें बनायें, यह दुर नहीं हो सकती । स्पीकर साहिव, मैने सरकार के सामने एक तजवीज रखी थी, ठीक है वह तजवीज महंगी है, करोड़ों रुपये को स्कीम है । जिस तरह सरकार ने भाखड़ा डैथ बनाया है, उस पर कई करोड़ रुपया खर्च हुआ और लोगो को काफी फायदा है, यह स्कीम भी उसी किस्म की है । मेरी स्कीम यह है कि हरियाणा में पाँच नदियां हैं जिनकी वजह से हरियाणा बरबाद होता है । वे है घग्घर, मारकंडा, टांगरी, सरस्वती और चुतांग । चौधरी रणबीर सिंह जी यहां बैठे हैं, जब वे इरीगेशन एड पावर मिनिस्टर थे तब मैने उन्हें कहा था कि इन पांच नदियों पर डैम बना दिया जाए । जब इन पर डैम बन जायेगा तो इनका पानी रुक जायेगा और स्टोर हो जायेगा । जो लाखों एकड़ जमीन बरबाद होती है वह बच जायेगी । अगर सरकार इस तजवीज को मान ले तो काफी आमदनी हो सकती है

**खान अब्दूल गफ्फार खां :** यह नहीं मानती ।

**चौधरी राम प्रकाश :** मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि यह तजवीज सरकार ने नही मानी । इसलिए मेरी सरकार से पुरजोर गुजारिश बै कि अगर हरियाणा को फ्लड से बचाना चाहते हो और इरीगेट करना चाहते हो तो सबसे पहले इन नदियों पर डैम

लाजमी तौर पर बनाए जाएं । इसका सर्वे भी हो चुका है । यहां पर हर साल फ्लड फ्री रोकथाम की बात करते हैं और लाखों रुपया खर्च होता है, इसका कोई फायदा नहीं, यह फजूल जाता रहा है ।

अब थोड़ा स शड्यूल्ड के कास्टस के बारे में आपकी सेवा में अर्ज करना चाहता हूं । स्पीकर साहिब, हमारी सरकार हरियाणा के ' शड्यूल्ड कास्टस ने बनाई है, यह कोई लुकी छिपी बात नहीं है । इन्होंने कांग्रेस को वोट दिये और मैजोरिटी बनाई । लेकिन निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इनको अपनी जिन्दगी बसर करने के लिए अच्छे साधन नहीं है' । इन्हें जमीन की जरूरत होती है लेकिन जमीन ही नहीं । जब हरिजनों के पास जमीन नहीं होती तो लोगों का झुकाव इंडस्ट्रीज की तरफ जाता है लेकिन इंडस्ट्रीज के लिहाज से भी हरिजनों को बिल्कुल सहूलतें नहीं दी जातीं । बड़े बड़े कारखानेदारों को करोड़ों रुपया लोन दे देते हैं' लेकिन जब शड्यूल्ड कास्टस की बारी आती है तो सिर्फ पांच हजार से ज्यादा लोन नहीं दिया जाता । मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि इस बजट में हरिजनों के लिए काफी रुपया रखा गया है, शड्यूल्ड कास्टस की वैलफेयर स्कीम के तहत भी काफी रुपया रखा है, लेकिन आज जो शड्यूल्ड कास्टस की हालत है उसको देखते हुए मैं समझता हूं कि यह रुपया थोड़ा है । अगर शड्यूल्ड कास्टस के लिए उद्योग-धन्धे चलायें तो दूसरे तबकों के साथ साथ इनका भी भला हो सकता है । अन्त में मेरा सरकार

से, आपके जरिये, निवेदन है कि जौ चीजें मैंने सरकार के सामने रखी हैं—फलड, बिजली, पानी वगैरा वगैरा की, उसके ऊपर वह जरूर ध्यान दे । ( इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई ) ।

**चौधरी राजेन्द्र सिंह ( कौलाना ) :** डिप्टी स्पीकर साहिबा, सरकार ने जो वजट (ए श किया है, वह वाक्या ही काबिले तारीफ है लेकिन मेरी समझ के मुताबिक इसमें कुछ ओमिशन्ज रह गई हैं । सरकार ने गवर्न मैट इम्पलाईज को जो रिलीफ दिया है वह ठीक तरह से नहीं दिया किसी को ज्यादा रिलीफ दे दिया गया है और किसी को कुछ नहीं दिया । जिन को रलीफ दिया तै उनके बारे में ऐसा मालूम होता है कि जैसे वे खुद अकाउंट्स की ब्रान्च में रहते हो और उन्होंने अपने लिए खुद ही पैसे ले लिये हों, लेकिन जो दूसरे तबकों की बड़ी पोस्टों पर लगे हुए आदमी हैं, जो हिम्मत से काम करते हैं उनके साथ कोई इन्साफ नहीं हुआ । जैसे ऐस. डी. ओ. और इंजीनियर्ज हैं, ये बड़े बड़े डैमों पर काम करते हैं इन्हें कोई रिलीफ नही दिया । आज से पाँच साल पहले जो इंजीनियर पंजाब के इंजीनियरों के साथ इकट्ठे काम करते थे उन को 350 रुपये दिये गये और पंजाब में 430 रुपये दिये जाते हैं । इन की तन्खाहों में इतना फर्क नहीं होना चाहिए क्योंकि एक ही डैम पर काम करने वाले हैं, एक ही रैंक के आदमी है । पंजाब के इंजीनियर और हरियाणा के इंजीनियर जिन्होंने एक ही कालेज में ट्रेनिंग ली हो, और कई केसिज में हरियाणा के इंजीनियर पंजाब के इंजीनियरों से सीनियर भी हूँ, उन्हें कम पैसा नही दिया

जाना चाहिए । यह चीज मैंने फाईनेस मिनिस्टर साहिब के नोटिस में भी लाई है और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि इस मामले पर हमने आदमी बिठाये हुए हैं, वे गौर करके इस कमी को पूर करेंगे । इसके इलावा इसी तरह ओवरसीयरों को चालीस पचास रुपये कम मिलते है , जबकि वे किसी से कम क्वालिफाईड न हीं हैं ले किन जो इनसे कम क्वालिफाईड है' उन के इन से ज्यादा दे दिया गया है । जिन को रिलीफ दिया गया है, मैं उन के खिलाफ नहीं हूं, मै हिसाब से चाहता हूं कि इन के साथ साथ एस.डी. ओ. और ओवरसीयरों को भी पूरा रिलीफ दिया जाये जिस हिसाब से दूसरे इम्पलाईज के पैसे बढ़ाये हैं, उनके भी उसी तरह से बढ़ाये जाने चाहिए । इस बजट में यही ए क थोड़ी सी गलती हुई है, बाकी सब ठीक है ।

इनके इलावा जो वैटरनरी डाक्टर है उनकी भी कोई रिलीफ नहीं दिया गया है, ऐसा लगता है कि उन्हें कम्पाउंडर के बराबर कर दिया गया है । जो सिविल के कम्पाउंडर हैं उनको भी कुछ नहीं दिया गया । जिस ग्रेड के लायक सिविल कम्पाउंडर थे वह ग्रेड उन्हें दिया ही नहीं गया । जो सिविल सर्जन हैं उनकी क्वालिफिकेशन भी वैटरनरी डाक्टर के बराबर ही होती है लेकिन फिर भी उनकी तन्खाह में काफी फर्क है । वैटरनरी डाक्टर की तन्खाह को भी बढ़ाया जाना चाहिए, ये लोग मवेशियों का इलाज करते हैं जो बोल नहीं सकते हैं आफिसर की हैसियत से पोली में काम करते हैं जब कि सिविल डाक्टर सिर्फ इन्सानो को ही देखते

हैं । रुस लिए मेरी दरखास्त है कि वैटरनरी डाक्टरों को सिविल डाक्टरों के बराबर ग्रेड देने चाहिए ।

दूसरी बात जिसके लिए मैं गवर्नमैट को मूबारिकबाद देना चाहता हूं वह हिन्दी को आफिशियल लैंग्वेज बनाना है । सरकार ने यह बड़ा सराहनीय कदम उठाया है । डिप्टी स्पीकर साहिब, हाउस में इम्मोशनल स्पीचिज देना कोई अच्छी बात नहीं है । अभी कुछ दिन पहले राव साहिब ने हाउस में कहा था कि यूसुफ साहिब को सिर पर बैठा रखा है । इस किसम की इम्मोशनल स्पीचिज नहीं करनी चाहिए । उसके बाद कांग्रेस पार्टी के कुछ भाई कांग्रेस पार्टी में होते हुए भी कांग्रेस को हराना चाहते थे । तो उन्होंने उस वक्त यह कहा था कि बहुमती ले आओ । मुझे इस बहुमती लपज का उस वक्त पता नहीं चला था, अब पता चला है बहुमती क्या होती है । मेरे कहने का मतलब यह है कि लैंग्वेज में बहुमती जैसे मुश्किल लपज नहीं होने चाहिए । हिन्दी लैंग्वेज लागू की गई है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर सिम्पल लैंग्वेज लाई जाये तो बहुत अच्छी चीज है । जो भाषा हम यहां पर बोल रहे हैं यही हमारी लैंग्वेज है । महात्मा गान्धी ने जिन्हें हम बापू जी कहते हैं, मुल्क को आजाद कराया, उन्होंने कहा कि अगर हम इन बड़े महापुरुषों की बात नहीं मानते तो नुकसान उठाएंगे । बापू जी ने फरमाया था कि देश की भाषा हिन्दी हो क्योंकि यह सारे राष्ट्र में बोली जाती है । फौज में भी इसकी समझते है बम्बई और महाराष्ट्र में इसको समझते हैं । लेकिन जो हरियाणा प्रान्त में

हिन्दी बोली जाती है वही असली हिन्दुस्तानी जबान है । इसकी सब समझते हैं । यही जबान जो हम आपस में बोल चाल के लिए प्रयोग करते है यदि हम अपनाए तो बहुत अच्छा है । मगर कुछ लोग अपने आपको काबिल समझ कर ऐसी लैंग्वेज प्रयोग करते हैं जो कि बड़ी कठिन होती है और बहुत कम लोग समझ सकते हैं । इससे तो यह होगा कि हमारा हरियाणा पचास साल पीछे चला जाएगा । इसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं अगर सिम्पल लफज जो हम बोलते हैं उन्हीं को प्रयोग किया जाए। मैं तो कहता हूं कि इन्हीं लक्तों का प्रयोग होना चाहिए ।

इसके इलावा, डिप्टी जीकर साहिबा, मैं एक और बात के बारे में अर्ज करना चाहना हूं । फाईनेन्स मिनिस्टर साहिबा ने बताया था और बजट में भी प्रोविजन कर रखा है कि 54 लाख के करीब रुपया सरकार जमींदारों को ट्यूबवैल लगाने के लिए कर्जे के रूप में देगी । यह तो सरकार की मेहरवानी है कि वह इतना रुपया दे रही है मगर मैं सरकार को बता दूं कि आप उनकी मदद नहीं कर रहे हो बल्कि आप उनको मार रहे हो क्योंकि जिस तरीके से यह पैसा बांटा जाता है, वह तरीका ठीक नहीं है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, जमींदारों को ट्यूबवैल लगाने के लिए कर्जा लैन्ड मॉर्टगेज बैंक के द्वारा दिया जाएगा । पहले ही कोआप्रेटिव के महकमे से लोग बड़े तंग थे क्योंकि वहाँ कुरप्शन का घर बना हुआ है । अब लैन्ड मॉर्टगेज बैंक सरकार ने और बीच में ठोंस दिया । इससे नो लॉगों को बहुत दिक्कत हो जाएगी । पहले उनको केवल



कोआप्रेटिव डिपार्टमेंट के अफसरों के पीछे घूमना पड़ता था और काम कराने के लिए सिर्फ उन्हीं को पैसा आदि ईना पड़ता था मगर अब लेन्ड मॉर्टगेज बैंक के अफसरों के पीछे भी उन्हें घूमना पड़ेगा तथा उन्हें खुश करना पड़ेगा । तब जाकर कहीं उन्हें लोन मिल सकेगा । डिप्टी स्पीकर साहिबा, जमींदार को सरकार ट्यूबवैल लगाने के लिए कागजों में तो आठ हजार रुपया देती है मगर उसे मिलते बहुत कम हैं क्योंकि उससे कहा जाता है कि अढ़ाई हजार तो पक्की नालियां बनाने के लिए खर्च करना पड़ेगा और अढ़ाई हजार बिजली का खर्चा आएगा । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं तो नहीं समझता कि इन सब बातों की कोई आवश्यकता है । जब ग्रक किसान की जमीन अच्छी िए, पक्की है तो क्यों उसे अढ़ाई हजार रुपया पक्की नालियां बनाने के लिए खर्च करने को मजबूर किया जाता है । यह बात मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा के नॉटिस में एक डिस्ट्रिक्ट मीटिंग में, जहां वे हाजिर थीं, भी लाया था और आज मैं दुवारा ला रहा हूं कि अढ़ाई हजार रुपया नालियों के लिए क्यों देते हैं' । इसके ऊपर सरकार को विचार करना चाहिए । केवल इतना ही नहीं, डिप्टी स्पीकर साहिबा, जमींदार को कर्जा हू लेने के लिए शेयर भी खरीदने पड़ते हैं' । तौ इस तरह से वह लगभग दस हजार रुपये के कर्जे के नीचे आ जाता है सारे खर्चे को मिलाकर । इसलिए मैं तो यह कहना चाहता हूं .कि सरकार कौ इस सिस्टम को सिम्पलिफाइ करना चाहिए । जब महकमा कोआप्रेटिव का सरकार के पास मौजूद है तो इस पैसे को बजाय एक और एजेन्सी यानी

लैन्ड मौर्टगेज बैंक को देने के, स्टेटफारवर्डली कोआप्रेटिव बैंक को दे ना चाहिए । मौर्टगेज बैंक की इसमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आज हर जगह कुरप्शन चल रही है और इस से लोगों को जितना बचाया जासके बचाया जाना चाहिए । लैन्ड मौर्टगेज बैंक के, डिप्टी स्पीकर साहिबा, वे आदमी डायरैक्टर है जिनके पास ट्रैक्टर की एजैन्सियां है' । वे लोगो से रिश्वत लेकर ट्रैक्टर दिलाते हैं और इस तरीके से अपने बिजनैस को खूब चलाते डै' । तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा तो सरकार से यही सुझाव है कि उसे किसान को बजाय आठ हजार रुपया देने के केवल तीन हजार रुपया ही देना चाहिए क्योंकि एक ट्यूबवेल बड़ी आसानी से तीन हजार रुपये में लग जाता है । यह आठ हजार रुपये देकर किसान को हमें मारना नहीं चाहिए । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं सरकार से यह भी प्रार्थना करूंगा कि ट्यूबवेल लगाने के लिए सरकार को और ज्यादा पैसा जमींदारों को देना चाहिए । जब हम जमींदार से यह एक्सपैक्ट करते है' कि वह न सिर्फ हरियाणा के लिए बल्कि हिन्दुस्तान के लिए भी अनाज पैदा करें तो उसकी मदद करना सरकार का फर्ज है । अगर सरकार के पास पैसा न भी होतो वह गवर्नमैट आफ इंडिया से मांग सकती है यह कह कर कि हम आपको ज्यादा अनाज पैदा करके देते हुं इसलिए आप हमें किसान को ट्यूबवेल लगाने के लिए मदद देने के लिए पैसा दो ।

अब, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं ब्लाकों के सम्बन्ध में थोड़ी बात कहना चाहूंगा । डिप्टी स्पीकर साहिबा, पंचायत समिति आज एक मजाक बन चुकी हैं । वहां सरकार ने पांच पांच छः छः एग्रीकल्चर इन्स्पेक्टर दे रखे है लेकिन उनको काम कुछ नहीं है । अगर उनको कुछ काम देना चाहे तो चेयरमैन का उनके ऊपर कोई कन्ट्रोल नहीं है, पंचायत समिति का उनके ऊपर कोई कन्ट्रोल नहीं है । उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, एक्सप्लेनेशन काल नहीं फर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते और न ही उन्हें छुट्टी दे सकते हैं । उनको छी देने का भी डी. सी. को अख्तियार है । जब कभी दो दिन की छुट्टी आती है तो तीन दिन पहले चौथे दिन की छुट्टी की दरखास्त आ जाती हूँ क्योंकि चेयरमैन तो नहीं दे सकता, छुट्टी डी. सी. दे सकता है । इससे, डिप्टी स्पीकर साहिबा, उन लोगों को भी दिक्कत है और पंचायत समिति भी एक मजाक बनी हुई है क्योंकि इसके पास पावर ही कोई नहीं । इन सब बातों को कहने का, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा मतलब यह है कि कई जगह सरकार का पैसा फजूल जा रहा है जब इन लोगों के पास काम ही कुछ नहीं तो इसका मतलब यह नहीं कि इन्हें वहां नौकरी देने के लिए ही बैठा रखो, कुरप्शन करने के लिए बैठा रखी । कुरप्शन का तो मेरे पास रिकार्ड भी है । मेरे ब्लाक के एक ग्रामसेवक ने तो दरखास्त दी हुई है कि एग्रीकल्चर इन्स्पैक्टर दस्तखत तो फर्टिलाइजर के 15 कट्टों पर कराता है मगर देता 10 है मौके के ऊपर । तो मेरा तो तजूरूबे के बिना पर यह सुझाव है कि इन इन्स्पैस्टरों को हटा लेना चाहिए क्योंकि ये कुरप्शन के

सिवा कुछ नहीं करते । काम तो कुछ है नहीं मगर हैं पांच पांच एग्रीकल्चर इंस्पैक्टर, फिर उनके स्टोटे असिसटैन्ट बार इसी तरीके से और लोग । न कभी ये लोग दवाई छिड़कते हैं और न कोई और काम करते है' । हमेशा झूठी रिपोर्ट भेज देते हैं कि हमने फलां फलां काम किया । इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उसे इस दिशा में भी कुछ सोचना चाहिए ।

इसके बाद, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं मार्किटिंग सोसाटीज की तरफ हाउस का ध्यान दिलाना चाहता हूं । इनके बारे में तो मेरी अर्ज है कि मार्किटिंग सासाइटीज जो खोल रखी हैं ये कुछ आदमियों को पालने के लिए खोल रखी हैं । इनकी, मेरें ख्याल के मुताबिक कोई जरूरत नहीं है । ये जनता से बहुत फायदा उठाती 'है' । सरकार को चाहिए कि वे इन्हें खत्म करके चीनी और खाद आदि बांटने का काम अपने हाभ में ले ले । जो लाखों रुपये की आमदनी ये सोसाइटिया कमाती है इस तरह का कोई प्रबन्ध करने से सरकार की हो जाएगी । ये सोसाइटियां एक सौ रुपया एकड की जमीन को एक हजार में बेचती है' । खाद फजी मुंग से देती हैं । मगर फाइनेन्स मिनिस्टर साहिबा कहती हैं कि हमने पैदावार को बहुत बढ़ा दिया और बढ़ोतरी का कारण वे ज्यादा खाद का देना बताती हैं । मैं तो कहता हूं कि खाद को बांटने की जो फिगर्ज है वे सिर्फ कागजों में ही हैं और हकीकत कुछ और ही है । यदि में यह कहूं कि 100 फीसदी में से केवल 20 फीसदी खाद ही ठीक ढंग से तकसीम हुई है और 80 फीसदी

यू. पी. में, दिल्ली में या स्मंगलिंग द्वारा कहीं और गई है, तो इस बात को सच भाना जाए । इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और कोई न कोई कंट्रोल की बात होनी चाहिए । आज तो पुलिस भी और गवर्नमंट मशीनरी भी लाचार है क्योंकि खाद के बाहर ले जाने पर सरकार की ओर से कोई पाबन्दी नहीं लगाई गई है ।

अब मैं, डिप्टी स्पीकर साहिबा, हरिजनों के मुताल्लिक कुछ अर्ज करना चाहता हूं । डिप्टी स्पीकर साहिबा, यहां कहा जाता है कि हमने हरिजनों को बहुत रुपया दे दिया । लेकिन मैं तो इस ख्याल का हूं कि इस तरह से तो आप मरते हुए को और मारते हो । आज इनको जो जमीन खरीदने के लिए कर्जा दिया जाता है इसमें उनके साथ बड़ी ज्यादाती होती है । फिर जो जमीन इनको दी जाती है उसमें भी बड़ी गड़बड़ होती है । गुंडे लोग ऐसी ऐसी जमीन की जो कि जमुना के साथ लगती है, जिसमें पानी ही पानी होता है, ज्यादा बोली दे देते हैं । पांच पांच हजार किल्ला तक इस तरह की गन्दी जमीन जाती है । गरीब हरिजन भाइयों को इससे बड़ी मुसीबत का साभना करना पड़ता है । यही नहीं, डिप्टी स्पीकर साहिबा, जमीन को बिना देखे ही उसकी बोली हो जाती है । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि एक तो सरकार को इस बोली वाले ढंग को दूर करना चाहिए दूसरे जमीन दिखाकर देनी चाहिए । इसके अलावा मेरी सरकार से यह भी दरख्वास्त है कि जिस तरह से और लोगों को जमीन गिरवी रखने से कर्जा मिल जाता है उसी

तरह इन हरिजन भाईयों को भी ट्यूबवैल और बिजली आदि लगवाने के लिए कर्जा मिल जाना चाहिए चाहे उन्होंने जमीन के पूरे पैसे दे दिए हों या न दिए हों ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं आखिरी बात कह कर अपना स्थान लेता हूं । कुछ समय पहले श्री बनारसी दास गुप्ता जी कह रहे थे कि यहां पर अपोजीशन वाले नहीं हैं वरना बहुत कुछ कहना था । इसी प्रकार से कहना तो मैंने भी बहुत कुछ था, क्योंकि उन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा कि मैंने पार्टी छोड़ दी, यह किया, वह किया फाइनेन्स मिनिस्टर साहिबा ने इस बजट के आखिरी पैरा ह 3 में कहा है कि स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए । मैं भी मानता हूं कि स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए । लेकिन, डिप्टी स्पीकर साहिबा, ये अपोजीशन वाले मेरे साथी यहां हाउस में बड़ी स्पीचें देते हैं और जितनी स्पीचें देते हैं वे दूसरों के बारे में होती हैं अपने विषय में कुछ नहीं देखते कि हम क्या करते हैं । ये रात को दूसरे के घरों में घूमते है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपके सामने परसों का जिक्र करना चाहता हूं । परसों रात के डेढ़ बजे जिसको राव साहिव यूसफ कहते हैं अर्थात् श्री भगवत् दयाल शर्मा, मेरे एर पहुंचे और कहने लगे कि जिस वाज सन् 1960 में मैं प्रैजीडेन्ट बना था उस वक्त भी आपने मेरी सहायता की थी । क्योंकि सन् 1960 में दे ही एक ऐसा प्रदेश कांग्रेस का मेम्बर था जो डिफाल्टर नहीं था और तकरीबन सभी डिफाल्टर थे इसलिए मैंने ही उनका नाम कांग्रेस प्रैजीडेन्ट के लिए प्रपोज किया था और

वे प्रेजीडेन्ट बन गये । उस दिन भी वे मेरे पास रात के डेढ बजे ही पहुंचे थे और परसों भी डेढ बजे ही पहुंचे थे कि इस बार भी मेरा काम बन जाये— गा । वे कहने लगे कि पहली बातों को माफ कर दो आगे के लिए हम ठीक तरह से रहेंगे । मैंने उनसे कहा कि आपके पास तो कोई मेजोरिटी ही नहीं है । आपके साथ तो श्री जोगिन्द्र सिंह भी नहीं है । इस पर शर्मा जी ने जवाब दिया कि श्री जोगिन्द्र सिंह हमारे साथ है और उनको हमने खुद छिपा कर चीफ मिनिस्टर पर उसके उठाने का इल्जाम लगाया था । जिस तरीके से पंजाद भे बाबू वचन सिंह सन् 1962 के चुनाव में छुप गए थे और लोगों ने रहम करके उनको कामयाब बना दिया था इसी तरीके से जोगिन्द्र सिंह की कहानी से एम.एल.ए. साहिबान की हमदर्दी हमारे साथ हो जाएगी और हम सरकार को गिराने में सफल हों जाएंगे लेकिन ये यहां और बातें करते हैं । मेरे विषय में कहा गया कि कांग्रेस छोड़ दी, मैंने अपने विचारों के अनुसार ठीक छोड़ दी थी, क्योंकि उस समय कुछ ऐसे लोग थे जिनसे हमारे विचार नहीं मिलते थे । मेहता साहिब ने बहुत कुछ कहा कि मुझे कांग्रेस छोड़ते समय बड़ा दुःख हुआ । मैंने तीस साल तक कांग्रेस नहीं छोड़ी, मैंने इतनी सेवा की, लाठियां खायी, यह किया, वह किया । मैं उनको बता देना चाहता हूं कि उन्होंने जो तीस साल तक कांग्रेस की सेवा की हमने तो, हमारे खानदान ने तो चालीस साल तक कांग्रेस की सेवा की है । चालीस साल से कांग्रेस के वफादार रहे हैं हमारे भाई, बाप जेलों में गए। हम छोटे छोटे बच्चे होते थे सिकन्दर हैयात जैसे हमारे घरों के सामने डेढ

डेढ़ घन्टा हाथी के जलूस की शकल में खड़े रहते थे । बम्ब बनाने का बहाना ले कर हमारे घर की तलाशी ली जाती थी । कुर्वानियां तो हमने भी बहुत दी थी और कांग्रेस छोड़ते समय दुःख तो हमें भी हुआ था । उस वक्त हालात ये थे कि जो अंग्रेजों के पिछू थे उनको कांग्रेसी माना जाता था । हमने पुरानी तारीख से सबक नहीं सीखा जिस की वजह से आज दो पाकिस्तान बन गए । सयासी पार्टियों के आधार सबके अच्छे होते हैं' लेकिन पार्टी अच्छी बुरी उसके आदमियों के काम पर कहलाती है । इसी तरीके से हरियाणा में पास्ट में यहां की कांग्रेस के लीडर पं० भगवत दयाल बन गए । जिसने उस उम्मीदवार को कांग्रेसी माना जो खाह वह अंग्रेजों के पिछू भी थे लेकिन उसकी विरादरी के थे । और हमारे जैसे आदमी जो कांग्रेस में चालीस साल से शामिल रहे हों और उस वक्त से जब कि हरेक आदमी को अपने आपको कांग्रेसी कहने से डर भी लगता था, हमारा चुनाव में विरोध किया । अब वह जब कांग्रेस छोड़ गया तो हमने कांग्रेस को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, हमें न कोई मिनिस्टर बनने का लालच था और न किसी और चीज की आवश्यकता थी । अभी जैसा मैंने कहा कि परसों मेरे से. उन्होंने कहा कि तुम ही चीफ मिनिस्टर होंगे, तुम ही। मब कुछ होंगे । साथ साथ मैं यह भी बता दू कि आज से कोई डेढ़ महीना पहले भी हमारे पास कुछ जनसंघ के साथी और कुछ और भाई आये कि आप लछमन सिंह गिल वाली मिनिस्टरी बना नो हम आप को सपोर्ट करेंगे । मैंने कलियरली, साफ इलफाज में यह कह दिया कि दोस्तो आपको यह बहुम हूं



कि मैंने कांग्रेस मिनिस्ट्री के लालच में छोड़ी थी और अब मिनिस्ट्री के लालच में आपके साथ आ जाऊं । अब मैं कांग्रेस में आया हूँ तो कोई मिनिस्ट्री के लालच में नहीं आया हूँ, ईमानदारी से बिना के बिना लोभ के आया हूँ ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा यह रोजाना अपोजीशन वाले यहां डिफेक्टर का गाना गाते हैं । मैं उनको यहां चौलेन्ज से कहना चाहता हूँ कि मैंने 68 में इलैक्शन जो लड़ा वह इन्डीपेन्डेंट कैंडिडेट के रूप में लड़ा है । मेरा उस समय साईकल का निशान था । मैंने नामीनेशन पेपर जो भरा है वह इन्डीपेन्डेंट कैंडिडेट के रूप में भरा है । बेशक आप मेरा नामीनेशन पेपर निकलवा कर देख लें । मैं अब उन नौ लोगों को जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी यह चौलेन्ज करता हूँ कि वे भी इस्तीफा दे दें और मैं भी इस्तीफा दे देता हूँ देखते हैं वे कामयाब होते हैं या मैं कामयाब होता हूँ । मैं उनको दावे से कहता हूँ कि वे किसी भी सूरत से नहीं जीत सकते । मेरे दो पड़ौसी एम. एल. ए. पं० रामधारी और श्री कंवर सिंह दहिया हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी है अगर वह जीत कर आ जाएं तो मैं जीतने के बाद भी विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा । पं० रामधारी गौड़ ने चार घंटे के अन्दर अन्दर तीन दफा डिफेक्ट किया, क्योंकि वह तो दुबारा किसी भी हालत में बन ही नहीं सकता था । इसलिये यह जो बार बार डिफेक्टर का गाना गाते हैं यह ठीक नहीं है । राव बीरेन्द्र सिंह जी ने तो हमें पहले ही कह दिया है

कि मैं तो कांग्रेस में आ जाऊंगा पर इस एस.वी.डी. के लीडर को सिर से गिरा कर छोड़ दूँ फिर कांग्रेस में आऊंगा।

मेरे भाई चौधरी चान्द राम जी यहां पर कहते हैं कि मैंने तो कांग्रेस देख रखी है कहते हैं कि मैं तो पिछले इलैक्शन में टिकट देने वाला हूँ। तुम को मैंने टिकट दिया। यह सब उनकी भूल है। चौधरी चान्द राम जी तो सिर्फ मिनिस्टरी के ख्वाब देखते हैं। वे तो मिनि-स्टरी के बगैर जिन्दा नहीं रह सकते। मैं उनसे कहता हूँ कि वे भी इस्तीफा दे दें और नै भी दे देता हूँ देखते हैं कौन जीत कर आता है। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। आपका धन्यवाद जो आपने मुझे टाईम दिया।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक बात जो बहुत जरूरी थी वह एस० डी० ओज, इजीनियरज और वैटनरी के डाक्टरों की तनख्वाहों के शरे में थी। मैंने फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा को मेमोरेन्डम भी दिया है। उनका ख्याल रखा जाये।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, अभी चौधरी राम प्रकाश जी ने ..... नाम लिया था, सो कार्यवाही में उसका नाम नहीं आना चाहिए क्योंकि वह पर्सनल अटैक है। सो यह नाम एसक्यन्ज किया जाये।

**उपाध्यक्षा :** हां वह कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

**श्रीमती शारदा रानी कुंवर (बल्लभगढ) :** डिप्टी स्पीकर साहिबा, जनरल बजट पर बोलते हुए हमारे एक साथी ने कांग्रेस का नाम ले कर व्यंग्गात्मक भाव में यह कहा था कि कांग्रेस का तो सिद्धान्त

समाजवाद पर आधारित हूँ । मैं यह बताना चाहती हूँ कि वास्तव में कांग्रेस समाजवाद पर आधारित हूँ और इसी के अनुसार सारे काम हो रहे हैं—यह समाजवाद शुरू से अन्त तक दिखाई देता है । गवर्नर साहब का ऐड्रेस पेश हुआ और उसे मैंने पढ़ा और बजट भी देखा है उससे पता चलता है कि कांग्रेस समाजवाद के सिद्धान्त पर चल रही है । इस समय कांग्रेस जो कुछ कर रही है उससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि कांग्रेस समाजवाद लाने का प्रयत्न पूरी तरह से कर रही है । इसमें कोई शक नहीं । अगर यह बात न होती और सिद्धान्त विहीन आदमी यहां पर बैठ जाते तो शायद यह नहोता । लेकिन जब हम इस बजट को देखते हैं तो पता चलता है कि हमारी थोड़े ही काल से चल रही सरकार तेजी से समाजवाद के सिद्धान्तों पर चल रही है । शुरू शुरू में यह देखा गया कि सन् 1967 में जौ हालात इस प्रान्त के हुए उनमें प्रान्त के अन्दर मूल्यों में बढ़ोतरी हुई और वह 9 प्वायंट एक प्रतिशत के आधार पर वृद्धि हुई लेकिन 1968 में साल के अन्त तक 1 प्वायंट 8 परसेंट की कमी हुई है । तो इनसे भी पता चलता है कि समाजवाद की तरफ यह बड़ा कदम है । और सबसे बड़ी खूबी इस बजट की यह है कि किसी प्रकार के टैक्स नहीं लगाए गए । पिछला बजट अगर देखा जाए तो पता चलेगा कि वह 8 करोड़ के घाटे का था लेकिन इस साल सिर्फ 5 प्वायंट 10 करोड़ का ही घाटा रह गया है । मैडम, यह जो नई स्टेट बनी है उसका मुख्य धंधा कृषि है । इसको बढ़ाना समाजवाद की ओर एक बड़ा कदम है कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जहां सब

ओर से प्रयत्न हो रहे हैं वहां हरियाणा के अन्दर कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना की जा रही है वह बहुत बड़ा कदम है । जैसा कि मैंने अभी कहा कि प्रदेश की जनता अधिकतर कृषि करती है तो उनके लड़के इस विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे और अपनी खेती को वै जिन तरीके से करेंगे । इस बजट में मैंने देखा है कि इसके अन्दर कृषि पर जो पूजीगत व्यय है उसका 2 तिहाई भाग सिंचाई के ऊपर रखा गया है, जो कि इस प्रदेश की साधारण जनता को आगे बढ़ाने में सहायता देगा । मैडम, यह भी सभी जानते हैं कि हरियाणा में स्त्रियों की शिक्षा काफी पीछे है । इसका कारण यह है किस्ती शिक्षा को कभी प्रोत्साहन नहीं मिला । मगर अब इस बजट में महिला शिक्षा के लिए प्रोवीजन रखा गया है और 1 प्वायंट 9 करोड़ की राशि महिला स्कुल्ज और 7 प्वायंट पांच लाख रुपए की राशि महिला टैक्नोकल कालेज पर खर्च को जाएगी । यह बड़े संतोष की बात है । यह हरियाणा के अन्दर पहली चीज है । इससे पूर्व कभी ऐसी बात नहीं हुई । पिछले साल 1967- 68 में बहुत सा रुपया ऐसे स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए लगा दिया गया था जहां न तो जगह थी और न ही लड़कियां या लड़के होते थे । जो कुछ स्वारल अपग्रेड किए गए थे उनका आधार राजनीति था । और यह सोचा गया था कि लोग उन्हें इलैक्शन में जिताएंगे । इस साल 74 स्कूलों को अपग्रेड किए जाने की योजना दी गई है और इससे भी ज्यादा किरार जाएंगे यह बहुत अच्छी बात है । 1967 में लड़कों की फीस को लागू कर दिया गया था ले किंन अब इस सरकार ने फीसो को

माफ कर दिया है बैकवर्ड एरियाज के लिए और हरिजनों के बच्चों की शिक्षा को वजीफों आदि से और अधिक प्रोत्साहित किया है । सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो एक और कदम उठाया है, वह हाई स्कूल की शिक्षा के लिए एक बोर्ड स्थापित किया है । हमें इस मामले में दूसरों पर निर्भर करना पड़ता था और जैसी शिक्षा हमें चाहिए थी वैसी शिक्षा नहीं मिलती थी । तौ जिन चीजों की हमारे प्रान्त को जरूरत है उन बातों को पूरा करना समाजवाद की ओर बहुत बड़ा कदम है ।

इसके बाद हरिजनों को मकान बनाने के लिए, उनके उद्योगों को तरक्की देने के लिए और सामाजिक सुविधाएं देने के लिए 25, 20 और 34 लाख रुपया रखा गया है । यही नहीं, मैडम, चिकित्सा के क्षेत्र में भी सुविधाएं दी जा रही हैं । यह तो सभी को मालूम है कि हमारा प्र बहुत पिछड़ा हुआ है । हमारे पास हास्पिटल नहीं हैं और दे हात में डाक्टर इसलिए नहीं जाते कि उनकी सुविधाएं शहरों जैसी नहीं मिलती । इसलिए इस दिशा में सुविधाएं देना और डाक्टरों को देहात ने भेजना जरूरी थ । कह प्रोविजन इस बजट में रखा गया है और यह मैं ' समझती हू कि यह बड़ा महत्वपूर्ण कदम है ।

पिछले बजट मे 1 करोड़ रुपया सड़कों के लिए रखा गया था । अब इसको बढ़ा कर 2 प्वायंट 10 करोड़ कर दिया गया है । आज कल भी इस दिशा में सड़कों का जो निर्माण हो रहा है वह किसी से छिपा नहीं है । सड़कों का तेजी से निर्माण होना बहुत

आवश्यक इसलिए भी है कि ग्रामीण और शहरी जीवन की दूरी खत्म हो जाएगी । मैडम, इतना सब कुछ तो हुआ है मगर मैं गवर्नर मेट से निवेदन करना चाहूँगी कि जो भी रुपया बजट में रखा गया है और जिन जिन मदों के लिए रखा गया है उसका उपयोग बढ़ा सही और तेजी से होना चाहिए ।

1967 में गुड़गांव कैनल का निर्माण किया गया था उसके लिए बड़ी भारी राशि रखी गई थी और बड़ा शोर था क नहर बन जाने पर इतने भारी क्षेत्र को सैराब करेगी और यह होगा वह होगा लेकिन वह ऐसी नहर बनी कि बरसात में कट गई और रुपया बर्बाद गया । मुझे मालूम है उसके बनने में समिट एं वगैरह में जो ब्लैक और चोरबाजारी हुई उसकी हद नहीं रही । और जनता के किसी आदमी ने कोई शिकायत भी करनी चाही तो उसे सुना नहीं गया । तो मेरा निवेदन है अपनी गवर्नरमेट से कि अब इस तरह की चीजें न चलने दी जाएं । वहां पर कुछ आफिसरज ए से भी गए थे, जिन्होंने इस घोटाले को रहस्योदघाटन किया था मगर उनकी वहां से ट्रांसफर करके इस चीज को प्रोत्साहन दिया गया था । मैं जानती हू कि अगर अच्छे और ईमानदार अफसर रुपये का ठीक से उपयोग करेंगे तो हरियाणा जल्दी तरक्की करेगा ।

जहां हरियाणा में कई जगहों पर काम हो रहा है, वहां कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो अच्छे पड़े हैं । बीर उनके लिए इस बजट में कोई प्रोवीजन नहीं है इसी प्रकार का मेरा क्षेत्र बल्लबगद है जहां पर कई गांव 1 5— 15 और 20—20 की तादाद में ऐसी जगह बाके हैं

जहां पानी भर जाता और आवाजाई खत्म हो जाती है । जब चारों तरफ पानी खड़ा हो जाता है तो चिकित्सा की कोई सुविधा वहां नहीं होती है । जिस तरह पिछड़े इलाकों में सिंचाई बिजली सड़कों आदि की सुविधायें दी जाती हैं और वहां का विशेष ध्यान रखा जाता है वैसे चाहे बड़ी योजना या छोटी योजना बना कर उन लोगों को भी जो पानी से धिरे रहते हैं इस तरह का सहारा दिया जाए । जहां पानी घुसता है वहां बांध बांधें जाएं और बिजली, सड़कों और चिकित्सा आदि की सुविधाएं दी जाएं । अगर अभी इतना पैसा नहीं है कि अभी ही जमुना पर पुल बना कर दूसरे इलाके से कुनैक्ट कर सके तो इतना तो कर सकते हैं कि उन सारे गांव को आपस में कुनैक्ट कर दें ।

इरीगेशन की जो हमारी स्कीमें हैं इस में शक नहीं कि वह चल रही हैं और काम जारी है लेकिन उन में जो कमियां हैं वह बरदाश्त के काबिल नहीं हैं । बहुत से माइनर्ज बने हैं लेकिन उन में पानी नहीं जा रहा है और अगर कहीं पानी जाता है तो जिन इलाकों के लिये पानी जाना चाहिए वहां वहां मिलता नहीं है । इसके साथ साथ माइनर्ज के आस पास जो रास्ते होते हैं उन के लिये पुल नहीं बनाये जाते और न कोई पक्का रास्ता दिया जाता है । रास्तों पर पुल न होने की वजह से लोग बहुत परेशान हैं और बहुत तकलीफ में है' । वह जो माइनर या नहर बनती है तो उसके एक तरफ घर रह जाते हैं और खेत जमीन दूसरी तरफ होते हैं । अपने घरों से जमीन पर काम करने केलिये जाने में

लोगों को रास्तों पर पुल न होने की वजह से कई कई मीरा का चक्कर लगा कर जाना पड़ता है । उनका बहुत समय नष्ट होता है और बहुत असुविधा होती है, बैल भी मरते हैं, और वह भी उतना ऐफीशेटली खेती का काम नहीं कर सकते हैं जितना करना चाहिए । फिर हमारे यहां पीने के पानी की भी समस्या थी । मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जहां पानी खारा है और जहां सिंचाई के लिये ट्यूबवैल्ज नहीं लग सकते हैं वहां पर इन माइनर्ज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए और पीने के पानी की योजनायें लागू करनी चाहिए ।

हमारी तरफ उस इलाके में टारुन एंड कटरी प्लानिंग का काम चल रहा है और लोगों को जमीने ले कर प्लॉट बना कर शहरों से आने वाले लोगों को दिए जाते हैं । बड़ी सुन्दर बात है शहर से आने वालों को मकान बनाने के लिए जगह देनी चाहिए लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं कि वह प्लॉट बिक नहीं रहे हैं इसके बावजूद भी और जमीन एक्वायर की जा रही है । जमुना में जो गांव बह गए हैं उन गांवों के रहने वालों को अभी तक जमीन का एक चप्पा भी नहीं मिला है और वह खानाबदोशों की तरह फिर रहे हैं । जिधर वह जाते हैं लोग उधर से उन को हटा देते हैं । उनकी तरफ शीघ्र ध्यान दिया जाए और उनको जमीन दी जाए ।

**उपाध्यक्षा :** आप का टाइम हो गया है इस लिये आप बैठ जाएं ।



सूबेदार प्रभु सिंह (बवानी खेड़ा, एस.सी. ) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपकी मारफत इस सरकारके नोटिस मै कुछ जरूरी बातें लाना चाहता हूं । पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो बजट फाइनेंस मिनिस्टर साहिबाने पेश किया है यह शानदार भी है और जानदार भी है, बीच से खोखला भी नहीं जैसे कि पिछली भगौड़ी सरकार ने बनाया था (विघ्न ) । ईमानदारी की बात तो बाद में आती है और वह बजट की इम्प्लीमेंटेशन के बाद अगले सेशन में कहूंगा और इसके बरतने के बाद कहूंगा कि ईमानदार है, या नहीं । गुप्ताजी ने अपना भाषण शुरू करते ही कहा था और मेरी नजर भी उधर ही जाती है लेकिन बात कुछ समझ में नहीं आती । खैर कुछ भी हो और वह जहां कहीं भी हों उन लोगों की तसवीर हमारे दिल में है । जिन्होंने हरियाणा के साथ गुनाहों का तमाशा दिखा कर जो तरीका अख्तियार किया वही हम भूल नहीं सकते । हम ने यहां तक तो नहीं कहा था कि भाग ही जाओ और इस बारे में एक शेर कहता हूं रु --

जनाजा रोक कर मेरा वह किस अंदाज से बोले,

हम ने कहा था गली छोड़ो वह दुनियां छोड़े जा रहे हूँ ।

मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम ने तो कहा था कि गुनाहों के बदले कुछ बातें तो मुन जाओ और अगर गुनाह करते हो तो कुछ सुनते तो जाते । मैं इस वजट को जानदार और शानदार कहता हूं । मैं विस्तार से नहीं कहूंगा कुछ व्यवस्था की बातें कहूंगा ।

सरकार की नीयत भी है, सरकार करना भी चाहती है, दिल में दर्द भी है और दिमाग से सोचती भी है लेकिन व्यवस्था में क्या कमियां है उस बारे में चंद तजवी जे रखूंगा और यह बातें मैं इस ख्याल से नहीं कहता कि मुझे बोलने का शौक है बल्कि मेरे दिल में दर्द है और दिमाग में वे चौनी है और दिल में तस्वीर है । मैं ' सरकार से कहना चाहता हूं और हरेक एम० एल० ए० से जो यहां आज हाउस में है कहना चाहता हूं कि उस वक्त जो आप इलैक्शन में वायदे करते हो उनको यहां आ कर भूलना नहीं चाहिए । मैं उन मैबरान के बधाई देता हूं जो यहां बोले है' कि उन्होंने जो वायदे किगु थे हरिजनों के साथ उनको वह भूले नहीं हूँ ' और उनका जिकर यहां उन्होंने किया है । लेकिन जो व्यवस्था में कमियां है ' वह मे ' बताना चाहता हूं और कोई भाषण नहीं कर रहा हूं । बजट में घाटा बताया गया है । यह घाटा क्यों है इस के बारे में मैं दो मिनट लूंगा । मैं बहिन जी को बताना चाहता हूं कि बजट में घाटे का कारण ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन की कुरप्शन, अफसरों को बेइमानी और बढ़यानती नहीं है बल्कि मैं ' कहना चाहता हूं कि यह जो एम० एल० एज० और मंत्री होते हैं' उन के अनड्यू इनपलूएंस से दौलत को गबन और गायब किया जाता हूँ इस बारे में कृरछ मिसालें भी देना चाहता हूं । यह एक झज्जर कोआप्रेटिव लेबर ऐड कंस्ट्रकशन सोसाइटी झज्जर है । यह सोसाइटी 6-1-53 को रजिस्टर हुई और इस में 2,10,354 रुपया गवन हुआ है । The society is under liquidation. but hte records are not handed over to the liquidator. इस में एक एम०

एल ० ए ० का अन ड्यू इनफ्लूएंस है जिसकी वजह से यह गबन हुआ है । आप देखें कि सोसाइटी का लिक्विडेटर मुकर्रर हो चुका है उस में 50 हज का गबन हौ और एक एम ० एल ० ए ० रिकार्ड न दिखाता द तो बजट को घ नहीं पड़ेगा तो और क्या होगा बहिन जी आपके वजट में कुछ वजीर और एम ० एल ० एज० घाटा बनाए बैठे है , आप इन को सम्भालो । मैं कहता हूं क अगर आप पांच रुपये के चोर को दो दो साल की सजा देते है ' तो जिन एम ० एल ० एज ० ने दो दो लाख के गबन किए हुए हैं और करते हैं उनके लिये भी तो कोई कानून आप के पास होगा, कोई ताजीरातेहिन्द की दफा होगी । अगर उन को नहीं सम्भालोगे तौ यह डैमोक्रेसी नहीं चल सकेगी और आपका यह निजाम नही चल सकेगा ।

**वित्त मन्त्री :** जरा बात साफ कर दे कि क्या है और कौन है ।

**सुबेदार प्रभु सिंह:** असल मे यह रुपया लोगों को पेमेंट नहीं किया गया, यत्र चीतटंग किया गया है । मै सरकार मे दरख्वास्त करता हूं कि जिन लोगों ने यह गबन किया है उन्हें दफा 409 आई ० पी ० सी ० ताजीराते हिन्द के तहत मजा दिलवाये, चाहे ' आप अपने वकील से पूछे लेकिन इन्हें जेल जरुर भिजवाये ।

इसके इलावा रोहतक कोआप्रेटिव लेवर एंड कंस्ट्रक्शन सोसाइटी लिमिटेड, रोहतक में एक लाख, 82 हजार 713 रुपया मिसऐप्रोप्रिएट हुआ । नम्बर तीन पर आती है रोहतक डिस्ट्रिकट

कोआप्रेटिव लैदर एंड टेर्निंग विलेज इंडस्ट्रीज डिवैल्पमेट लिमिटेड, खरखोदा । यह सोसाइटी 14- 5- 1953 को रजिस्टर हुई थी । इस सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट ने 26 हजार रुपये की सबसिडी दी थी । इसके खिलाफ भी Enquiry has been ordered under Section 50 but the records not produced. इसके रिकार्ड को खत्म कर दिया गया । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मे' सरकार को बताना चाहता हूं कि यह रिकार्ड की चीज है, जबानी बात नहीं करता, यह किसी के ऊपर गतनत इल्जाम नहीं है । जब आर्डर होते हैं कि रिकार्ड पेश करो तो रिकार्ड पेश नहीं होता । न एस ० पी ० को दिखाया जाता है न डी ० सी ० को दिखाया जाता है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, ला-एड-आर्डर की व्यवस्था ठीक करने के लिए मैं सरकार से अर्ज करना चाहता हूं कि इस किस्म के बे-लगाम बेईमान लोगों को माफ न किया जाये ताकि दूसरे लोगों को यह पता चले क सरकार ने गबन करने वाले एम ० एल ० एज० और वजीरो को सजा दी है और सजा दे ने की हिम्मत करती है ।

**वित्त मन्त्री :** ये मौजूदा वजीर हैं या एक्स-वजीर है'?

**सूबेदार प्रभु सिंह :** ये एक्स वजीर है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, नम्बर चार पर आती है झज्जर हरिजन कोआप्रेटिव कुलैक्टिव फार्मिंग सोसाइटी लिमिटेड, झज्जर, डिस्ट्रिक्ट रोहतक । इस सोसाइटी ने हरिजनों के नाम पर जमीनती और गवर्नमेंट ने उन्हें रुपया दिया । गवर्नमेंट ने हरिजनों के लिये तो बहुत कुछ किया

और हरिजनों को, जिनकी हालत बहुत खराब थी, जमीन से उठाकर आसमान पर रख दिया हूँ लेकिन सोसायटियों वालों ने सारे का सारा पैसा गबन कर लिया । डिप्टी स्पीकर साहिबा, पिछली सरकार ने 14 रुपये से 40 रुपये बीघे तक लगान लिया । आज तक किसी लैंड ओनर ने इतना महंगा लगान हरिजनों से नहीं लिया, मैं उस चीज को दावे के साथ कह सकता हूँ ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, रवीदास होस्टल, रोहतक ( फौरमरली नोन ऐज चमार होस्टल, रोहतक ) रवीदास नगर, रोहतक, जिस वक्त बना तो इसके लिये लाखों रुपये की ग्रांट गवर्नमेंट से ली गई, और लाखों रुपया जनता से लिये, लेकिन जब हिसाब मांगा तो हिसाब पेश ही नहीं किया जाता । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपकी मारफत सरकार से जानना चाहता हूँ कि इन चीजों को रोकने के लिये सरकार के पास इलाज है? जो लोग पब्लिक मनी को बरबाद कर रहे हैं उनके लिये कोई कायदा-कानून बनाएं ।

इसके बाद एक इंस्टीच्यूशन हरिजन शिक्षा प्रचारिणी सभा, रवीदास नगर, रोहतक है, उसमें भी लाखों रुपये का गबन है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, यहां पर 18 किस्म के ड्रामें खेले गये और उन 18 किस्म के ड्रामों में खुद रांझा है' चौधरी चान्द राम । जितनी भी सोसाइटिया हैं उन सब के प्रैजिडेंट चौधरी चान्द राम हैं । उनका साला मैम्बर है, बहनोई मैम्बर है.

**चौधरी रणवीर सिंह** : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आनरेबल मैम्बर का नाम न लिया जाये तो अच्छा है ।

**सूबेदार प्रभु सिंह** : अगर उनका नाम भी न लिया जाये तो भी रुस सारी दास्तां को आप लोग जानते हैं और समझते हैं । वे खुद इस हाउस के मैम्बर हैं, मैं उनका नाम ले सकता हूं । वे तो चेयरमैन हैं (व्यवधान ) डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन चार सोसाइटियों पर लिक्वीडेटर मुकर्रर हो चुका है लेकिन कागजात दिखाये नहीं जाते, छुपा लिए गए हैं । अगर ऐसे एक एमएल० ए० की इन्क्वायरी कर ली जाये तो बजट का काफी घाटा पूरा हो सकता है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं येम चारों केस हाउस की टेबल पर पेश करता हूं ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक और ऐसा ही एम० एल० ए० है नाम लेने की तो आपने मनाही कर दी है वे पहले मिनिस्टर थे उन्होने गोहाना लेबर कोआप्रेटिव सोसाइटी लिमिटेड, गोहाना (डिस्ट्रिक्ट रोहतक ) सोसाइटी बनाई थी । यह सोसाइटी 24 जनवरी, 1953 को रजिस्टर हुई थी, इसके 25 मेम्बर थे । इस सोसाइटी में 59055.52 रुपये का काम हुआ था और इसमें तीन लाख रुपये का फायदा हुआ । लेकिन इस का कोई हिसाब पेश नहीं किया गया, बोगस रसीदें लगा दी गई । किसी मेम्बर को उसका ड्यू शेयररु नहीं दिया गया । इस सोसाइटी के कागजात भी मैं हाउस की टेबल पर रखता हूं । एक आवाज रु उस आदमी का नाम ले लें ।

**सूबेदार प्रभु सिंह :** यह वह आदमी हूँ जिसको हार्ट अटैक हो जाता हूँ, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ ।

**उपाध्यक्षा :** क्या किसी ने इस किसम की कोई शिकायत की है या आप ही कह रहे हैं'?

**सूबेदार प्रभु सिंह :** डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया है । जिन हरिजनों के साथ यह जुल्म हुआ है वे चिल्लाते हैं, उनका कत्लेआम हुआ है और सारे हरिजन रो रहे हैं । यह तो मैं ने आपको गबन की बात बताई हूँ कि सरकारी व्यवस्था में इस तरह की कमी क्यों है । अगर सरकार एक्स एम० एल० एज० की जांच पड़ताल करे तो छरू करोड़ रुपये का जो घाटा है वह पूरा हो सकता है । उपाध्यक्षा रू जो कुछ आप कह रहे हैं इस में सारे एम० एल० एज० हैं या वे हैं जिनके बारे आपने शिकायत की है?

**सूबेदार प्रभु सिंह :** इसमें वही एम० एल० एज० शामिल हैं जिनके खिलाफ शिकायत है । अगर ये एम० एल० एज० मेरे खिलाफ शिकायत करेंगे तो ये चेलेंज कर सकते हैं । अब डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं दूसरी तरफ आता हूँ । सरकार ने हरिजनों के लिए सर्विस में 21 परसैट रिजर्वेशन रखी थी लेकिन उस 12 परसैट रिजर्वेशन में से पिछले 17 सालों में केवल तीन या साढ़े तीन परसैट ही सर्विस में हरिजनों का नम्बर आया है । मैं कहना चाहता हूँ कि 17 सालों में सिर्फ तीन परसैट रिजर्वेशन दी गई तो

21 परसैटं रिजर्वेशन कितने सालो मे पूरी होगी? इसका हिसाब आप लगा सकते हैं । जब सरकार ने 21 परसैटं रिजर्वेशन हमें दी हुई है उसकी क्यों क्यों नहीं किया जाता । पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने जब लोग जाते है' तो उन्हे डिसक्वालिफाई करके नान-हरियाणवी लोगों को ले लिया जाता है । इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि नान-हरियाणवी की जगह हरिजनों को लिया जाये ताकि कोई फेवरेटीजम या नेपोटिजम न हो ।

अब मैं ट्रांसपोर्ट कोआप्रीटव सोसाइटियों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । हरियाणा में जितनी ट्रांसपोर्ट कोआप्रेटिव सोसाइटियां है उन में किसी हरिजन के पास कोई रूट परमिट नहीं है । सरकार हरिजनों को जुतिगां बनाने के' लिए कर्जा देती है अगर रट परमिट दे दे तो इनकी व्यापार की तरफ भी रुचि होगी और तरक्की होगी। लेकिन हरिजनों को व्यापार करने का मौका ही नहीं दिया जाता । इनको व्यापार की तरफ भी हाथ बढ़ाने का मौका दिया जाना चाहिए । मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सारे हरियाणा में एक भी हरिजन के पास रूट परमिट नहीं है ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसके अलावा एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं । वजीफे जो स्कूलों में मिलते हैं वे देर से मिलते है' । अगर इसको मंथली कर दिया जाए तो मां बाप के सिर पर बोझ नहीं रहेगा । आज यह होता है कि साल के आखिर में वजीफे



दिस जाते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं । मां बाप के पास साधन न होने के कारण एक तो बच्चे स्कूलों में पढ़ ही नहीं पाते और यदि पढ़ते हैं तो फेल हो जाते हैं । इसलिए मेरा सुझाव है कि इन वजीफों को साल के अखीर में बजाय हर महीने देने का इन्तजाम किया जाना चाहिए ।

इसके अलावा एक और तजवीज मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूँ । गवर्नमेन्ट जो कंट्रेक्टर से काम करवाती है उसे लेबर को आप्रेटिव सोसाइटी के थ्रू करवाया जाना चाहिए क्योंकि यह गवर्नमेन्ट और मजदूर के बीच एक फजूल की एजैसी है । शडियूल के मुताबिक यदि 30 रुपये हजार क्यूबिक फुट के हिसाब रो मिट्टी का काम होता है तो कंट्रक्टर लेबर को 20 रुपये हजार के हिसाब से पेमेंट करता है । बाकी पैसे स्वयं खा जाता है । इसलिए सरकार और मजदूर के बीच जो कंट्रक्टर इस तरह से फायदा उठाता है उसे हटाया जाना चाहिए और सारा काज लेबर को आप्रेटिव सोसाइटी के थ्रू करवाकर मजदूर को पूरी मजदूरी दी जानी चाहिए क्योंकि काम तो वह करता है ।

अब अगली बात में गुजारों की वैलफेयर से सम्बन्ध रखने बाजी कहूंगा । आज मुजारों को बड़ी चालाकी से और गलत ढंग से बेदखल किया जाता है । जमींदार या मालिक बटाई तो ले लैते हैं मगर चालाकी से रसीद नहीं और फजूल ही मुखारे को तंग करते रहते हैं । मुजारा जब कोर्ट में जाता है तो रैवेन्यू अफसर कहता है कि रसीद पेश करो । रसीद होती नहीं और डिक्री शोक

नौनपेमेंट के बिना पर मुजारे को बेदखल होना पड़ता है । तो मेरी सरकार से प्रार्थना है कि ऐसी बेदखलियों को रोका जाए । सिक्थोरिटी आफ टैनेन्ट ऐक्ट जो लचकीला है उसकी मजबूत किया जाए । जो डिसपैरेटी है उसको खत्म किया जाए और जो गुनाहगार हों उसको सजा दी जाए । आज तो गुनाह करता है पटवारी और सता होती है टैनेन्ट को । यह जो दो लोटे दूध और दो सेर घी से गिरदावरी गलत होती है, इसे रोका जाए ।

**चौधरी नेकी राम :** अब मात्रा कुछ ज्यादा हों गई है ।

**सुबेदार प्रभु सिंह :** शायद ज्यादा लेते हों क्योंकि महंगाई हो गई है । खैर डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अर्ज कर रहा था कि जमींदारों से, मालिकों से पैसा लेकर, रिश्वत लेकर गिरदावरी गलत की जाती है । वास्तव में जो टैनेन्ट होता है उसे तंग किया जाता है । इसमें, डिप्टी स्पीकर साहिबा बड़े अफसोस को बात तो यद्दु है कि टैनेन्ट को तो इस तरह से हैरास किया जाता है मगर जब तहसील में जाकर फैसला उसके हक में होता है तो पटवारी को कोई सजा नहीं मिलती । मे चाहूंगा कि जो पटवारी गलत इन्द्राज करे या कोर्ट से जब साबित हो जाए कि फलां पटवारी ने गलत इन्द्राज किए थे तो उस पटवारी को डिसमिस किया जाए ताकि और पटवारी भी दो लोटे दूध और दो सेर घी लेकर गिरदावरी गलत न कर सके । डिप्टी स्पीकर साहिबा, यहां इंडस्ट्रीज का जिक्र आया । इसके बारे में बहिन ओम प्रभा जी ने कहा था कि सरकार ने छोटे तथा बड़े उद्योगों के मालिकों को बड़ी रियायतें

दी हैं । बहुत अच्छी बात हूँ क्योंकि व्यापार इससे बढ़ेगा । मगर हरिजन या बैकवर्ड क्लासिज के आदमी अगर आज भी दो हजार से ज्यादा कर्जा लेना चाहें तो उनके लिये आज भी वही शर्तें हैं जो पहले हुआ करती थीं कि उसको तीन हजार का लोन लेने के लिये 6 हजार के दो जमानती देने पड़ेंगे । इस बारे में, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं सरकार से ज्यादा नहीं चाहता मगर यह जरूर प्रार्थना करता हूँ कि इन शर्तों को नर्म किया जाए ताकि गरीब आदमी बिना किसी दिक्कत के दस्तकारी का कोई कंधा शुरू कर सकें ।

एक बात, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं और कहना चाहूंगा और मैं आपसे रिक्वैस्ट भी करूंगा क्योंकि मैं एक सांझी बात कर रहा हूँ, कि इस घंटी पर आप हाथ न मारना क्योंकि यदि आपने हाथ लगा दिया तो मैं भूल जाऊंगा । मैं खुद ही बैठ जाऊंगा । ( हंसी )

**उपाध्यक्षा :** मैं तौ अभी चुप बैठी हूँ ।

**सूबेदार प्रभु सिंह :** आप जरा ऊपर उठीं थीं । मैंने समझा कि कहीं हाथ ऊपर चला गया तो सारा काम खराब हो जाएगा । (हंसी ) खैर, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं एक बहुत जरूरी बात अब सरकार से कहना चाहूंगा । आप जानती हैं कि रीमूवल आफ अनटचेबिलिटी ऐक्ट बन गया है । कोई तजवीज नहीं है, रूल भी नहीं है, ऐक्ट बन गया है रीमूवल ओफ अनटचेबिलिटी ऐक्ट और उसकी बातों का ना मानना कौंगनिजेबल औफैन्स है, नौन—

कौगनिजेबल भी नहीं है, मगर मैं सरकार से आपके द्वारा जानना चाहता हूँ कि आज तक क्या सारे हरियाणे में एक भी आदमी के साथ छूतछात नहीं की गई जो आज तक एक केस भी रजिस्टर नहीं हुआ? इस तरह से ऐक्ट को बलाए ताक रखना आवाम के ऊपर बुरा असर डालता है । वे यह सोचने लग जाते हैं कि ऐक्ट नाम की चीज को अगर वे चलाना चाहे तो वह चल सकती है और अगर न चलाना चाहे तो नहीं चल सकती । तो मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह इस ओर ध्यान दे और सारे एम ० एल० एज० साहिबान से गुजारिश है कि वे अपने अपने हल्के में जाकर रीमवूल ओफ अन-टचेबिलिटी के खिलाफ पूरे जोर से आवाज उठाएं.....

**चौधरी जगदिश चन्द्र :** डिप्टी स्पीकर साहिबा, आन ए प्यायंट आफ क्लैरिफिकेशन । मैं ओनरेबल मैम्बर से पूछना चाहता हूँ कि क्या केस का रजिस्टर होना जरूरी बात है? मैं तो समझता हूँ कि हरियाणा के लोग इतने सयाने हो गए हैं कि वे इस किस्म का केस बनाने को जरूरत ही नहीं समझते ।

**उपाध्यक्षा :** मैं भी सूबेदार साहिब की इफर्मेशन के लिये एक बात कहना चाहती हूँ वडु यह कि अभी तक किसी हरिजन ने जब शिकायत ही नहीं की कि उसके साथ छुआछूत की गई है तो केस कैसे रजिस्टर होता?

**सूबेदार प्रभु सिंह :** डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं यही कह सकता हूँ कि ये मेरे बुर्जुग है, बड़े पुराने मैम्बर हैं और मैं इनकी इज्जत

करता हूँ । आपने भी जो कहा सो ठीक है । गवर्नमेंट का इसमें कसूर नहीं है । लेकिन वहिन जी मेरी तो सब भाईयों से और जनता से यही अपील है कि अगर मुल्क को मजबूत रखना है तो छुआछुत को हटाना होगा, इसे सही मायनों में दूर करने के लिये हमें लग जाना चाहिए ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक और बात मुझे हरिजनों की याद आ गई । कस्टोडियन लैन्ड जो सरकार ने खरीदी पैकेज डील में गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया से वह केवल 37 रुपये एकड़ के हिसाब से खरीदी थी मगर उसे, अफसोस की बात है, 37 रुपये एकड़ खरीदने के पश्चात् दो हजार, तीन हजार रुपये एकड़ तक ओपन औक्शन में बेचा गया । डिप्टी स्पीकर साहिबा. इतना नफा जिस समाज से लिया जाए वह कैसे ऊपर उठ सकता है? परन्तु फिर भी अगर अब कुछ और नहीं हो सकता, क्योंकि कागजात में वे कर्जदार बन चुके हैं, लिखा पढ़ी तो चुकी है, तो कम से कम सरकार को यह चाहिए कि जो 6 परसेन्ट के हिसाब से सूद हरिजनों को जिन्दा रखने के लिए लिया जाता है उसे हरिजनों को जिन्दा रखने के लिये, हरिजनों को बचाने के लिये छोड़ दिया जाना चाहिए ताकि वे सुख की सांस लें । यह मेरी पुरजोर अपील है अपनी कांग्रेस सरकार से और बहिन ओम प्रभा जैन जी से । पहले भी, डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारी कांग्रेस ने जब कस्टोडियन लैन्ड के लिये रिस्ट्रिक्टेड सेल रखी थी तो भाव चार सी रुपये स्टैंडर्ड एकड़ रखा था मगर बीच में एक रावण सरकार आई

जिसमें चन्द्र सरकार का भी हाथ था । चन्द्र सरकार में इसलिये कहता हूँ कि जिस फाईल से साढ़े चार सौ से नौ सौ रुपये तक इस लैण्ड को बेचने के आर्डर हुए थे उस पर मेरे उस भाई ने दस्तखत किए हुए हैं जी हरिजनों के ठेकेदार बनते फिरने हैं । ( विधन ) मेरे दिल में अपने इस दोस्त के लिये दर्द है, उसके काम से नफरत है उसकी शकल से नहीं । तो मैं अपनी इस सरकार से प्रार्थना करूंगा कि यह अपनी पहली कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए फैसले की तरह कि साढ़े चार सौ रुपये स्टैण्डर्ड एकड़ के हिसाब से कस्टोडियन लैण्ड को बेचा जाएगा, फैसला करे तथा हरिजन भाईयों की दुआएं हासिल करे । मैं तो समझता हूँ कि इस सरकार के दिल में हरिजनों के लिये बड़ा दर्द है और इस से अच्छी सरकार न आगे आएगी और न पहले आई थी । लेकिन यदि सरकार अपने से पहले वाली सरकार के फैसले की खिलाफ-वजी करके इस फँसते को भी कर दे तो हरिजन भाईयों के दिल में जरूर यह ख्याल और पक्का हो जाएगा कि जिस कांग्रेस पार्टी को हमने वोट दिया है, जिस पार्टी ने हमें जिन्दा किया है, जिस पार्टी ने जूते बनाने वाले मोची को ऊंचे से ऊंचे ओहदे तक पहुंचाया है, जिस पार्टी की वजह से बाबू जगजीवन राम भी उधर सैंटर में फूड एण्ड एग्रीकल्चर मिनिस्टर की हैसियत से बैठे हैं और जिस पार्टी ने मेरे जैसे सड़क पर चलने वाले मजदूर को यहां बैठाया है, वह अब भी हमारी भलाई के लिये खूब काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी । मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर मेरे उधर बैठने वाले भाई यहां होते तो मैं उन्हें बताता कि

किस तरह से हरिजन भाई उस सरकार को जो इनकी कमर में छुरा घोपना चाहती है तोड़ते हैं और किस तरह से थे उस सरकार को, जो इससे हमददी रखती है, चलाने में मदद देते हैं.... (विघ्न )

डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक बात और रह गई, जो हरिजनों के विषय में कहनी है वह है रिजर्वेशन इन-प्रमोशनज ।

**उषाध्यक्षा :** आपका समय हो चुका है । इसलिये आपको केवल पांच मिनट खैर दिये जा सकते हैं । आप जल्दी से अपना भाषण समाप्त करें ।

**सूबेकर प्रभु सिंह :** डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह तो बहुत काम की बात है । मैं तो सरकार के सामने एक तजवीज पेश करना चाहता हूँ विचार करना सरकार का काम है । व्यवस्था की जो कभी है उसमें एक तजवीज है । डिप्टी स्पीकर सहिबा, हमारे यहां एक मसल मशहूर है कि ' विधवा के दुख को विधवा जाने' क्योंकि खसम वाली औरत को दुःख का कुछ नहीं पता होता, इसलिये उस दुख को जो हमारे हरिजन भाईयों को है उसको मैं ही जानता हूँ । (हंसी ) हमारे यहां पहले हरिजनों के लिये प्रमोशन में रिजर्वेशन होती थी और पंजाव सरकार मे भी वह कर दी है मगर उस रिजर्वेशन को जो पीछे खिचडी सरकार आयी उसने बन्द कर दिया । उसी सरकार में जो चौधरी चान्द राम डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते थे और हरिजनों के लीडर होते थे उस रिजर्वेशन

इन-प्रमोशन को रोकने में उनके फाइल पर दस्तखत हैं । वह हरिजनों का गद्दार था । इसलिये डिप्टी स्पीकर साहिबा में आपके जरिए इस सरकार से पुरजोर अपील करूंगा कि जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन में थी उसे सरकार फिर से लागू करें और उन तमाम हरिजनों को यह तसल्ली कराये कि हमें कोई सम्भालने वाली सरकार आई है ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो लो-इन्काम स्कीम थी उसके तहत हरिजनों को मकान बनाने के लिये कर्जा दिया गया था । आपने उन को झोंपडियों से निकाल कर पक्के मकानों में रहना तो सिखा दिया परन्तु उसके साथ साथ उनको एक और दिक्कत हो गई । जो उनको कर्जा दिया गया है उस पर सरकार छः परसेन्ट सूद वसूल करती है । इसलिये मैं सरकार से यह गुजारिश करूंगा कि वह माफ होना चाहिए । दूसरी बात उन पर जो हाउस टैक्स लगाया हुआ है वह भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वह तो पहले भी अपने लोन की किश्त अदा नहीं कर सकते । उनके घर तो पहले ही सरकार के पास रहन रखे हुए होते हैं' । अगर उस पर हाउस टैक्स और लग जाए तो फिर और भी मुश्किल हो जाता है । इसलिये उन गरीब हरिजनों के घरों पर से यह हाउस टैक्स हटाया जाना चाहिए ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक काम की बात रह गई है वह कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा । इस बजट में हरिजन कल्याण फण्ड के लिये 65 लाख रुपया रखा गया है परन्तु जो पिछले सात्र



का बजट था उसमें 78 लाख रुपया रखा गया था । तो इसका मतलब यह हुआ कि पिछले साल से 13 लाख रुपया कम रखा गया । आपने इस बजट में पशुपालन के लिये 85 लाख रुपया रखा है परन्तु हरिजनों के लिए ह 5 लाख रुपया रखा है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप के जरिए मैं बहिन ओम प्रभा जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या हरिजनों से ज्यादा जरूरी पशुपालन है जो उनके लिए तो 85 लाख रख दिया और हरिजनों के लिए 85 लाख । इससे तो हरिजनों को मुर्गीपालन में ही रख लें कुछ पैसा तो ज्यादा मित्र जायेगा । इसलिए मैं सरकार से पुरजोर अपील करूंगा जो 78 से 65 लाख किया है यह फर्क दूर होना चाहिए । इन गरीब हरिजनों को इन्साफ मिलना चाहिए क्योंकि पहले ही इनको काफी झटके लग चुके हैं ।

**उषाध्यक्षा :** आपने काफी टाईम ले लिया हूँ इसलिए अब आपको बैठना ही पड़ेगा ।

**सूबेदार प्रभु सिंह :** डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक बात और कतू लेने दो वह कोई मेरी अपनी बात नहीं हूँ मैं तो हाउस के सामने तजवीज रख रहा हूँ ।

**उपाध्यक्षा :** नहीं, अब आपने काफी समय ले लिया है ।

**सूबेदार प्रभु सिंह :** अच्छा एक शेर कह लूं और उसके बाद बैठ जाता हूँ । मेरे दोस्त यहां पर नहीं हैं । लेकिन मियां रफतासर ने कहा है रु

गुनाहगारों में शामिल हूँ गुनाहों से नावाकिफ हूँ ।

सजा को जानता हूँ खुदा जाने खता क्या है ।

तो डिप्टी स्पीकर साहिबा सजा तो मैं जानता हूँ सो बातें तो मेरी बहुत रह गयी । लेकिन फिर भी आपका शुक्रिया जो आपने मूझे समय दिया ।

**चौधरी हरि सिंह सैनी (हांसी ):** डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपकी विसातत से अपने विचार हाउस के सामने रख रहा हूँ । डिप्टी स्पीकर साहिबा, जब नवम्बर 1966 में हरियाणा बना, तब से ले कर अब तक तीसरा बजट है । इस बजट को बहिन ओम प्रभा जैन जी ने बिना टैक्स लगाये यहां पेश किया है, इसलिए वे बधाई की पाल है' । इसके साथ ही दूसरी बात मैं अपोजीशन के भाईयों से कहना चाहता हूँ, वे इस समय हाउस मे नहीं हैं । अप्रैल, 1967 में संयुक्त विधायक दल की सरकार ने जो वजट पेश किया था, उस वजट के अन्दर किसानों पर 25 परसेन्ट आबयाना बडा दिया था । वे लोग जो आज यह दुहाई देते बैर कि हम हरियाणा का भला करेंगे उन सींगों ने उस किरान पर जो दिन और रात मेहनत करता है और लोगों को अन्न देता है और उस गरीब मजदूर पर जिसको केवल डेसू रुपया फी व्यक्ति के हिसाब से मिलता है उन्होंने 25 फीसदी लगान बढा दिया था । परन्तु इस सरकार ने उनपर कोर्टू किसी किस्म का आवयाना या टैक्स वगैरह नहीं लगाया है । साथ ही साथ मं' एक वात और आपके जरिए हाउस

को बताना चाहता है कि उस सरकार बिजली और पानी के मती चौधरी मनीराम गौदारा थे उन्होंने उस समय यह प्रोटेस्ट किया था कि अगर किमानो पर आवयाना वढाया गया तो मैं मिनिस्टरशिप से इस्तीफा दे दूगा । अब मैं उनके विषय मैं अधिक नही कहना चाहता हुं क्योकिं वे इस समय हाउस में नहीं हैं जो बड़ी बातें कहते हैं' और हमेशा गवर्नमेंट के ठेकेदार बन रहना चाहते हैं ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, दूसरी जौ इन वजट के अन्दर विशेष वान कही गयी देर वह यह है कि हमारी सरकार ने जो बुद्धो को पेन्शन देने का आश्वासन दिया है उसके लिए हमारी सरकार बधाई की पाव है । दूसरी और तालीम के मैदान मे आज दो-सौ के करीब स्कूलों को अपग्रेड किया है जब कि पिछली सरकार ने केवल सी स्कूलों को जो कि पांच मात के अन्दर अपग्रेड होने थे केवल दो ही महीने में अपग्रेड कर दिया था ।

हमारी सरकार ने बगैर जनता पर कोइ टैक्स इत्यादि लगाये दो-सौ के करीब स्कूलों को अपग्रेड किया है । इसके लिए भी मैं अपनी वित्त मली महोदया को वधाई देता हूं ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, कुछ तकलीफें, आगके जरिए में' वित्त मंत्री महोदय के सामने अपने हलके के विषय में पेश करना चाहता हूं । सन् 1960-61 में सरदार प्रताप सिंह कैरों के समय मुतहिदा पंजाब में डिस्ट्रिक्ट संगरूर, अमृतसर और हांसी के सेमजदा इलाके के लिए एक स्कीम बनी थी । उस समय यह स्कीम थी कि सेम को

निकालने के लिए डैन सिस्टम और कुछ ट्यूबवैल लगाने थे । उसके बाद मेरे इलाके के विषय में कोई नहीं सुनायी हुई, न तो कोई डैनो की खुदाई वगैरह हुई, न नहरों की हुई जो कि अब मिट्टी से भर चुकी हैं और न ही नहरों को ऊंचा किया और साथ ही जो वह डैन सिस्टम चालू किया गया था हांसी के लिए वह चालू हुआ । उस वक्त चौधरी दलवीर सिंह जी डिप्टी मिनिस्टर होते थे । उनके हटने के बाद वह स्कीम वहीं ठप्प हो गयी । मेरे इलाके में सन् 1960-61 में इतना जबर्दस्त सैलाब आया था कि तीन महीने तक लोगों को किश्तियों में चलना पड़ा था और पंजाब सरकार ने साठ लाख रुपया अनाज की शकल में इमदाद के लिए दिया था । अब हमारी सरकार भूल गयी है कि फिर भी वहां सैलाब आ सकता है । सन् 1967 में सब से ज्यादा पानी हांसी के इलाके में आया था उस समय भी लोगों की बहुत खराब हालत हुई थी । इसलिए मैं अपनी सरकार से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि जहां और जगहों पर सैलाब रोकने के लिए काम हो रहा है वहां हांसी तहसील में कोई काम नहीं हो रहा ।

इसके साथ ही मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सन् 1967 में पंडित भगवतदयाल जी की सरकार कुछ दिनों के लिए रही । यह बहिन ओम प्रभा जी उस वक्त भी वित्त मंत्री थीं । उन्होंने हांसी के अन्दर एक स्कूल को कालेज के रूप में बदलने के लिए एक लाख 50 हजार रुपया मंजूर किया था । लेकिन हुआ यह कि उसके बाद संयुक्त दल की सरकार आ गई और जब राव वीरेन्द्र सिंह वहां गए

तो लोगों ने कहा कि हांसी तहसील में बहुत सारे हाई स्कूल हैं' और इतनी संख्या है कि जितनी स्टेट में शायद ही कहीं हो, इसलिये कालेज होना चाहिए । मगर राव साहिब कहने लगे कि यह बतलाओ कि तुम्हारा एम.एल.ए. कहां है । तो लोगों ने बतलाया कि वह तो कांग्रेसी है । बस फिर क्या था । उन्होंने कहा कि यह रुपया जो एक लाख पचास हजार रखा गया है इसको वापस कर लो । यहां कालेज नहीं बनना चाहिए । और वह कालेज उस वक्त नहीं बना । मैं आज अपनी सरकार से मतालबा करता हूं कि नेहरुय मेमोरियल कालेज को सरकार अपनी तहसील में ले कर स्वीकृति दे । साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हांसी के अन्दर जो गवर्नमेंट हाई स्कूल है उसकी बिल्डिंग नहीं है और वह स्कूल एक घोड़ों के अस्तबल में जो 200 रुपए माहवार पर आज से 10 साल पहले लिया गया था. उसमें वाकै है । 2, 200 लड़कियां उस स्कूल में पढ़ती हैं । मगर उसकी इमारत इतनी खस्ता है कि छतों के गिर जाने से 80, 000 की कीमत का साइंस का सामान उसके नीचे दबा हुआ है । मैं सरकार से मतालबा करता हूं कि जहां लड़कियां इतनी तादाद में पढ़ती हों वहां पर बाकायदा एक इमारत बनानी चाहिए ।

अब मैं वाटर लौगिंग के मुताल्लिक कुछ अर्ज करना चाहता हूं । हांसी तहसील में खासतौर पर हांसी के अन्दर इतना कीचड़ हो जाता है कि किसान को सड़कों पर से अपना अनाज ले जाने में भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है । वह अपने दाने भी

घर नहीं ले जा पाता । अब सरकार ने एक सड़क 10 मील लम्बी दी है उसके लिये मैं सरकार को वश' देता हूँ, क्योंकि हांसी से महजोद और बरबाल से राजडी तक आने जाने में लोगों को राहत मिली है । मैं सरकार को बिजली के काम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिये बधाई देता है । लेकिन हांसी हल्के के अन्दर किसी भी गांव को बिजली नहीं दी गई । इस लिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि हांसी के गांवों को बिजली देने का प्रबन्ध करें ।

जहां तक हांसी के हस्पताल का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि वह बहुत ही घटिया है । बड़े ताज्जुब की बात है कि हांसी शहर की आबादी 60 हजार के करीब है मगर हस्पताल को हालत बहुत ही खस्ता और नाकिस है । मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस अस्पताल को प्रोविंशियलाइज करने की कृपा करे । और जो शेर सिंह रघुबीर अस्पताल हूँ उसमें 6 महीने से लेडी डाक्टर नहीं है इसलिये वहां पर लेडी डाक्टर भेजने की कृपा करें (घंटी) वस डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता है कि आपने मुझे टाइम दिया । इतना कहूँ कर मैं बैठ जाता हूँ ।

**चौधरी रणबीर सिंह (किलोई ):** उपाध्यक्ष महोदया, आप जानती हैं कि हमारे पड़ौसी प्रदेश के अन्दर आज चुनाव की गिनती हो रही है और उसके बाद वहां पर सरकार आएगी जो इस बात की बड़े जोर से मांग करेगी कि चंडीगढ़ हमारा हूँ, हमें दो । भाखडा नंगल हमारा है, हमें दो । और पता नहीं क्या क्या मांगेंगे । उनके नेता संत फतेह सिंह के व्यान अखबारों में छपे हैं । उससे

लगता है कि उन्हें समझ आ गई है लेकिन मेरा कयास यह है कि एक बहुत बड़ा हल्ला शुरू होगा । इसलिए हमारी सरकार को भी तैयार रहना चाहिए ।

जहां तक चंडीगढ़ हरियाणा में मिलने का कमीशन का फंसना था वह बहुत मौजूं फैसला था और हरियाणा का दावा भी बड़ा मुनासिब था । लेकिन कुछ मुश्किलों की बिना पर केन्द्रीय सरकार ने यह सोचा कि अगर दोनों सरकारों का हैडक्वार्टज चंडीगढ़ रहेगा तो वही दोनों सरकारें अच्छी तरह से रह सकेंगी इसलिए चंडीगढ़ को सैन्ट्रल टैरिटरी शामिल कर दिया गया । उनको खतरा था कि अगर किसी एक के पास चला गया तो हो सकता है कि वह सरकार दूसरी सरकार को रहने न दे । और यह सच है कि हमारे देश के अन्दर कुछ वायुमंडल ऐसा है कि किसी भी प्रदेश को अगर चंडीगढ़ मिलता तो वह प्रदेश दूसरे प्रदेश की सरकार को शायद न रहने देता । अब मैं कहता हूँ कि वह चंडीगढ़ यूनियन टैरिटरी बना दिया गया है । ठीक है फिलहाल । मगर चुनाव के परिणामों और सरकार के बन जाने पर काफी हल्ला होगा । इसके साथ साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि बहुत सारी बातों में हमारा पंजाब के साथ सांझा था और ज्वायंट पंजाब में जो अदारे थे कुछ मिलिक्यत थी उसका बंटवारा होना था लेकिन अभी तक नहीं हुआ । मैंने बहुत तलाश किया जो कागज हमें बांटे गए है उनमें वह कागज भी मिल जाएं जिनमें बंटवारे का जिक्र हो लेकिन मैं तलाश नहीं कर सका । लेकिन सन् 1988 के

चुनाव के बाद जब बजट पास हुआ था तो उस वक्त सैकेटरी का जो मेमोरंडम था उसके अन्दर अनैक्सचर नम्बर 6 है, उसके अन्दर दिया था कि कितने अदारे हैं' जिनके अन्दर हरियाणा सरकार की साझेदारी है । उस वक्त उनकी तादाद 68 के करीब थी । इनमें कुछ अदारे ऐसे हैं जो हरियाणा बनने के बाद बने, इसलिए इनमें तो बंटवारे का सवाल ही पैदा नहीं होता । कुछ कोआप्रेटिव बैंक्स ऐसे थे जो सारे के सारे हरियाणा के अंदर आ गए उसमें भी कोई बंटवारे का सवाल पैदा नहीं होता । मगर यह काई 16 या 17 ही होंगे । और 50 के करीब ऐसे अदारे हैं' जिनमें हमारी पंजाब व हिमाचल के साथ साझेदारी है । कुछ चडीगड़ का भी इनमें हिस्सा करू । मैं जानना चाह हूँ कि उनका बंटवारा हुआ या नहीं हुआ । अब तो वह दो साल भी वति गार जिनमें हम बंटवारा कर सकते थे ।

उसा वक्त हम आपस में बँट कर मिलकर बंटवारा कर सकते थे लेकिन अब तो भारत सरकार की विसातत से उन का बंटवारा हो सकता है । मैं कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि मेरी गलती हो शायद कहीं कागज में इस बात का जिक्र हो और अगर ऐसा है तो मैं चाहूंगा कि विल मंत्री महोदया मैबरान की जानकारी के लिए बतलाए कि वह जानकारी किस कागज पर लिखी हुई है और अगर अभी नहीं दी गई तो उग जानकारी को हमें दिया जाए कि आज की हालत क्या है । अगर 1968 की बात आज मैं कहूँ तो वह पिछड़ी हुई लगती है । लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं



। इस बात पर ज्यादा जोर न डालता हुआ मैं कहना चाहता हूँ कि आप को याद होगा कि राव बीरेंद्र सिंह जी ने भी इस बारे में काल अटैन्शन मोशन दी थी लेकिन वह कुछ चंद अदारो के वारे में थी और चंद कारपोरेशन्ज के बारे में दी 'वो । इनके अहादा और भी कारपोरेशन्ज है जिन में हमारी हिम्सेदारी है । यहां भाखड़ा के पानी और बिजली के बटवारे का भी जिक्र है । उसका भी लेई फैसला नहीं हुआ है । इसी बात पर मैं जरा दूसरी तरफ होना चाहता हूँ । मद्रास के इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो चेयरमैन थे वह एक रिटायर्ड अफसर थे और उन्होंने जो काम किया उस की मिसाल किसी प्रदेश में नहीं मिलती है । चौधरी सूबे सिंह जो हमारे आज बोर्ड के चेयरमैन हैं जब चेयरमैन यने तो उस वक्त एक रोज अचानक मेरी उन से सड़क पर मिलने पर बात-चीत हुई और मैंने उनसे कहा था कि आप को मद्रास से सीखना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, सरकार को भी वात होती है लेकिन सरकार का काम कितनी तेजी से चलता है वहू उसके कारिदों पर मुनहसर होता है । हमारे हरियाणा स्टेट के बोर्ड ने बहुत तेजी से काम किया है इसलिये मैं उन को मुबारिकबाद पेश करना चाहता हूँ और यह भी साथ 'ही साथ कहे बिना नहीं रह सकता कि हालात हमारे ऐसे हैं कि विजली की हमें बहुत जरूरत है लेकिन बिजली की कमी है और बंटवारा करने वाले हमारे से होशियार हैं । सरदार रछपाल सिंह गिल जो पंजाब के इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन हैं हमने उन का दौड़ में मुकाबला करना है ।

हम पहले ही बिजली के बंटवारा में घाटे में हैं । एक दफा वह तेजी से आगे बढ़ गए तो बिजली की खपत उधर ज्यादा होगी । इसके मायने हैं कि हमारे लिये बढ़ने की गुन्जायश कम रहेगी । यहां विरोधी दल के नेता राव बीरेन्द्र सिंह जी हाउस में हाजिर नहीं हैं । मुझे उनकी और बातों से गिला नहीं है । उन के राज में कितना अच्छा काम हुआ है या नहीं हुआ है उस वारे में मैंने कुछ नहीं कहना है लेकिन एक बात मैं कहे बगैर नहीं रह सकता कि एक वक्त आया था

हिन्दुस्तान के इतिहास में जिस वक्त हरियाणा के मुख्य मंत्री राव साहिब थे जो कांग्रेस पार्टी से बाहर चले गए और जमुना के दूसरी तरफ बसने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री चौधरी चरण सिंह जी थे । दोनों इलाकों का जमुना नदी से घनिष्ठ सम्बन्ध था और दोनों ही नेता जमुना दादी के रहने वाले थे । दोनों तरफ पानी और बिजली की तरक्की के लिये जमुना डैम की स्कीम चालू होती तो उस पर दोनों इलाकों को तरक्की का मुनहसर था लेकिन हमारी बदकिस्मती कि ऐसा वह नहीं कर सके । हम को तो कहते थे कि हम भारत सरकार से घबराते हैं इसलिये कई दफा तेजी से नहीं चल पाते हैं । लोगों से राये मांगते वक्त भी हमेशा यही कहते थे कि हम भारत सरकार से घबरा जायेंगे, हम टक्कर नहीं ले सकेंगे लेकिन वह डट कर टक्कर ले सकेंगे । लेकिन जो कुछ हुआ वह आपके सामने है मैं क्या बताऊं । यह किशाऊ डैम एक ऐसी चीज है कि आज का हरियाणा ही नहीं

आगे का जो हरियाणा है जैसे कि हमारे विरोधी दल के नेता के नुक्तानिगाह के मुताबिक विशाल हरियाणा बनाना है तो उस सारे इलाके की तरक्की इस डैम के बनने पर मुनहसर करती है । किशाऊ डैम की कोई ईंट रखी जानी चाहिए थी और अगर वह इसकी कोई ईंट ही रख देते तो हमारी तसल्ली हो जाती लेकिन वह ऐसा न कर सके । वैसे तो हमारे वित्त मंत्री महोदया ने हमारे प्रदेश के लिये कई बातें अच्छी की हैं लेकिन मुझे दुख के साथ उनके लिये भी कहना पड़ता है कि उन की सरकार ने एक फूटी कौड़ी भी किशाऊ डैम के लिये नहीं रखी है और इस डैम के बगैर भै' कह सकता हूँ हमारी तरक्की नहीं हो सकती । इस में जिक्र आता है एक नहर बनाने का । हमारे विशेषज्ञ कितनी होशियारी और ध्यान से काम करते हैं वह गम्भीरता से विचार करने का विषय है । व्यास दरिया का पानी सतलुज में डाल रहे हैं और उसके लिये पहाड़ियों में खुदाई करके दो सुरंगे बनाई जा रही हैं और उन में कोई 800 क्यूसिक्स के करीब पानी का प्रवाह होगा । व्यास के ऊपर दो डैम बनाने जा रहे हैं एक पौंग और दूसरे पंडोह के ऊपर । दोनों पर कई साल से काम चालू है और भगवान की दया से मुझे खुशकिस्मती मिली थी जिस वक्त मैं पंजाब का बिजली तथा सिंचाई मंत्री था उस वक्त उन पर काम जारी हुआ था । काम अभी कुछ सुस्ती से हुआ क्योंकि जब तक हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के मुआदा के मुताबिक हमें पूरा अधिकार नहीं मिल जाएगा कि हम पूरा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं उस वक्त तक यह डैम तैयार नहीं हो सकते हैं । उसमें सुस्ती

कई कारण से हुई । विदेशी मुद्रा कम मिली और केन्द्रीय सरकार से कर्ज का पैसा कम मिला लेकिन इस में यह बात जरूर हुई कि अफसरों की गिनती में कोई फर्क नहीं आया । मुझे व्यास प्रोजैक्ट के अफसरों से बात करने का मौका मिला और वह एक तरह से इस तरीकाकार पर हंसते भी थे कि हम आदमी तो बढ़ाते जाते हैं लेकिन काम करने के लिये सामान नहीं जुटाते हैं । खैर वह तो बनेंगे लेकिन इस वक्त देखने की बात यह है कि आया उस पानी को इस्तेमाल करने के लिये 120 मील लम्बी नहर बनाने की आवश्यकता है या नहीं जिसके लिये हमारे वित्त मंत्री महोदय ने बजट में 158 लाख रुपए का प्रोविजन इस साल के लिये किया है । इस 120 मील लम्बी नहर के बनाने पर अनुमान है कोई 27 करोड़ रुपया खर्च होगा । आप अंदाजा करें कितना बड़ा काम है । मैं यह कहना चाहता हूँ कि देखने की जरूरत है कि आया उसके करने की आवश्यकता है भी या नहीं । अगर आवश्यकता है तो तेजी से चलना चाहिए था और अगर आवश्यकता नहीं तो हमें गम्भीरता से सोचना चाहिए कि आया इतना पैसा खर्च करना है या नहीं । आज सारे दरियाओ व्यास, रावी, सतलुज को काफी दिनों से जोड़ रखा है और जमुना तक उन का मेल जोड़ खा जाता है । जो इलाके जमुना के पानी से सींचे जाते थे उसमें यह देखने की आवश्यकता है कि आया उन इलाकों की सिंचाई रावी—व्यास और सतलुज के पानी से आज भी हो सकती है और अगर हो जाती है तो आया हम जो नई योजना व्यास प्रोजैक्ट के पानी इस्तेमाल करने के लिये बना रहे हैं उसके पानी का पूरा

हिस्सा इस्तेमाल करने के लिये हमें कोई नहर बनाने की आवश्यकता है या नहीं । कहीं वे ऐसा कहना शुरू न कर दें कि जो पानी हमारे हिस्से में आता है हम उस को इस्तेमाल करने लायक ही नहीं हैं जब तक नई नहर नहीं बन जाती ? नई नहर बनाने से हम यदि बरसात का पानी भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं । भाखड़ा की नहर है उसमें 14 हजार क्यूसिक पानी चलता है । यह चौदह हजार क्यूसिक पानी चन्द दिन तक ही चलता है, सारा साल तो इतना पानी चलता ही नहीं है । आम तौर पर उस नहर के अन्दर कोई पांच, छः, सात और आठ हजार क्यूसिक पानी चलता है । साल में किसी महीने में 10 हजार क्यूसिक पानी बहता होगा, किसी में आठ हजार क्यूसिक बहता होगा और किसी में छः हजार क्यूसिक बहता होगा । इन हालात में हम नहीं चाहते कि व्यास प्रोजैक्ट से हमें कम पानी मिले । व्यास प्रोजैक्ट के ऊपर जो बान्ध वान्धा जा रहा है उसमें भाखड़ा की तरह बहुत सा पानी इक्का करने के लिये कोई जलाशय बनाने की बात नहीं है । हां, थोडा सा जलाशय पोग डैम पर बना है, यह कोई ज्यादा जलाशय नहीं है, उस जलाशय का हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे हिस्से में आयेगा । इसके इलावा जो पंडोह डैम बना रहे हैं वह भी कोई जलाशय नहीं होगा, वहू दरिया के बहाव के पानी को मोड़ने के लिए बनाया गया है । इसका आठ दस हजार क्यूसिक पानी भाखड़ा के जलाशय में पड़ता रहे गा और उससे बिजली पैदा होगी । उस पानी को हम अपनी नहर में से आज भी ले जा सकते हैं या नहीं,

इसके बारे में कुछ कहूँ सकता हूँ । यह अहम प्रश्न है । उपाध्यक्ष महोदया, आपकी मारफत में ' सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम में उस पानी चलाने की शक्ति मौजूद है । इसलिये यह जो 27 करोड़ रुपये की नई नहर चालू करने की बात है, यह बड़ी समझ से चलाने वाली चीज है । यह हमको धोखे में डाल सकती है' । अगर 27 करोड़ रुपया खर्च करने की बजाय, जमुना नहर को पक्का कर दिया जाता है तो यह रुपये का सही खर्च होगा । वित्त मंत्री के भाषण में एक बड़े इंजीनियर का जिक्र आया, वे हमारे हरियाणा प्रदेश के निवासी हैं, यू .एनओ. में काम करते हैं और विदेशों के सलाहकार हैं । मैं समझता हूँ कि अगर इस सिलसिले में उन से सलाह की जाये तो उनकी राय और मेरी राय में कोई फर्क नहीं हो सकता । उन्होंने एक किताब लिखी थी उसमें लिखा था कि नहरों को शुरू से लेकर अन्त तक पक्का कर दिया जाये तो उसमें चलने वाले पानी से 35 फीसदी और ज्यादा भूमि को सिंचा जा सकता है । यह एक बहुत बड़ी बात है । अगर नहरों को पक्का कर दिया जाये तो डैम बनाने की आवश्यकता पानी बढ़ाने के लिये नहीं पड़ती, इस पर रुपया भी कम खर्च होता है और 35 फीसदी जमीन और सैराब करने लायक हो सकते हैं । लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि हमें पानी कहां से मिलेगा, इस बात पर गम्भीरता से विचार करने वाली बात है ।

इसके इलावा उपाध्यक्ष महोदया, आप जानते हैं कि पंजाब प्रदेश दो तीन हिस्सों में बांटा गया है । ज्वायंट पंजाब में हरियाणा के

लोगों को यह शिकायत थी कि उन्हें पूरा अधिकार नहीं मिलता है । पंजाब के कर्मचारियों ने हमें अपने अधिकार से महरूम रखा था । सिर्फ एक मैडिकल कालेज रोहतक में बड़ी मुश्किल से बना हैं । इस कालेज में आज जितने भी प्रोफ़ैसर है, आप को जान कर ताज्जुब होगा कि उन में सिर्फ एक ही भाई है' जो हरियाणा प्रदेश के रहने वाले है' । वै भी हमारे हैल्प मिनिस्टर के हल्के के रहने वाले आदमी हैं ।

**श्री राम सरन चन्द मितल :** एक प्रोफ़ैसर नारनौल के भी है' ।

**चौधरी रणबीर सिंह :** वे प्रोफ़ैसर नहीं है, असिस्टेंट प्रोफ़ैसर है' । इस बात के लिए झगड़ा तो मैं नहीं करता कि मैडिकल कालेज के अन्दर हरियाणा से वाहर के प्रोफ़ैसर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, लेकिन एक बात पर मुझे दुख से कहना पड़ता है वह है स्वास्थ्य विभाग । इस विभाग में मुझे तीन चार महीने काम करने का मौका मिला था । उस वक्त मैंने देखा था कि जो लोग उच्च अधिकारी हैं वे किम तरह की साजिशें करते है' । एक दूसरे की तरक्की करवाने के लिए या रोकने के जिस किसम की साजिशें वे करते हैं, उसको मैंने अच्छी तरह समझा है । बड़ी बड़ी रुकावटें डाली जाती थीं ताकि हरियाणा के लोगों का भर्ती करने के लिए पूरा हिस्सा न मिले । मैं सिर्फ प्रोफ़ैसर का ही जिकर नहीं करता, डाक्टर का ही जिकर नहीं करता, चारों तरफ सबके साथ पेसा ही तरीका बरता जाता था ताकि हरियाणा के निवासियों को आगे बढ़ने का मौका न मिले । जो असिस्टेंट प्रोफ़ैसर बन गया उसको

शुरू से ही खत्म करने की कौशिश की जाती थी ताकि वह पूरा प्रोफ़ैसर न बन सके । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं एक महकमा के बारे में ही जिकर करना नहीं चाहता हूँ । उस वक्त तमाम नौकरियों की भर्ती पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की मारफत की जाती थी । सब नौकरियां अखबार में निकाली गईं लेकिन एक नौकरी नहीं निकाली गई क्योंकि उस नौकरी के निकालने से उस में हरियाणा के आदमियों के आने की सम्भावना थी । हरियाणा के आदमियों को राकने के लिए उस मांग को आयोग के पास या अखवार में निकाला ही नहीं गया । इस मामले में इतनी होशियारी और समझ से काम लिया जाता रहा ताकि हरियाणा कुछ न ले सके और लोग एक दूसरे के साथ झगड़ते रहे । आप देखें कि जो विरोधी दल के भाई है वे हरियाणा के ही रहने वाले हैं और हरियाणा के लोगों के नुमायंदे हैं । हमारा आपस में इख्तलाफ हो जाता हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं । लेकिन अगर उस इख्तलाफ से हम फायदा उठाना चाहें तो वह थोड़ी देर के लिए ही होगा, हमेशा के लिए नहीं । इसी तरह अगर हरियाणा प्रदेश के लोगों को जो फायदा पहुंचता है अगर उसको कोई छीनना चाहे तो छीन नहीं सकता चाहे कोई कितनी शक्ति वाला हो, सरकारी कर्मचारियों का तो कहना ही क्या है । दो तीन दिन पहले मेजर अमीर सिंह जी ने एक सवाल पूछा था कि चण्डीगढ में स्थित हरियाणा कार्यालयों में कर्मचारियों की भर्ती किस तरह की जाती है? उन्होंने फोर्थक्लास की भर्ती का जिकर किया था । इस बात को कौ कौन नहीं जानता कि जिन लोगों के नाम चण्डीगड एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में



दर्ज हैं उनको छः महीने तक की मुलाजमत घर बैठे बेंटे ही देते हूँ' । इन लोगों में भी सब से पहले उन भाइयों के नाम आते हैं जो यहां के मालिक बन बैठे हैं । आप देखते हैं कि किस ढंग से और किस होशियारी से हरियाणा के लोगों को उन के हक से महरूम किया जाता है । मुझको मालूम कहीं कि हिन्दुस्तान को सरकार का कौन सा कायदा और कानून हमारे रास्ते में आ सकता है जब कि हम यह कहें कि कोई नौकरी चाहे चतुर्थ श्रेणी की हो, चाहे तृतीय श्रेणी की हो, चाहे द्वितीय श्रेणी की हो और चाहे प्रथम श्रेणी की हो, चाहे वह एक महीने के लिए है या चार या पांच महीने के लिए है, भरी नहीं जाएगी, जब तक हरियाणा के सारे एक्सचेन्जिज से नाम नहीं आयेंगे । लेकिन हमारे सलाहकार हैं और आप जानते हैं मैं भी एक बोझ से बोल रहा हूँ और इस लिए बोल रहा हूँ कि मेरा जन्म रोहतक में हुआ है । मेरी तरह ही, मैं समझता हूँ दूसरे भाइयों, जिन का जन्म हरियाणा के अन्य स्थानों में हुआ है, के दिल में भी ऐसा बोझ होगा । खैर हमें इसका इन्तजाम करना चाहिए और मैं तो समझता हूँ कि अगर हम हरियाणा के लोगों के नुमायन्दे हैं' तो हम को इस बात की चौकसी रखनी होगी कि हरियाणा की नौकरियां सारी चण्डीगढ़ के भाइयों को ही न मिल जाएं । चण्डीगढ़ वालों को भी मिलें इस बात का मुझे गिला नहीं । मैं तो चण्डीगढ़ को अपना ही मानता हूँ मगर अगर अपना भी हो जाए तो भी हमें खयाल रखना होगा कि सारी नौकरियां यहां रहने वाले भाइयों के रिश्तेदारों या बच्चों को ही न चली जाएं । आज चण्डीगढ़ में क्या होता है? कौन सा दिन

खाली जाता है जिस दिन सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल नहीं होती है? तो उनके असीजों को, उनके रिश्तेदारों को रखने के लिए जो जो हथकण्डे इस्तेमाल किए जाते हैं' उन से हम को होशियार रहना होगा, उन से हम को बचना होगा । इस लिए उपाध्यक्ष महोदया, मेरा सरकार सै निवेदन है कि जब कभी कोई नौकरी यहां निकले, चाहे वह थोड़े ही दिनों के लिए क्यों न हो, उस के लिए हरियाणा की तमाम एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से नाम मांगे जाने चाहिए ।

इसके इलावा, उपाध्यक्ष महोदया, मुझको अपने हल्के के बारे में कुछ निवेदन करना है । परन्तु जौ बात मैं अभी करने लगा हूं वह न सिर्फ मेरे ही हल्के से सम्बन्ध रखती है बल्कि सारे प्रदेश की बात है । बहिन ओमप्रभा जैन हमारे साथ कभी मन्त्री होती थीं और उन्हें याद होगा कि उस वक्त किस तरह से बाढग्रस्त लोगों की मदद की जाती थी । डिप्टी स्पीकर साहिबा, उस वक्त जब कभी भी कहीं बाढ से तबाही होती थी तो बिना लोगों के कहे, बिना काश्तकार के प्रार्थना-पत्र के, सरकार की तरफ से एलान हो जाता था कि सब ऐसे इलाकों में जहां जहां बाढ आई है मालिया माफ, आबियाना माफ, किया जाता है । मगर अब बहिन जी ने कहा तो है कि काफी रुपया सरकार को फ्लड अफैक्टड ऐ रियाज में खर्च करना पड़ा लेकिन हमें तो पता नहीं कि कहां वह खर्च हुआ? मेरे हल्के में दो तीन गांव हैं, वहां तो किसी के लिए कुछ हुआ नहीं । इ सलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जहां जहां भी

फलड से तबाही हुई है वहां भूमि कर माफ होना चाहिए, आबयाना माफ होना चाहिए और इस माफी के लिए हमें एक एक आदमी को प्रार्थना पत्र देने के लिए नहीं कहना चाहिए बल्कि इस माफी की घोषणा सरकार की ओर से होनी चाहिए । अगर एक आदमी को भूमिकर या आबयाना माफ कराने के लिए 20 रुपए या 25 रुपए पहले खर्चने पड़ जाएं तो उस माफी का कीर्त्त फायदा नहीं । इसके अतिरिक्त इस दिशा में तबाही को रोकने के लिए और भी कदम उठाने की जरूरत है । इस साल मेरे हल्के में धामड, कलाई, लाडोत, बोहर और कनैहली के इलाके में काफी तबाही हुई । उस तबाही को रोकने के लिए कुछ काम तो हुआ और जो काम हुआ उस में कुछ अच्छा भी हुआ मगर पूरी तरह से उस तबाही को रोक नहीं सके तो उपाध्यक्ष महोदया, मेरी सरकार से यही प्रार्थना है कि जहां इसे तबाही वाले इलाकों में भूमिकर वसूल करने, आबयाना वसूल करने नहीं जाना चाहिए बल्कि इन करों की माफी का सरकार की तरफ से ऐसे इलाकों के लिए एक इलान होना चाहिए, वहां इस तबाही से आयदा लोगों को बचाने के लिए और मजबूत कदम भी उठाने चाहिए । इसके साथही साथ, उपाध्यक्ष महोदया, मैं सरकार का ध्यान भालौठ ब्रांच की ओर भी दिलाना चाहता हूं । यह दांच तहसील झज्जर, तहसील गोहाना और रोहतक को पानी देती हूँ । तहसील झच्चर क्योंकि आखिर में पड़ती है इसलिए वहां पर तो अभी तक वाटर लोगिंग नहीं हुआ परन्तु रोहतक में बहुत बुरा हाल है । उपाध्यक्ष महोदया, मैं जब पढ़ता था तो रोहतक में बड़ी मुश्किल से 60 फीट नीचे पानी

निकला करता था मगर अब अगर एक कस्सी मारों तो पानी निकल आता है । इसका कारण भालौठ ब्रांच है । यह खुदी हुई नहर नहीं है बल्कि बन्धी नहर है और जो भी बन्धी नहर होगी और कच्ची होगी वह वाटर लोगिंग ज्यादा पैदा करती है । इन सब बातों का नतीजा यह है कि आज हरियाणा का वह शहर जिस पर हरेक भाई गौरव कर सकता है, जो हरियाणा के लिए हर किस्म की आवाज उठाता है, पानी में तैर रहा है । उसको, डिप्टी स्पीकर साहिबा, दो तरीकों से डूबने से बचाया जा सकता है । एक तो नहर को पक्की किया जाए और दूसरे जिस तरीके से हमने हांसी शहर को बचाया था उस तरीके से । कुछ दिन हुए हांसी शहर बाढ़ की लपेट में आ गया था । उसे बचाने के लिए नहर के साथ साथ पानी निकालने के लिए, पानी की निकासी के लिए जगह जगह के ऊपर बिजली के पम्पिंग सैट लगाए गए थे । तो यदि उसी तरह से रोहतक शहर में और उन इलाकों में जिन्हें भालौठ ब्रांच ने पानी में लगभग डुबो दिया है पम्पिंग सैट लगा दिए जाएं तो उन्हें बचाया जा सकता है । रोहतक में, डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक रिठाल गांव है । मेरे एक दोस्त जो कुछ दिन पहले सिंचाई और बिजली मन्त्री थे उनके ' हल्के में यह पड़ता था । जब मैं मन्त्री था तो वहां पर मैंने एक पम्पिंग स्टेशन लगवाया था और उस वक्त जबकि रोहतक में सैलाब आता था उसकी वजह से उस गांव की तमाम जमीन बोई गई थी लेकिन मेरे साथी ने जब मैं मन्त्री नहीं रहा हल्ला गुल्ला करके उस पीम्पग स्टेशन को उठवा दिया । परन्तु डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे इस बात की खुशी है

कि जब मेरे साथी खुद मन्त्री बने तो इन्होंने फिर वहां पम्पिंग स्टेशन को लगवाया । पहले तो मेरे खिलाफ नारे लगाए गए थे कि अगली गांव मेरे गोत का गांव है इस लिए पानी को निकालने नहीं देंगे । खैर, इसके इलावा, डिप्टी स्पीकर साहिबा मेरे हलके के एक गांव घामड़ के अन्दर भी पम्पिंग सैट लगाया गया है और इसकी वजह से अब की बार यह गांव बचा रहा । लेकिन कुछ गांव और हैं, जैसे लाडौत है, किलोई हे और खास करके रोहतक शहर है, यहां भी इन सैटों को लगाने का इन्तजाम जल्दी से जल्दी होना चाहिए । रोहतक शहर तो अब की दफा डूबा ही इस लिए क्योंकि वहां पम्पिंग स्टेशन नहीं था । अगर वहां पहले पम्पिंग स्टेशन लगा दिया जाता तो रोहतक शहर डुबने से बच जाता । रुस लिए, उपाध्यक्ष महोदया, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जहां भी पम्पिंग स्टेशन लगने चाहिए वहां जल्दी से जल्दी लगाए जाएं और जब तक नहर पक्की न हो तब तक हमारे जिले को, हमारे इलाके को हमारी तहसील को और न डूबने दें ।

उपाध्यक्ष महोदया, इसके इलावा सरकार को मेरा सुझाव है कि बहुत सारी योजनाएं जो हमारी पहली कांग्रेस सरकार ने चालू की थीं मगर राव बीरेन्द्र सिंह सरकार ने बन्द कर दी थीं उन पर काम चालू करना चाहिए क्योंकि वे राजनीतिक बिना पर बन्द हुई थीं ।

उपाध्यक्ष महोदया, यह तो मैंने बजट के सम्बन्ध में बातें कहीं, मगर यदि आप इजाजत दें तो एक दो बातें और माननीय सदन के समाने अर्ज कर दूं क्योंकि यहां एक और ड्रामा भी हो रहा है ।

आप जानती है कि आज कोई विरोधी दल का सदस्य यहां नहीं है । वे हमारे ऊपर इलजाम लगाते हैं कि हमने उनको भगा दिया या उनकी गैरहाजिरी में हम बजट को या दीगर काम को पास करना चाहते हैं । उपाध्यक्ष महोदया, जिस दिन राव साहिब यहां बैठे थे, मैंने तो उस दिन ही उनसे कहा था कि अगर चार के ही फर्क से कोई चीज पास हो तब तो हम मान लें कि आप जीत गए और हम हार गए और अगर चार से ज्यादा फर्क से हम जीतें तब तो आप हारे ही हैं । लेकिन वे इस बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं थे । फिर डिप्टी स्पीकर साहिब हमने उन से कब कहा था कि सारे के सारे खड़े होकर इस सदन का काम न चलने दो । यह तो उनके ही नेता थे जो यह सलाह देते थे और बाहर बैठे थे । तो कांग्रेस की सरकार को, कांग्रेस पार्टी को, इस सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदया, दोष देना विरोधी दल के लिए सही बात नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदया, इसके इलावा एक और ड्रामा यहां रचा गया । यहां कहा जाता है या डर दिखाया जाता है कि हम अपने प्रदेश को राष्ट्रपति शासन की तरफ धकेल रहे हैं । लेकिन दरअसल कौन ऐसा कर रहा है इस बात को हमको समझना होगा । कुछ साथी हैं, जो इस सदन के 'मैम्बर नहीं हैं, जो इस सदन के काम को बाहर बैठकर चलाना चाहते हैं । और जब वे देखते हैं कि उनकी मजी के मुताबिक काम नहीं चलता तो वे सदन को भंग कराने की साजिश करते हैं, कर सकते हैं और करना चाहते हैं । डिप्टी

स्पीकर साहिबा ये तो इस सदन को भंग करने की साजिश कर रहे हैं । हम को कहा जाता है ' कि हम कर रहे हैं ' । हमने कभी गली कहा कि हमारा कोई मैम्बर भगा लिया गया है कौन नहीं जानता कि कितने मैम्बर भाग गये, खुद विरोधी दल के नेता भाग गये थे दो वर्ष पहले । हमारे साथी जिनका जिक करते हैं, वे हम से भाग गये बल्कि उल्टा उन्होंने हमारे मैम्बरों को भगाया है । यहां पर हाउस में श्री जोगिन्द्र सिंह का नाम लिया गया । उपाध्यक्ष महोदया, जो ब्यान श्री जोगिन्द्र सिंह ने यहां हाउस में दिया ह अगर वही व्यान किसी अदालत के सामने दिया जाये तो पहली ही पेशी में उनका यह मुकदमा खारिज हो जायेगा । इन व्यानो पर कोई विश्वास ही नहीं कर सकता । पहले वे कहते हैं कि मुझे बेहोशी की हालत मे अजमेर ले जाया गया, जब तुम बेहोश थे तो तुम्हें यह कैसे पता लगा कि तुम अजमेर में हे । फिर उसके बाद कहते हैं जब मुझे होश आया तो पता लगा कि मैं जयपुर में हूं । ये सब बातें इनकी बनायी हुई है । यहां यह भी कहा गया कि चीफ मिनिस्टर साहब के यहां मुझे कुछ पिलाया गया और काफी दिनों से उसको लाईसेंस नहीं मिला था, कुछ ही समय में लाइसेंस मिल गया । उपाध्यक्ष महोदया आज हमारा बहुमत है और विरोधी दल के नेता और सदस्य हमारे साथ सहयोग करना नहीं चाहते । वे हरियाणा को बदनाम करने की तरफ ले जा रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदया मैं आप के जरिए यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि भगवान हम सब को सद्बुद्धि दे । जिस प्रकार विलायत के अन्दर तीन मैम्बरों के फर्क से सरकार चल सकती है तो इसी

प्रकार का रास्ता यहां हमें दिखाये' कि तीन के फर्क से पांच वर्ष तक हरियाणा के अन्दर कांग्रेस सरकार चल सकती है ।

जिन भाइयों ने बड़े प्यार से हमें यहां चुन कर भेजा है, खुदा उनके सामने फिर से हमें पांच साल के बाद भेजे तो हम यह कह सकें कि हमने आप लोगों की सेवा की हूँ । हम उनकी भलाई के काम करें और हरियाणा से प्रजातन्त्र शासन खत्म न हो और राष्ट्रपति राज लागू न हो यती मेरी प्रार्थना है ।

**श्री प्रेम सुख सिंह ( सिरसा )** : डिप्टी स्पीकर साहिबा, फाईनेस मिनिस्टर साहिबा ने जो बजट सदन के सामने रखा है उसके बारे में कुछ विचार मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ । इस थोड़े से अर्से के अन्दर सरकार ने बहुत से ऐसे काम किये हैं जो सराहने योग्य हैं । राव साहब की सरकार के समय भी मैं इस असैम्बली का मेम्बर था । उस समय भी हमने काफी कोशिश की यह ओल्ड एज पेन्शन बन्द न हो परन्तु उस सरकार ने इसको बन्द कर दिया था । परन्तु अब हमारी सरकार ने इसको फिर से चालू कर दिया है । यह एक बड़ा भारी कदम है । इतना ही नहीं इस पेन्शन को 15 रुपए से बढ़ा कर 25 रुपए कर दिया है ।

दूसरी बात जो हमारी सरकार ने की है वह यह है कि मिडल तक के बच्चों को पहले फी तालीम दी जाती थी लेकिन राव साहब की सरकार ने इसको बन्द कर दिया था । अब हमारी सरकार ने फिर



से इस फैसले को रिवाइव कर दिया है और मिडल तक के बच्चों की फीस माफ कर दी है ।

सेल्ज टैक्स के इन्सपैक्टर अचानक दुकानदारों पर छापा मारा करते थे दिस से उनको बड़ी तकलीफ थी । लेकिन हमारी सरकार ने एक साल के लिए बतौर तजरुबे के वह बन्द कर दिये हैं । इस से सरकार को आमदनी ज्यादा होगी और व्यापारियों को भी चैन और आराम मिलेगा । हमारी सरकार ने 26 जनवरी से हिन्दी को स्टेट की सरकारी भाषा बना दिया है यह भी एक बहुत भारी कदम है अब सारा काम काज हिन्दी में होने लगेगा । तीसरी और चौथी श्रेणी के गवर्नमेंट कर्मचारियों को जो डीयरनेस अलाउन्स दिया गया है यह भी एक बड़ा सराहनीय और अच्छा काम किया हूँ । आशा है कि सरकार और भी तरक्की देने के बारे में फिर विचार करेगी ।

बिजली बोर्ड के काम में भी बड़ी तेजी से काम हो रहा है । हमारी सरकार ने 15 हजार ट्यूबवैलों को कनेक्शन दिये हैं लेकिन जिस कंस्ट्रिचुऐसी से मैं मैम्बर बन कर आया हूँ वहां 45 गांव ऐसे हैं जिन में किसी एक गांव के अन्दर भी बिजली नहीं है । मेरे इलाके में पानी खारा है न वहां पर कोई पीने के पानी का ही प्रबन्ध किया गया है । बजट के अन्दर न सड़कों के बारे में लिखा है कि उस एरिया में भी कोई सड़क वगैरह निकाली जायेगी । कम से कम जनाल रोड को डींग मैकसरान तक तो जरूर निकाल दिया

जाये ताकि मेरे इलाके के लोगों को आमदो-रफत में फायदा हो सके ।

चीफ मिनिस्टर साहिब ने कुछ अर्से पहले कारवान में यह एलान किया था कि ट्यूबवैल्ज बोरिंग करके सरकार अपने खर्चे से लोगों को मीठे पीने के पानी की सहूलियत देगी । लेकिन उसकी तरफ अभी तक सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया । तो मैं आपके हारा सरकार कौ याद दिलाना चाहता हूं कि वहू भी प्रान्त का एक हिस्सा है, इस लिए सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए ।

जहां तक तालीम का सवाल है हमारे यहां एक हायर सैकैन्डरी स्कूल है उस में कोई 1,800 के करीब लड़कों की तादाद है । वहां पर लड़कों की तादाद ज्यादा है और बिल्डिंग छोटी है इस लिए वहां लड़कों को बैठने में दिक्कत होती है । यह स्कूल शहर में वाकै है । अगर उस स्कूल की बिल्डिंग और जमीन को बेच कर शहर से बाहर जमीन मोल ले ली जाये, तो स्कूल की बिल्डिंग भी बन जायेगी और गवर्नमेंट का भी कोई खर्चा नहीं होगा । शहर वाली जमीन काफी मेंहगी बिकेगी । ऐसा होने से बच्चों की तालीम में काफी फायदा होगा ।

दूसरा एक मिडल प्राईमरी स्कूल है जिस में करीब 1, 800 के लड़कियों की तादाद है । उनकी बिल्डिंग काफी छोटी है जिस के कारण बच्चों को काफी दिक्कत होती है । वहां पर बच्चों को सेहन में बैठ कर पढ़ना पड़ता है जिस के कारण गर्मियों में और

सर्दियों में काफी तकलीफ होती है । इसलिए इस बिल्डिंग का भी जल्दी से जल्दी प्रबन्ध होना चाहिए । प्राईमरी स्कूल है उनके पास भी कोई सरकारी बिल्डिंग नहीं है वह भी पुरानी किराये पर चली आ रही है उसकी हालत बहुत खराब है । उसकी छतें कभी भी गिर सकती हैं और बच्चों का नुकसान हो सकता है । उसकी ओर सरकार को तवज्जुह अवश्य देनी चाहिए ।

**चौधरी कटार सिंह छोकर (सम्भालका ) :** डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान चन्द बातों की ओर दिलाने के लिए आज की चर्चा में भाग ले रहा है हमारे बजट में फाईनेन्स मिनिस्टर साहिबा ने अपनी बजट स्पीच प्रोहिबिशन की बाबत जिक्र किया है । प्रोहिबिशन को हरियाणा की सरकार एक फेज्ड प्रोग्राम के तहत लागू करेगी । सरकार के उस फैसले की बड़ी आशा से और बड़ी देर से हरियाणा की जनता इन्तजार कर रही थी और आज यह फैसला सिरें चढा है । हमें बड़ी खुशी हुई है और हरियाणा की जनता को बड़ी खुशी हुई है । इस फेज्ड प्रोग्राम की बाबत मैं सरकार से यह दरखास्त करूंगा कि हमारे इलाके में पानीपत तहसील में गान्धी स्मारक निधि हाई स्कूल है । यह न केवल हरियाणा में है बल्कि उतर भारत में पहला है । काश्मीर और हरियाणा रीजन में यह हरियाणा में वाकै है । तो मैं सरकार से यह दरखास्त करूंगा कि पहला फेज प्रोहिबिशन का विशेष तौर से हमारे इलाके से हो, क्योंकि वहां गान्धी जी की गान्धी स्मारक निधि भी बनी हुई है । उस इलाके में तुरन्त ही लागू किया जाये

। जब इस सात हम गान्धी जी सैन्चरी सैलीबरेशन मनाने जा रहे हैं और जनता की इसमें बड़ी भारी श्रद्धा है तो तुरन्त ही पहला फेज्ड प्रोग्राम हमारे इलाके से शुरू हो । हमारे इलाके में तुरन्त ही नशाबन्दी की जानी चाहिए । क्योंकि पहले ही मास ओपिनियन है और गांधी निधि के कर्मचारियों ने छोटा सा आन्दोलन चलाया हुआ है । उसके बहुत से कर्मचारियों द्वारा उस इलाके में बहुत जागृति पैदा की गयी है । इसलिए उस एरिया में सरकार को कोई कठिनाई नहीं आयेगी और यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा, अगर पहला फेज हमारे यहां से शुरू हो । अगर शराब पूरी तरह से बन्द नहीं कर सकते तो जो देहात हैं वहां से फौरी तौर पर ठेका उठा लिया जाए और नए ठेके किसी को न दिए जाएं अगर दिए जाये तो शहरों में या कस्बों में दिए जायें न कि देहात में ।

मैं खादर के इलाके से आ रहा हूँ । मेरी कस्टिचुंऐसी का तीन चौथाई भाग खादर का इलाका है । मेरी ही नहीं हरियाणा की कई कंस्टिचुएंसीज ऐसी हैं जिनमें तहसील की तहसील खादर हैं । मेरे जिले में करनाल और पानीपत जमुना से अफैक्टिड हैं अम्बाला का, रोहतक का और गुड़गांव का बहुत सा हिस्सा जमुना से अफैक्टिड है । जैसा कि और कई मैम्बरान ने अपनी मुसीबत बतलाई, मैं भी उसी मुसीबत में मुबतला हूँ । इस विषय पर कभी विचार तक नहीं गया हल ढूँढने की बात तो बाद में आती है । बहिन ओम प्रभा जी को पता है कि क्योंकि लोग इनके पास आए

हैं और मैं भी फाइनेंस मिनिस्टर को उस क्षेत्र में ले गया हूँ । निरीक्षण कराया है, इनको पता है कि हर साल कुछ परिवारों की जमीन जमुना से कट जाती है और कायदा कानून ऐसे हैं कि जब कभी भी रिकवरी होती है तो वह जमीन के मालिकों को नहीं मिलती बल्कि गांव शामलात को चली जाती है । मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो परिवार हर साल जिनकी जमीनें कट जाती हैं और बे जमीने हो जाते हैं उनको आज तक किसी किसम का रिलीफ नहीं दिया गया । और न ही कोई मुआवजा देने के लिए सोचा गया । वैसे दूसरे क्षेत्रों में यह देखा गया है कि बारिश की वजह से या अकाल पड जाने या कोई और मुसीबत आने से जब लोगों का नुकसान होता है तो उन्हें सरकार रिलीफ देती है लेकिन ऐसा कोई रिलीफ उन लोगों के लिए नहीं सोचा गया जिनकी जमीनें कट जाएं और वापिस कभी उनके पास लौट कर आए । वह लोग बिल्कुल ही उजड़ जाते हैं' उनकी तरफ सरकार को तवज्जुह देनी चाहिए । मैं समझता हूँ कि यह रिलीफ कुछ ही सालों के लिए देना पड़ेगा जब तक कि किशाऊ डैम पूरा नहीं बन जाता क्योंकि किशाऊ डैम के पूरा होने से जमुना से अफैक्टिड एरिया में काफी रिलीफ हो जाएगा । लेकिन किशाऊ डैम कब बनता है, उसके बनने में कितने साल लगते हैं' । यह कई स्टेट्स का मामला है और इसमें सेटर भी इनवाल्वड है । पता नहीं कितने साल लगेंगे तब कहीं जा कर यह बनेगा । इस लिए मैं सरकार से पुरजोर अपील करता दूँ कि वह इस तरफ ध्यान दे' । हम अब इन्तजार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं । मुझे याद है कि

पिछले बजट के वक्त भी कई मैम्बरान ने सुझाव दिया था तेकिन उस पर कोई गौर नहीं हुआ । मैइस वार भी सुझाव देकर उन मैम्बरान के साथ जिन्होंने इसकी चर्चा की है, इत्तफाक करता हूं । और अगर यह सरकार गौर न कर सकी उन परिवारों के लिए जो रोजगार हो जाते है बेसहारे हो जाते हैतो फिर हम हर वहू तरीका अपनाएंगे जिससे यह रिलीफ मिले । हम यह समझते हैं कि यूनाइटेड पंजाब में खादर का प्रिया अनरिप्रजेन्टिड था

**उपाध्यक्षा :** में आनरेबल मैम्बर से रिक्बैस्ट कहती हुं कि वे रेपिटिशन न करें ।

**चौधरी कटार सिंह छोकर :** किशाऊ ड्रैम पर सरकार शीध काम करना शुरु करे । लेकिन ड्रैम के बनने से पहले रिलीफ दें । ऐसी कोई स्कीम तैयार की जानी चाहिए । जहां तक फलड रिलीफ का ताल्लुक है इस सरकार ने खादर के एरिया को फिर कम रिलीफ दी है ।

ड्रेन नम्बर 2 सारे एरिया को फलडिड करता था । पिछले सालों में उसके लिए बजट भी बनाया गया लेकिन वहां पर काम नहीं हुआ । मगर हां, इस साल जो इंटरिम मैयर्ज ले कर काम हुआ है उससे लोगों में कुछ संतोष है और लोगों का विश्वास बढ़ा है कि इस साल ड्रेन के द्वारा एरिया फलड की जल्द में नहीं आएगा । इस थोड़े ग अर्से में जमुना का बन्द बनाया गया उससे भी लोगों

में संतोष है । लोगों को कुछ फलड रिलीफ भी मिला है जिसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं ।

इस एरिया में स्कूल और हास्पिटल्ज का कोई इंतजाम नहीं है । सड़कों का भी कोई इंतजाम नहीं हुआ । इनमें कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनके दोनों तरफ जमुना है और वहां पर महीनों पानी भरा रहता है । पहले कुछ बंध बनाए गए थे मगर बरसात की वजह से उनकी मिट्टी बह चुकी है । उनकी दुबारा मुरम्मत कराई जानी चाहिए । इन गाबो में सड़कों का कंस्ट्रक्शन कराया जाना चाहिए । इसी तरह छोटे बड़े स्कूल और डिसपेंसरीज भी इन इलाकों में देनी चाहिए । डिप्टी स्पीकर साहिबा, भै' आपके द्वारा फिर सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इस एरिया की तरफ ध्यान दिया जाए क्योंकि इस एरिया को बिल्कुल इग्नोर किया गया है ।

**वित्त मन्त्री :** डिप्टी स्पीकर साहिबा, हाउस का टाइम एक घंटा और बढ़ा दिया जाए ।

**उपाध्यक्षा :** अगर मैम्बर बोलना चाहते हों तो बढ़ाया जा सकता है ।

**चौधरी कटार सिंह छोकर :** मैअब कोआप्रेटिव की बाबत कुछ कहना चाहूंगा । मेरे सम्भालका हल्का के देहात के लिये जो मार्किटिंग सोसाइटी काम करती है वह 1964 में रजिस्टर हुई थी और 1964 में ही उस का बोर्ड आफ डायरेक्टर नामीनेट किया गया था । उस वक्त सै लेकर आज तक पांच साल के अर्से में एइतंक

बार भी उसका चुनाव नहीं हुआ और वही बोर्ड आफ डायरेक्टर जो उस वक्त नामीनेट हुआ था यही चला आ रहा हूँ । अगर यही बोर्ड फंक्शन करता भी रहे तो कोई एतराज नहीं था लेकिन इन्होंने इतनी बेजाबतगियां की है कि हद कर रखी हूँ । इ स बारे मे मैं वक्त वक्त पर सरकार का ध्यान दिलाता रहा हूँ कि लाखों रुपये का गबन हुआ है । जो मैम्बर हैं और प्रेजीडेंट है उन्हेंने दस्ती पैसे उठाये हुए हैं । लेकिन हैरानी की बात है कि उस सोसाइटी को जिसने लाखों रुपये का गबन कर रखा है 12 लाख रुपया और सरकार की तरफ से फर्टिलाइजर के लिये दे. दिया गया है जिस में से अधिक रुपया मिसएप्रोप्रीएट किया जा रहा है । आडिट रिपोर्ट कहती है कि तीन हजार वैग फांर्टलाइजर के मिसिंग पाए गए । बडी हैरानी की बात है कि इतनी हेराफेरी होते. हुए शी डिगर्टमेंट के कर्मचारी उस पर हाथ नहीं डाल सके । इसी तरह की एक और मिसाल वे सकता हूँ । मेरे गांव मे कुछ डाक त्नेटर बगैरा जाते हैऔर ऐसी सोसाइटी के नाम पर जाते है जिसका न वहां कोई मैम्बर है और न कोई ओफिस हैं, न प्रेजीडेंट है । कोआप्रेटिव डिपार्टमेंट रग ता शायद उससे कोई तांल्लुक न हो और खादी कमीशन एंड इन्डस्ट्रीज वार्ड वालों से उसका संबंध हॉगा । वहां पर खंडसारी का कोई फजी यूनिट खड़ा किया हुआ है और कितना पैसा पता नहीं उन्होंने खादी कमीशन से उसके नाम पर उठाया हुआ है । मे विश्राम से कह सकता हूँ कि वह काआप्रेटिव सोसाइटी मेरे गांव और क्षेत्र' में करी काम गी करती है और शायद उसके मैम्बर चडीगड के रहने वाले हो । मैंने उस



बारे में जानकारी की है और उस जानकारी के बाद पता लगा है कि ऐसी कुछ स्कीमें खादी बोर्ड की तरफ में होती है' जिन के बारे में बोर्ड और डिपार्टमेंट वाले जनता को कुछ बताते नहीं है' और करते यह हैं कि कार्ड फजी सोसाइटी खड़ी कर ली, लोन ले त्रिया और मिसएप्रोप्रीएट कर लिया । ऐसी और भी कई मिसाले है

**उपाध्यक्षा :** आपका टाइम हो गया है अब आप बैठ जाएं ।

**वित्त मन्त्री :** डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप एक घंटा ऐक्सटेंड कर दे ओर इन को बोल लेने दें अगर वह बोलना चाहते हैं ।

**उपाध्यक्षा :** पहले इसके कि मैं किसी और को बालने के लिये टाइम दूर मैं सैंस आफ दी हाउस लेना चाहती हूं कि क्या हाउस चाहता है कि टाइम एक घंटा के लिये ऐक्सटेड कर दिया जाए? तेकिन मैं यह कहना चाहती हूं कि आज यह दूसरी सिटिंग चल रही है और हम ने रिपोर्टरज़ की तरफ भी देखना है जो यह कार्यवाही लिख रहे हैं और अपसर साहिबान की तरफ भी देखना है । कल बजट पर फिर बहस हो रही है और अमी जो मेरे पास लिस्ट है उसमें चौधरी नेकी राम जो का नो नाम है

**आवाजें :** नहीं और भी बोलना चाहते हैं अभी ।

**वित्त मन्त्री :** आप आध घंटा ही बढ़ा दें ।

**मुख्य मन्त्री :** ठीक है । अभी कुछ मैम्बर बोलेंगे ही इस लिये आध घंटा बढ़ा दें । उपाध्यक्षा रू क्या हाउस की सैसे है कि हाउस का टाइम आध घंटा बढ़ा दिया जाए । आवाजें. हां जी बढ़ा दें ।

**उपाध्यक्षा :** हाउस आध घंटा के लिये ऐक्सटैडं किया जाता है ।

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET (Resumption)  
(concl'd)

चौधरी नेकी राम (नरवाना ) रू डिप्टी स्पीकर साहिबा, हाउस में सूबा का बजट पेश है और इस पर बहुत सी तकरीरें हुई हैं । बजट में सूबा के खर्च और आमदनी का इन्तजाम जिस खूबसूरती से दिखाया गया है वह काबिले तारीफ है और मैं समझता हूं और मानता हूं कि मजमूई तौर पर यह जो बजट पेश हुआ है काबिले तारीफ है लेकिन इस में कुछ खामियां भी हैं । अगर वह न होती तो यह निहायत शानदार बजट होता । इस के इलावा कुछ बातें और कहना चाहता हूं और वह यह है कि चौधरी रणबीर सिंह जी नेचंडीगढ़ और भाखड़ा का जिक्र किया और यह खदशा जाहिर किया कि कार्ड और तरह की हकूमत पंजाब में आएगी जिस से झगड़ा बढ़ने का अंदेशा है । मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है । चंडीगढ़ और भाखड़ा हमारा है और इस का फैसला हो चुका है ( तालियां ) इसके मुताल्लिक हमारे इरादे मजबूत हैं और उन में कोई तबदीली नहीं हो सकती चाहे किसी किसम की गवर्नमैट पंजाब में आए । दूसरे यह कि मुलाजमीन की भरती का जितना किया गया । मैं उनसे एक कदम आगे जाना चाहता हूं ।

हरियाणा सरकार के जो मुलाजमीन हैं और जिम्मेदार औहदों पर हैं उन के बारे में बहुत आदमी मिले जो चर्चा करते हैं कि उनकी वफादारी कहीं और है । जो आदमी यहां माकूल तनख्वाह लें और जिनको यहां हर तरह का आराम मिले अगर उनकी हमदर्दी और वफादारी किसी और जगह हो. तो उन से पूछ लेना चाहिए कि आपकी जहां हमदर्दी और वफादारी है वहाँ वह जा सकते हैं और उनको वहां भेज देना चाहिए ताकि उन का भला हो और इस सूबा की सरकार का भी भला हो । इसके इलावा अपोजिशन वो बारे में जो बात कही गई कि वह यहां से चले गए हैं उस के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि अगर वह चले न जाते तो और क्या करते । वह अपने गलत काम छुपाने के लिये यहां से चले गए हैं । बात सीधी है जब बैठते थे. तो सिवाये नुक्ताचीनी और एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के कोई खास बात उनकी तरफ से नहीं देखी गई । दूसरों की बुराई करना और अपने आप को बड़ा जाहिर करना मैं अच्छा नहीं समझता ।

अब मैं बजट के ऊपर आता हूं । आप सब जानते हैं कि किसान इस सूबा को रीढ़ की हड्डी और हमारी सोसाइटी का जरूरी अंग हैं और उनके बगैर यह सूबा और देश मजबूत नहीं बन सकता । इस बजट में किसान की बेहतरी के लिये कई बातें की गई हैं और काफी रकम रखी गई है लेकिन मैं समझता हूं कि तनासब के लिहाज से यह रकम बहुत कम है । अगर किसान की बेहतरी के लिये उसै ऊंचा उठाने के लिये और उसे खुशहाल बनाने के लिये

काम किया जाए तो मैं समझता हूँ कि यह सरकार का बहुत बड़ा काम होगा । मैं मानता हूँ कि अच्छे बीज, टैक्टर्ज और दूसरी सहूलियतें देने के लिये इस मौजूदा सरकार ने पिछले आठ नौ महीने में अच्छा काग किया है और इससे किसानों को फायदा पहुंचा है लेकिन तनासब के लिहाज से थोड़ी मिकदार में है । सरकार ने जो सरप्लस जमीन निकाली है उस बारे में मैं अपने इलाका नरवाना की ही बात करता हूँ कि उसकी जो अलाटमेंट हुई है वह गलत और बोगस हुई है । अगर ईमानदारी से अच्छे अफसर लगा कर उसकी इंक्वायरी की जाए तो बड़ा भारी स्कैंडल मिलेगा । ऐसे आदमियों को जमीनें दी गई है जिन्हें ने कभी जमीन काश्त नहीं की और .न. ही जिन के बाप दादा ने काश्त की और जिनका दूर से भी जमीन से वास्ता नहीं है दूसरे काम करते हैं । उन को मुजारे जाहिर करके जमीन दी गई है । मेरी जोरदार अलफाज में सरकार से मांग है कि ऐसी बोगस कार्यवाही ही की फौरी तहकिकात कराई जानी चाहिए । पी.डबल्यू. डी की सैकड़ों एकड़ जमीन है उसको गलत आदमियों ने यानी लालची और बेअसूले आदमियों ने दबाया हुआ है और नाजायज फायदा उठा रहे हैं जिससे सरकार को लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है । यह बात मैंने पहले भी सरकार के नोटिस में लाई थी लेकिन मेरे नोटिस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया । इस तरफ सरकार को फौरी तौर पर कार्यवाही करनी चाहिए ताकि जो सरकार को नुकसान दो रहा है वह न हो ।

अब महकमा नहर के बारे में कहना चाहता हूँ । महकमा नहर में जो काम हो रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि देहाती लोग उससे खुश नहीं हैं । जो निचली सतह पर काम होते हैं वे इतने बुरे हैं कि हर आदमी उससे नफरत किए बर्गर नहीं रह सकता । इस महकमा की तरफ सरकार की खास निगरानी की जरूरत है ताकि जो खराबो हों उसकी दूर किया जा सके । इस महकमा में रिश्वतसतानी की बीमारी बहुत फैलती जा रही है । दलालों ने रिश्वत का एक नया ढंग निकाल लिया है । जिन दलालों को आस पास के इलाकों में रिश्वत करने के लिए जगह नहीं मिली है वह नरवाना में आ गये हैं । उनका यह पेशा है कि वे आफिसर्ज के पास जाते हैं और घंटों उन के पास बैठे रहते हैं । ये लोग माने हुए रिश्वतखोर हैं । अगर ये लोग हमारे आफिसर्ज के पास घंटों बैठे रहें तो जनता को कैसे यकीन हो सकता है कि हमारे आफिसर्ज ठीक हैं, ईमानदार हैं । एक गांव में एक दलाल ने सेकड़ो बीघे जमीन बिकवा रखी है सिक यह कहकर कि जो नहर का मोघा लगा है यह मैंने मगवाया है । इन्होंने उस गांव से दो दो मन खोआ निकलवाया और कहा कि यह खोआ ख।कर मैं मजबूत हो जाऊंगा और मजबूत होकर और ज्यादा माघे लगवा दशा । मेरी सरकार से दरखास्त है कि इस बात की इन्क्वायरी सी. आई. डी. के जरिये कराई जाये और इस खतरनाक बीमारी को रोका जाये ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, हम समझते थे कि नरवाना में कहीं कोई शराब नहीं पी जाती थीं कोई रिश्वत नहीं ली जाती थी लेकिन अब वहां पर यह बीमारी बड़ी तेजी से फैलती जा रहा है, इसको दूर करन। निहायत जरूरी है । इसके बाद जब सवाल रहा कभी का । इस इलाके

में बहुत कमी है, नरवाना को तौ सरकार ने लावारिस समझ रखा है । वहां पर न कोई फ़ैक्ट्री है, न कोई कल-कारखाना हूँ । सड़कें तो काबिले रहमहै, ट्युब-वैलज भी नहीं है, तालीम' भी नहीं है । हरियाणा में अगर सबसे कम तालीम है तो नरवाना डुलाके में है । बिजली के लिहाज से भी दूसरों से पिछड़ा हुआ हूँ । जो इलाके ' इस तरह से पिछड़े हुए है' अगर सरकार उन को दूसरे एडवांस्ड इलाकों के बराबर लाने की कोशिश करे तो मैं कह सकता हूँ कि सरकार ठीक काम कर रही है । पिछले आठ नौ महीने के दौरान जो हालात सूबे के अन्दर रहे हैं वे नारमल रहे हैं । दूसरी जगहों पर कहीं एजीटेशन हुए है, और कई किसभ का शोर-शराबा हुआ है, लेकिन इन हालात से हमारा सूबा ठीक ही रण । हमारी सरकार इमानदारी से नेकनीयती से सूबे को ऊपर उठाने की कोशिश करती रही लेकिन हमारे अपोजीशन के साथियों

ने कदम कदम पर रुकावट डालने की कोशिश की ताकि सरकार अच्छे काम न कर सके और लोगों के सामने सरकार न तो सके । मैं मुख्य मन्त्री श्री बंसी लाल जी को मुबारिकबाद देता है कि उन्होंने बड़ी मन्त्री के साथ रुसको सम्भाल लिया और अमनोअमान कायम करने की हूर मुमकिन कोशिश की । महकमा बिजली के वारे में चन्द शब्द कहना चाहना हूं । इस महकमा ने चौधरी सूबे सिंह की रहनुमाई में, जो डस महकमा के चेयरमैन हैं, एक शानदार काम किया है । पन्द्रह हजार ट्युब-वैलज लगाकर बड़ा अच्छा कदम उठाया है । इस महकमे के कारनामो को ध्यान में रखते हुए दूसरे महकमों को भी नेकनीयती के साथ काम करना चाहिए । मैं समझता हूं कि मौजूदा सरकार अच्छी है, इस पर हमें विश्वास है, पक्का भरोसा है कि यह सूबे को ऊंचा उठाने मैं हर मुमकिन कोशिश करेगी । इन शब्दों के साथ मैं आपक- शुक्रिया अदा करता हूं ।

चौधरी चन्बा सिंह (नीलोखेडी ) रू डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस बजट पर तकरीबन सब मैम्बरों ने अपने अपने विचार प्रकट किये । हमारी छोटी सी स्टेट अभी अभी बनी है और इसके सामने काफी समस्याएं हैं । हिन्दुस्तान की दूसरी स्टेटों के मुकाबले इसके जराय काफी अच्छे है, लेकिन फिर भी इसके सामने काफी समस्यायें हैं । यहां के ज्यादातर लोग गांवों में बसते हैं और खेती-बाड़ी का काम करते हैं । इन लोगों में कूरछ ऐसे लोग भी

है' जिनके पास जमीन नहीं है, मकान नहीं है, दूकान नहीं है । अगर कोई आदमी कारखाना लगाने के लिए लोन वगैरा लेन) चाहे तो उसके पास जमानत देने के लिए कुछ नहीं होता । डस वर्ग के बारे में सदन में काफी चर्चा हुई है । जो बजट हाउस में पेश किया गया है, अगर इसको ध्यान से देखा जाये तो पता चलेगा कि इसमें काफी कमी है । इसमें वह वह जो साधनहीन है बिलकुल फायदा नहीं उठा सकता । आबादी के बीस सात्र गुजर जाने के बाद भी उनकी हालत में बहुत कम तबदीली आई है । वैसे तो आज भी खेती-बाड़ी के ऊपर बजट का 50 फी सदी से ज्यादा हिस्सा रखा है, इसके बावजूद भी इस तरफ खास ध्यान देने की जरूरत है । मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चर की जितनी भी प्रोडक्शन होती है उसकी कीमत फिक्स करने का पता नहीं सरकार के पास क्या तरीका है? पिछले बजट सेशन में भी मैने. यह कहा था और अब भी कह रहा हूं कि सब लोगों को मजदूरी ठीक तरीके से मिले जो कि प्रजातंत्र राज में मिलनी चाहिए । एग्रीकल्चर में जमींदार मजदूरी करके जितनी प्रोडक्शन करते हैं, हमें पता नहीं उसकी कीमतें किस

तरह से मुकर्रर करते है । आज जबकि अनाज बाहर से मंगवाया जा रहा हूँ, इसके बावजूद भी अनाज की कीमतें पिछले माल के मुकाबले में काफी रही हैं । कितनी कीमतें फसल के टाईम पर थीं यानी 50- 60 रुपये प्रति क्विंटल थी लेकिन आज 116 रुपये प्रति



क्विटल तक गेहूँ बिक रहा है । यह बहुत ज्यादा फर्क है, थोड़े से अर्से के अन्दर इतना ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए । किसान को दस्तकारी के लिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए या ट्यूब-वैल लगाने के लिए कर्जे की जो सहलियते मिलती हैं उनमें आठ हजार, दस हजार या पन्द्रह हजार रुपये तक लोन मिल सकता है चाहे वह किसान दो लाख रुपये की जमीन रखता हो । इसके मुकाबले में इंडस्ट्रियलिस्ट्स को 25 हजार रुपया या इससे भी ज्यादा रुपया कर्जे के तौर पर दिया जाता है । यह बहुत ज्यादा फर्क है । जो बड़ी इंडस्ट्रीस हैं जैसे कपड़े की इंडस्ट्री हैं, दवाईयों की इंडस्ट्री हैं या दूसरी दस्तकारी की इंडस्ट्रीज हैं, उनकी कितनी भी प्रोडक्शन हो, कीमत काफी ज्यादा होती है । इंडस्ट्रीज का बना हुआ बूट जिसकी कीमत रु 4 0. 95 पैसे लिखी होती है, 32 रुपये में मिल जाता है । मेरे कहने का मतलब है कि हर मजदूर को उसकी मेहनत की मजदूरी मिलनी चाहिए लेकिन किसान की मेहनत की पूरी मजदूरी नहीं दी जाती । यह जो फर्क है इससे एक वर्ग का शोषण होता है । जो वर्ग मेहनत करता हूँ, जिसके पास

माना बुद्धि कम है मगर जो जिस्मानी मेहनत करता है, जो चीज पैदा करता है उसको उसकी पैदावार की पूरी कीमत नहीं मिलती । इसलिए सरकार से मेरी प्रार्थना है कि उसे इस सारे के सारे तनासब को देखना चाहिए और चौक करना चाहिए ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, बिजली के सम्बन्ध में मे गई अज यह है कि इसकी भी अभी खासी कमी है । इसके अभी भी काफी बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि हरेक क्षेत्र में बिजली की जरूरत है । खेती के लिए बिजली की जरूरत है, घरों में जलाने के लिए बिजली चाहिए और इंडस्ट्री के लिए तो इसकी बहुत ही आवश्यकता है । इसके लिए सरकार को चाहिए कि वह जगाधरी तथा फरीदाबाद के थर्मल प्लांट्स को जल्दी से जल्दी लगाए तथा ब्यास डैम के काम को भी जल्दी से जल्दी पूरा करवाने के लिए कदम उठाए । डिप्टी स्पीकर साहिबा, पहले प्रोग्राम के मुताबिक ब्यास डैम पर कोई दो सौ करोड़ रुपया खर्च होना था और सन् 1970— 1972 तक शायद यह काम पूरा हो जाना था । मगर आज पोजीशन यह है कि दो तीन करोड़ तो सालाना सूद देने तथा कर्मचारियों की तनखाह पर खर्च हो रहा है और काम का जहां तक सम्बन्ध है, वह मैं समझता हूं सन् 1985 से पहले मुश्किल से ही पूरा होगा । फिर, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मजे की बात यह है कि व्यास प्रोजैक्ट बोर्ड में बिजली का ज्ञान रखने वाला न तो कोई औफिशियल है और न कोई नौन-औफिशियल है, सारे के सारे इरीगेशन इंजीनियर ही हैं, जबकि इस प्रोजैक्ट का मकसद 96 पर सैन्ट बिजली और 4 पर सैन्ट पानी मुहैया करना है । इसके अलावा 5, 6 साल से एक. एस. ई. और 8 एग्जैक्टिव इंजीनियरज डिजाइन बनाने लगे हुए हैं अगर आज तक वह डिजाइन ही तैयार नहीं हो पाता । इस तरह

से तो मैं समझता हूँ कि पता नहीं कितना अर्सा और इस डैम को बनने में लग जाएगा । इस लिए सरकार को चाहिए कि वह इस तरफ जरा ध्यान दे ताकि काम जल्दी से जल्दी हो सके । आज सरकार कह तो रही है कि उसने 15-20 हजार ट्यूब-वैलों को कुनैक्शन दे दिए हैं और आंयदा आने वाले सालों में ये और ज्यादा कुनैक्शन में बहुत कमी है, नरवाना को तो सरकार ने लावारिस समझ रखा है । वहां पर न कोई फ़ैक्ट्री है, न कोई कल-कारखाना हूँ । सड़कें तो काबिले रहम है, ट्यूब-वैलज भी नहीं है, तालीम भी नहीं है । हरियाणा में अगर सबसे कम तालीम है तो नरवाना डुलाके में है । बिजली के लिहाज से भी दूसरों से पिछड़ा हुआ हूँ । जो इलाके ' इस तरह से पिछड़े हुए है ' अगर सरकार उन को दूसरे एडवांस्ड इलाकों के बराबर लाने की कोशिश करे तो मैं कह सकता हूँ कि सरकार ठीक काम कर रही है । पिछले आठ नौ महीने के दौरान जो हालात सूबे के अन्दर रहे हैं वे नारमल रहे हैं । दूसरी जगहों पर कहीं एजीटेशन हुए है, और कई किसभ का शोर-शराबा हुआ है, लेकिन इन हालात से हमारा सूबा ठीक ही रण । हमारी सरकार इमानदारी से नेकनीयती से सूबे को ऊपर उठाने की कोशिश करती रही लेकिन हमारे अपोजीशन के साथियों ने कदम कदम पर रुकावट डालने की कोशिश की ताकि सरकार अच्छे काम न कर सके और लोगों के सामने सरकार न तो सके । मैं मुख्य मन्त्री श्री बंसी लाल जी को मुबारिकबाद देता है कि उन्होंने बड़ी मन्त्री के साथ रुसको सम्भाल लिया और अमनोअमान कायम करने की हूर मुमकिन

कोशिश की । महकमा बिजली के वारे में चन्द शब्द कहना चाहना हूं । इस महकमा ने चौधरी सूबे सिंह की रहनुमाई में, जो उस महकमा के चेयरमैन हैं, एक शानदार काम किया है । पन्द्रह हजार ट्युब-वैलज लगाकर बड़ा अच्छा कदम उठाया है । इस महकमे के कारनामो को ध्यान में रखते हुए दूसरे महकमों को भी नेकनीयती के साथ काम करना चाहिए । मैं समझता हूं कि मौजूदा सरकार अच्छी है, इस पर हमें विश्वास है, पक्का भरोसा है कि यह सूबे को ऊंचा उठाने में हर मुमकिन कोशिश करेगी । इन शब्दों के साथ मैं आपक- शुक्रिया अदा करता हूं ।

**चौधरी चन्बा सिंह (नीलोखेडी) :** डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस बजट पर तकरीबन सब मैम्बरो ने अपने अपने विचार प्रकट किये । हमारी छोटी सी स्टेट अभी अभी बनी है और इसके सामने काफी समस्याएं हैं । हिन्दुस्तान की दूसरी स्टेटों के मुकाबले इसके जराय काफी अच्छे है, लेकिन फिर भी इसके सामने काफी समस्यायें हैं । यहां के ज्यादातर लोग गांवों में बसते हैं और खेती-बाड़ी का काम करते हैं । इन लोगों में कृरछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास जमीन नहीं है, मकान नहीं है, दूकान नहीं है । अगर कोई आदमी कारखाना लगाने के लिए लोन वगैरा लेन) चाहे तो उसके पास जमानत देने के लिए कुछ नहीं होता । उस वर्ग के बारे में सदन में काफी चर्चा हुई है । जो बजट हाउस में पेश किया गया है, अगर इसको ध्यान से देखा जाये तो पता चलेगा कि इसमें काफी कमी है । इसमें वह वह जो साधनहीन है

बिलकुल फायदा नहीं उठा सकता । आबादी के बीस सात्र गुजर जाने के बाद भी उनकी हालत में बहुत कम तबदीली आई है । वैसे तो आज भी खेती-बाड़ी के ऊपर बजट का 50 फी सदी से ज्यादा हिस्सा रखा है, इसके बावजूद भी इस तरफ खास ध्यान देने की जरूरत है । मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चर की जितनी भी प्रोडक्शन होती है उसकी कीमत फिक्स करने का पता नहीं सरकार के पास क्या तरीका है? पिछले बजट सेशन में भी मैंने यह कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि सब लोगों को मजदूरी ठीक तरीके से मिले जो कि प्रजातंत्र राज में मिलनी चाहिए । एग्रीकल्चर में जमींदार मजदूरी करके जितनी प्रोडक्शन करते हैं, हमें पता नहीं उसकी कीमतें किस तरह से मुकर्रर करते हैं । आज जबकि अनाज बाहर से मंगवाया जा रहा हूँ, इसके बावजूद भी अनाज की कीमतें पिछले माल के मुकाबले में काफी रही हैं । कितनी कीमतें फसल के टाईम पर थीं यानी 50- 60 रुपये प्रति क्विंटल थी लेकिन आज 116 रुपये प्रति क्विंटल तक गेहूँ बिक रहा है । यह बहुत ज्यादा फर्क है, थोड़े से अर्से के अन्दर इतना ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए । किसान को दस्तकारी के लिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए या ट्यूब-वैल लगाने के लिए कर्जे की जो सहलियते मिलती हैं उनमें आठ हजार, दस हजार या पन्द्रह हजार रुपये तक लोन मिल सकता है चाहे वह किसान दो ताख रुपये की जमीन रखता हो । इसके मुकाबले में इंडस्ट्रियलिस्ट्स को 25 हजार रुपया या इससे भी ज्यादा रुपया कर्जे के तौर पर दिया जाता है । यह बहुत ज्यादा फर्क है । जो बड़ी इंडस्ट्रीस हैं जैसे

कपड़े की इंडस्ट्री हैं, दवाईयों की इंडस्ट्री हैं या दूसरी दस्तकारी की इंडस्ट्रीज हैं, उनकी कितनी भी प्रोडक्शन हो, कीमत काफी ज्यादा होती है । इंडस्ट्रीज का बना हुआ बूट जिसकी कीमत रु 40.95 पैसे लिखी होती है, 32 रुपये में मिल जाता है । मेरे कहने का मतलब है कि हर मजदूर को उसकी मेहनत की मजदूरी मिलनी चाहिए लेकिन किसान की मेहनत की पूरी मजदूरी नहीं दी जाती । यह जो फर्क है इससे एक वर्ग का शोषण होता है । जो वर्ग मेहनत करता हूँ, जिसके पास माना बुद्धि कम है मगर जो जिस्मानी मेहनत करता है, जो चीज पैदा करता है उसको उसकी पैदावार की पूरी कीमत नहीं मिलती । इसलिए सरकार से मेरी प्रार्थना है कि उसे इस सारे के सारे तनासब को देखना चाहिए और चौक करना चाहिए ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, बिजली के सम्बन्ध में मे गई अज यह है कि इसकी भी अभी खासी कमी है । इसके अभी भी काफी बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि हरेक क्षेत्र में बिजली की जरूरत है । खेती के लिए बिजली की जरूरत है, घरों में जलाने के लिए बिजली चाहिए और इंडस्ट्री के लिए तो इसकी बहुत ही आवश्यकता है । इसके लिए सरकार को चाहिए कि वह जगाधरी तथा फरीदाबाद के थर्मल प्लांटस को जल्दी से जल्दी लगाए तथा ब्यास डैम के काम को भी जल्दी से जल्दी पूरा करवाने के लिए कदम उठाए । डिप्टी स्पीकर साहिबा, पहले प्रोग्राम के मुताबिक ब्यास डैम पर कोई दो सौ करोड़ रुपया खर्च होना था और सन् 1970— 1972 तक शायद

यह काम पूरा हो जाना था । मगर आज पोजीशन यह है कि दो तीन करोड़ तो सालाना सूद देने तथा कर्मचारियों की तनखाह पर खर्च हो रहा है और काम का जहां तक सम्बन्ध है, वह मैं समझता हूं सन् 1985 से पहले मुश्किल से ही पूरा होगा । फिर, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मजे की बात यह है कि व्यास प्रोजैक्ट बोर्ड में बिजली का ज्ञान रखने वाला न तो कोई औफिशियल है और न कोई नौन-औफिशियल है, सारे के सारे इरीगेशन इंजीनियर ही हैं, जबकि इस प्रोजैक्ट का मकसद 96 पर सैन्ट बिजली और 4 पर सैन्ट पानी मुहैया करना है । इसके अलावा 5, 6 साल से एक. एस. ई. और 8 एग्जैक्टिव इंजीनियरज डिजाइन बनाने लगे हुए हैं अगर आज तक वह डिजाइन ही तैयार नहीं हो पाता । इस तरह से तो मैं समझता हूँ कि पता नहीं कितना अर्सा और इस डैम को बनने में लग जाएगा । इस लिए सरकार को चाहिए कि वह इस तरफ जरा ध्यान दे ताकि काम जल्दी से जल्दी हो सके । आज सरकार कह तो रही है कि उसने 15-20 हजार ट्यूब-वैलों को कुनैक्शन दे दिए हैं और आंयदा आने वाले सालों में ये और ज्यादा कुनैक्शन देंगे मगर मैं सरकार से निवेदन कर दूँ कि बिजली की इतनी आवश्यकता है, खेती के लिए, दस्तकारी के लिए, घरों में जलाने के लिए, और आने वाले समय में लोगों की इसके लिए इतनी मांग आएगी कि सरकार उसे पूरा नहीं कर पायेगी और कनैक्शन दिए हुए तथा मोटरें लगी हुई ही रह जाएंगी यदि इसने जगाधरी तथा फरीदाबाद के प्लांटस को जल्दी नहीं लगाया और ब्यास प्रोजैक्ट के काम को शीघ्र खत्म नहीं करवाया ।

इसके बाद, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं टैक्नीकल एजुकेशन के सम्बन्ध में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ । जहां तक मैं समझता हूँ इसमें ज्यादा पैसा बिल्डिंग के ऊपर ही खर्च किया गया और लोगों को बहुत कम फायदा सरकार दे पाई है क्योंकि यदि आज देखा जाए तो बिल्डिंग बनी हुई तो ज्यादा नजर आती है मगर जो लोग ट्रेनिंग लेकर गए हैं वे कहीं दिखाई नहीं देते । पता नहीं क्या करते हैं या क्या नहीं करते हैं । फिर जो लोग आइ. टी. आइज में या पौलिटैक्नीक में ट्रेनिंग लेने आते हैं उनका उद्देश्य यही होता है कि ट्रेनिंग लेकर वे नौकरी करेंगे । जिस उद्देश्य से सरकार ने इन संस्थाओं को चालू किया था वह नज़ा नहीं हो पाया है । इसकी ओर सरकार को ध्यान देनेकी जरूरत है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, नीलोखेडी में एक पुराना होस्टल था । उसमें कई हजार लड़के ठहर सकते थे । परन्तु पता नहीं उसे प्रयोग न करके सरकार ने वहां एक और नया होस्टल बना दिया जिसमें लगभग डेढ़ हजार लड़की के ठहरने की व्यवस्था की गई है जबकि उस पुराने होस्टल को अब भी होमगार्ड और एच. ए. पी वाले बड़े मजे से प्रयोग कर रहे हैं । पता नहीं कितने लाख रुपया उस होस्टल पर फजूल ही सरकार ने खर्च कर दिया है । तो इस ओर भी सरकार को ब्यान देना चाहिए ताकि जनता का पैसा अच्छी तरह से इस्तेमाल हो सके ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, अब मैं सड़कों के बारे में कुछ बातें सरकार के सामने रखना चाहता हूँ । यह तो ठीक है कि सरकार टैक्स



नहीं लगाती और इसके पास पैसों की कुछ कमी भी है मगर जहां यह और जगह काम कर रही है वहां सड़कों की ओर भी इसे ध्यान देना चाहिए । आज के वैज्ञानिक युग में सड़कों की बहुत भारी जरूरत है । मेरे इलाके में, डिप्टी स्पीकर साहिबा, जी. टी. रोड, जो कि सदियों से चली आ रही है, और एक दो और छोटी 2 सड़कों के सिवाय कोई सड़क नहीं है ।... (विधन) एक सड़क 12- 14 मील की नीलोखेडी ब्लाक ने 1953 में, जब वह बना ही था, बनाई थी एक तीन फर्लांग की तौड़ी से बुटाना गांव में और इसी तरह एक तीन फर्लांग की अमीन गांव में बनी है । एक सड़क तौड़ी से सगा जो कि कोई सात मील की है, को बनाने के लिए लोगों ने 22 जून, 1966 को 40 हजार रुपये दाखिल भी करा दिये थे मगर बावजूद हमारी कोशिशों के हमारे पैसों को ही उस सड़क को बनाने के लिए खर्च नहीं किया जा रहा है । इसी तरह 22 जून, 19 ह ह कोही कासा रोड पर ईजन थली नामक सड़क को जो कि लगभग तीन फर्लांग की होगी, बनाने के लिए पांच हजार रुपया जमा कराया गया थामगर उसका भी अभी तक कुछ नहीं बना । यह एक एप्रोच रोड है और वन -फोर्थ स्कीम के अंडर यह सड़क बननी थी, मगर अभी तक नहीं बनी । एक सड़क कोई सात फर्लांग की पुजम गांव में बननी शुरू तो हो गई थी मगर फिर काम बंद हो गया है, पता नहीं क्यों । इसी तरह कासा रोड से एक सड़क, डाबरथला साबी जो कमालपुर गांव से पौने दो मील है, बननी थी । दो साल से हमने इसके लिए भी 22 हजार रुपया लोगों से इकट्ठा करके पी. डब्ल्यू. डी. वालों को दिया हुआ है

मगर इस सड़क पर भी अभी तक काम शुरू नहीं हुआ । पता नहीं क्या वजह है? डिप्टी स्पीकर साहिबा, हम तो कहते हैं कि यदि पैसे की कमी की वजह से काम नहीं किया जा रहा है तो आप हमारे से और पैसा लें, हम देने को तैयार हैं, मगर काम तो शुरू किया जाए । मैं मानता हूँ कि सरकार ने खेती बाड़ी को बढ़ावा देने के लिए, दस्तकारी को उन्नति की ओर ले जाने के लिए, लोगों को शिक्षा देने आदि के लिए काफी कुछ किया है मगर मुझे अफसोस है कि पी. डब्ल्यू. डी. का काम अभी तक तसल्ली बख्श नहीं हो पाया है, इसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, चाहे उसे ना! टैक्स लगाने पड़े या चाहे गवर्नमेंट आफ इंडिया से मदद लेनी पड़े । सड़कों की बढ़ती हुई मांग को सरकार को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि इससे न सिर्फ लोगों को फायदा होगा बल्कि सरकार को भी फायदा होगा । सड़कों के बनने से न सिर्फ पैदावार बढ़ेगी बल्कि, जैसा बहिन शारदा जी ने कहा था, गांव और शहर के बीच जो आज दूरी बनी हुई है वह भी दूर होगी । पैदावार बढ़ने से न सिर्फ हरियाणा की जनता, हरियाणा प्रदेश को ही फायदा है बल्कि सारे देश को फायदा है । इसलिए सरकार को इस तरफ जरूर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, सरकार का कर्नाल में शुगर मिल लगाने का प्रोग्राम था परन्तु रुह मिल अभी तक नहीं लगी । फैसला तो वै से ज्वाइंट पंजाब में हो गया था मगर आज तक वह कारखाना नहीं लग पाया । आज आप देखते हैं कि लोगों को चीनी की

कितनी किल्लत है । यदि किसी आदमी के यहां ' शादी भी हो तो भी 50 किलो या 100 किलो का परमिट न को— आप्रेटिव डिपार्टमेंट से न सिविल सप्लाय डिपार्टमेंट से मिलता है । लोगों के पास गन्ना होने के बावजूद भी इस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है । सरकार को उन्हें वहां मिल लगा कर इस मुसीबत से छुड़ाना चाहिए । इसके साथ ही साथ, सरकार से मेरी यह भी प्रार्थना है जैसा मैंने पहले कहा कि वह देखे कि किसान को उसकी चीज की ठीक कीमत मिले । इस वार किसान को गन्ने की बहुत कम कीमत दी गई । अगर सरकार चाहती है कि राज्य में अमन रहे, चौन रहे तो इसे इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए वरना मैं बता दूँ कि अब किसान भी जाग उठा है । इ स दफा आप जानते हैं 'काफी दिन तक लोग हड़ताल पर रहे । वे भी अपने कर्ग्यों का पालन करने के साथ साथ आई धकारो के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हैं ताकि उनके साथ न्याय हो सके । तो मुझे उम्मीद है कि सरकार इन स ब बातों को ध्याने म रखते हुए करनाल में जल्दी ही चीनी की मिल को लगाएगी । इससे भी, डिप्टी स्पीकर साहिबा, न सिर्फ हरियाणा के रहने वाले लोगो ' तथा हरियाणा राज्य को फायदा होगा बल्कि सारे देश को फायदा होगा क्योंकि सरप्लस चीनी को बाहर भेज कर फौरन एक्सचेन्ज कमाई जा सकती है ।

इसी तरह, डिप्टी स्पीकर साहिबा, दूसरे कारखाने लगाकर भी हमार राज्य अपने लिए काफी पैसा कमाते हुए देश के लिए फौरेन

एक्सचेन्ज हासिल कर सकता है । आज हरियाणा में आप जानती हैं काफी पशु' पाया जाता है । यदि यहां चमड़े का कारखाना खोल दिया जाए तो काफी फोरेन एक्स- चेन्ज कमाई जा सकती है । दूसरे रीसोरसिज भी यहां काफी हैं और कई तरह की इंडस्ट्रीज यहां लग सकती हैं यदि हमारी सरकार अपने यहां के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स को जो कि कलकत्ता और बम्बई जैसे बड़े बड़े शहरों में बैठे हैं निमंत्रण दे, उन्हें कुछ सहूलियते दे, और यहां इंडस्ट्रीज लगाने के लिए कहे । सरकार कुछ मिले पब्लिक सैक्टर में भी लगा सकती है । हिसार में, डिप्टी स्पीकर साहिबा, कपास बहुत होती है और कपड़ा मिल वहां कामयाब हो सकती है । अगर इस तरह से हो जाए, तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं समझता हूं कि हरियाणा जो एक छोटी सी स्टेट है और अभी तक देश में पिछड़ी हुई मानी जाती है वह काफी उन्नति कर सकती है और नम्बर एक बन सकती है । सरकार को फिर लोगों के ऊपर टैक्स नहीं लगाने पड़ेंगे, इसके पास खूब पैसा आएगा और लोग भी खुशहाल होंगे ।

इसी तरह बसों से भी डिप्टी स्पीकर साहिबा, काफी पैसा कमाया जा सकता है । सरकार ने अधिक वो' चराने के लिए इस वर्ष कवि पैदा दिपा है लिए सरकार को भविष्य में काफी आमदनी होगी ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा अब मैं थोड़ा सा जिक्र अपने हल्के में एजूकेशन के बारे में करना चाहता हूं मेरे हल्के में एजूकेशन की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है और लड़कियों की

एजुकेशन की ओर तो विशेष रूप से कोई ध्यान नहीं दिया जाता है । मेरे विचार के अनुसार तो केवल तीन पर सैन्ट लड़कियां ही पढ़ती हैं और यह तादाद भी उन पंजाबियों की लड़कियों को मिलाकर है । यदि उनको निकाल दिया जाये तो गांवों की परसैन्टेज तो एक या निल के बराबर ही है मेरे हल्के में तरावडी एक ऐतिहासिक कस्बा है परन्तु वहां पर लड़कियों का अभी तक मिडल तक का ही स्कूल है इसलिए उस स्कूल को हायर सैकेन्डरी स्कूल बना दिया जायें । डिप्टी स्पीकर साहिबा आज हमारा देश आजाद है इन बच्चों की बेहबूदी के लिए कुछ न कुछ अवश्य किया जाना चाहिए ।

इन्हीं बच्चों ने देश के भविष्य को बनाना है ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा मेरे हल्के में गरीब आदमियों की तादाद करीब चालीस फीसदी है ' । आज तक उनसे केवल वोट लिये जाते हैं लेकिन उनकी बेहबूदी के लिए बहुत कम काम किये जाते हैं । यहां पर भी बहुत बार कहा जाता है कि हरिजनों के लिए 21 परसैन्ट रिजर्वेशन है परन्तु मेरे विचार से तो तीन परसैन्ट भी रिजर्वेशन नहीं है उन गरीबों को अपना पूरा हक भी नहीं मिलता है जिसके वे हकदार हैं । इसलिए यह उन के साथ बड़ी भारी ज्यादाती हो रही है । आज तक तो उन बेचारों के साथ सदियों से अन्याय होता रहा है अब तो देश आजाद है अब तो उनको ऊपर उठाया जाना चाहिए । पिछले वक्तों में में यदि कोई आदमी किसी अछूत को पानी पिला रहा हो और उसको यह पता लग जाये कि

यह अच्छूत है तो उसकी बांस की नलकी से पानी पिलाया जाता था । अब डिप्टी स्पीकर साहिबा इस प्रकार का व्यवहार न किया जाये और उनको ऊंचा उठाया जाये ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा यहां पर सड़कों का जिक्र आया । सरकार सड़कें बनाती है परन्तु वह सड़कें बनाने में पैसे का सही ढंग से प्रयोग नहीं करती । जिस सड़क पर सरकार साठ हजार रुपया खर्च करके बनाती है वही सड़क उस से कम दामों में तैयार हो सकती है । इसलिए इस पैसे को जाया होने से बचाया जाये । एक किसान जिस मकान को बीस हजार रुपये में बनाता है सरकार उसी मकान को पचास हजार रुपये में बनाती है । सरकार ने यहां पर कितना बड़ा बजट पढ़ा है इतने करोड़ों रुपये का बजट है हमें तो उसकी गिनती भी नहीं आती है । सरकार को इस पैसे से काफी काम करने हैं परन्तु फिर भी इससे अधिक काम हो सकता है जितना कि सरकार ने करना है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, हर मिनिस्टर का यह फर्ज है कि चाहे वह किसी भी डिपार्टमेंट का हो वह स्वयं चौक करे कि किस जगह पर क्या हेरा-फेरी होती है । हमारे यहां यह जो इतने बड़े-बड़े थर्मल प्लांट लग रहे हैं व्यास प्रोजैक्ट है उनको खुद जा कर चौक करें दूसरे हमारा यह को-ओपरेटिव डिपार्टमेंट है । इसके मिनिस्टर बड़े नौजवान और योग्य हैं । उनको इस महकमें में जो भी खामियां हों उनको स्वयं जा कर मौके पर चौक करना चाहिए । डिप्टी स्पीकर साहिब आज वह समय आ गया है जब कि हरेक आदमी हर चीज के विषय में

समझता है । अब उतने अनपढ़ लोग नहीं हैं जितने कि पहले थे । आज जब हम इलैक्शन का रिजल्ट सुनते हैं तो उससे पता चलता है कि आज प्रजातंत्र एक प्रकार डगमगा रहा है । क्योंकि अब अनपढ़ आदमी समझ गया है जब वह किसी सरकारी कर्मचारी के पास अपने काम के लिए जाता है तो सरकारी आदमी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं और उन बेचारों को ठीक प्रकार से गाइड नहीं करते हैं । जान-बूझ कर डिले करते हैं । सरकारी कर्मचारी आजकल ज्यादाती करते हैं । इसलिए इस ट्रेंड को आज बदलने की आवश्यकता है । डिप्टी स्पीकर साहिबा आजकल अधिकतर लोग अपने स्वार्थ के कारण एक पार्टी को छोड़ कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं । वे लोग जनता की भलाई के लिए पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए पार्टी को छोड़ रहे हैं । डिप्टी स्पीकर साहिबा, साहिबा चाहे कोई सरकारी कर्मचारी है या कोई एम. एल. ए. है जो भी है, अगर वह जनता की सेवा करेगा तो वह आज आगे आ सकता है वरना आगे नहीं बढ़ सकता । आज जब मैं और श्री देवी लाल जी पंजाब के इलैक्शन का रिजल्ट सुन रहे थे तो देवी लाल जी कह रहे थे कि जो जनता की सेवा करेगा वही इलैक्शन में जीतेगा । जितने भी ये लोग इलैक्शन में असफल हुए हैं ये स्वार्थी लोग हैं, और इन्होंने जनता की सेवा नहीं की है । इसलिए जो जनता की मज्जी के खिलाफ चलेगा उसको जनता बिछल सहयोग नहीं देगी । डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज समय बदल चुका है जो लोग हजारों बीघे के मालिक होते

थे आज वह 30 स्टेन्डर्ड एकड़ के मालिक हैं । इसलिए अब समय बदल चुका है उनको समय के अनुसार चलना ही पड़ेगा ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक बहुत जरूरी बात है कि आज जितने भी पढ़े-लिखे लोग हैं वे सत्ता को हथियाये बैठे हैं हर चीज की जिम्मेदारी उनके ऊपर है । अगर कोई व्यवस्था की कमी है तो उनके कारण ही है, अगर कोई जनता की तकलीफ है तो उन लोगों के कारण है । इस लिए उनको अपने कर्तव्य की ओर देखना है । आज देश के अन्दर किसी भी चीज की कमी नहीं है हर चीज का आसानी से प्रबन्ध हो सकता है ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, एजुकेशन के जितने बड़े बड़े स्कूल हैं उनमें बड़े बड़े अफसरों के लड़के ही पढ़ते हैं गरीबों के लिए वहां कोई स्थान नहीं है । जैसा कि आपको मासूम है कि जितने भी ये बड़े बड़े अफसर आई. ए. एस. या आई. एफ. एस. बनते हैं ये सब बड़े अफसरों के लड़के ही बनते हैं । उसका कारण यही है कि उन को ही सब सुविधायें मिलता हैं गरीब के बच्चों को कोई इस प्रकार की सुविधा नहीं मिलती, जिसके कारण वे आगे नहीं बढ़ सकते । गरीबों के लिए तो वही नीति अपनायी जा रही है जैसा कि मैकाले की पालिसी थी कि हिन्दुस्तानियों को केवल कर्ल्क बनाना है, हिन्दुस्तान में तो हमने केवल कर्ल्क पैदा करने है । इसी प्रकार से इन गरीबों के साथ व्यवहार हो रहा हूँ, ताकि ये आगे न बढ़ जायें । उन बड़े बड़े अफसरों की यह अपनी पालिटिक्स है । वे ही सारी पार्लियामेंट को चलाते हैं, सारे शासन



को चलाते हैं । यदि आज चीनी की कमी है तो वह एक आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए है, दूसरों के पास तो कमी होती ही नहीं । जब उनको यह पता लगता है कि कमी होने जा रही है तो पहले ही अपने घर पर दो बोरियों का प्रबन्ध कर लेते हैं । डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं तो मंत्री कहूंगा कि आज आफिशल और नान-आफिशल दोनों की ही जिम्मेदारी है ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा आज हमारे देश को आजाद हुए 20 साल हो गये हैं परन्तु प्रजातंत्र को बदनाम किया जा रहा है इसको वही लोग आज बदनाम कर रहे हैं जो सदियों से हुकूमत करते आ रहे थे । हमारे सामने आज सारी की सारी चीजें साक्षात् नजर आ रही हैं । जिनका हम कभी स्वप्न में भी खयाल नहीं करते थे वह आज अपने सामने दिखती हैं । मैं तो ऐसे परिवार में पला था कि जहां पर न तो पक्का मकान था, पहिनने को सिर्फ इतना ही कपड़ा था कि दूसरा धोने को नहीं था । जब कभी कही शादी हो या बाहर जाना हो तो कपड़ा नया मित्रता था । लेकिन आज यहां देखता हूं कि पक्के मकानों की और लोगों के कपड़े पहिनने की इस कदर भरमार है कि जैसे लोगों को कहीं कोई कमी ही नहीं है । लाखों लाखों रुपयों के मकान खड़े हैं और सैकड़ों जोड़े कपड़ों के भरे पड़े हैं । फिर भी लोगों को संतोष नहीं है । जब से आजादी आई है, तब से आदमी हर दिशा में आजाद हो गया है । पहले तो कहीं कोई झगड़ा होता था तो हद से हद थानेदार तक शिकायत जाती थी, मगर आज कल तो हर एक आदमी यह कहता

है कि मैं चण्डीगढ जाता हूँ और मिनिस्टर के पास मिल के आता हूँ ।

पहले अपने बुजुर्गों की गलतियां देख कर लोग यह कहते थे कि हमारी दशा खराब इसलिए हुई है कि उन्होंने गलतियां की है, इसलिए अब दशा सुधारने के लिए हमें गलतियां नहीं करनी चाहिए । मगर आज कल भी अगर हम गलतियां करते रहे तो आगे आने वाली नस्लें कैसे शिक्षा ग्रहण करेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे । इसलिए हमें इतना सोचना चाहिए कि केवल हम ही रोटी न खाते रहें और दावतें उड़ाते रहें, बल्कि लोगों के लिए जिनको भर पेट खाना नहीं मिलता । पहिनने को कपड़ा नहीं मिलता, रहते हैं कच्ची झोपड़ियों में और कोई कोई तो घर के बिना ही है, उनको भी सब चीजें नसीब हों इस तरह काम करना चाहिए । बस जी आपका बड़ा धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

**लाला किशोरी लाल (कालका ) :** बहिन ओम प्रभा जी ने जो बजट पेश किया है उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ । लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जिला अम्बाला के लिए बहुत थोड़े पैसे रखे हैं जब कि यह सब को पता है कि इसकी तरक्की के लिए ज्यादा रुपया रखा जाना चाहिए क्योंकि यह जिला सबसे पिछड़ा हुआ है । पहले जब पंजाब में था यह जिला, तौ उस वक्त सिर्फ हिसार में डिवैल्पमेंट होती थी, लेकिन अब जब हरियाणा में आ गया है तो भी डिवैल्पमेंट रोहतक मे होती है । जिला अम्बाला में कालका जो मेरी कंस्टीच्यूएँसी हूँ वह बहुत पिछड़ी हुई है । बहां

पर सिर्फ दो हाई स्कूल हैं जब कि डेढ़ लाख के करीब आबादी हैं—

**उपाध्यक्षा :** वह गवर्नमेंट के हैं या कि प्राइवेट हैं?

**लाला किशोरी लाल :** वह गवर्नमेंट के हैं और यह तो स्कूल की बात रही । कालका की आबादी तो इतनी बड़ी है मगर वहां पर कोई कालेज नहीं है । इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि वहां पर कालेज बनाया जाए ।

इसके इलावा मोरनी हिल्ज एक इलाका मेरी कंस्ट्रिक्च्युएन्सी में है, जो काफी ऊंचाई पर है । वैसे हरियाणा में कोई हिल स्टेशन तो है नहीं । इसलिए अगर इस मोरनी हिल्ज को सड़कों के जरिए मैदान से मिला दिया जाए तो यह बहुत अच्छा हिल रिजार्ट बन सकता है । हमारे यहां 10-12 साल में कोई सड़क नहीं बनी । मुझे पता नहीं कि इस कंस्ट्रिक्च्युएन्सी को क्यों पीछे रखा गया है । ड्रिंकिंग वाटर की यहां पर बहुत कमी है । 350 गांवों में ड्रिंकिंग वाटर का कोई इंतजाम नहीं है । कालका में, सूरजपुर में, अम्बाला में, रायपुर रानी में कहीं भी पीने के पानी का इंतजाम नहीं है । लोग आजादी मिलने के बाद भी जोहड़ों का पानी पीते हैं' जा अफसोस की बात है पीने के पानी का इंतजाम होना इंसान के लिए बहुत जरूरी चीज है । हर जगह ट्यूब-वैल्ज लग रहे हैं लेकिन जिला अम्बाले में जो कालका है वहां सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया है । यहां पर ट्यूब-वैल्ज जरूर लगाए जाएं ।

यहां पर इंडस्ट्री भी कोई नहीं है, इसलिए वहां पर इंडस्ट्रीत लगाई जाए ।

**वित्त मन्त्री :** डिप्टी स्पीकर साहिबा, रस्मी तौर पर मुझे आज जवाब देना चाहिए था मगर चूंकि अब टाइम नहीं है इसलिए कर डिमांड्ज के वाद जवाब देने का वक्त दे दिया जगर ।

**उपाध्यक्षा :** अच्छी बात । अब सभा की बैठक कल, बुधवार, दिनांक 12 फरवरी 1969, 10 बजे सुबह तक के लिए स्थगित होती है ।

(इसके बाद सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 12 फरवरी, 1969, 10 बजे सुबह तक के लिए स्थगित हुई )